R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2024-25

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

वर्ष : 22 । अंक : 14
16 से 30 अप्रैल 2024
पृष्ठ : 48
मूल्य : 25 रु.

मिशन 2024 का घमासान

भ्रष्टाचार बनाम... सियासी अत्याचार!

मोदी बनाम मुद्दों पर सिमटता जा रहा है लोकसभा चुनाव

मोदी की गारंटी बनाम राहुल की न्याय गारंटी की परीक्षा

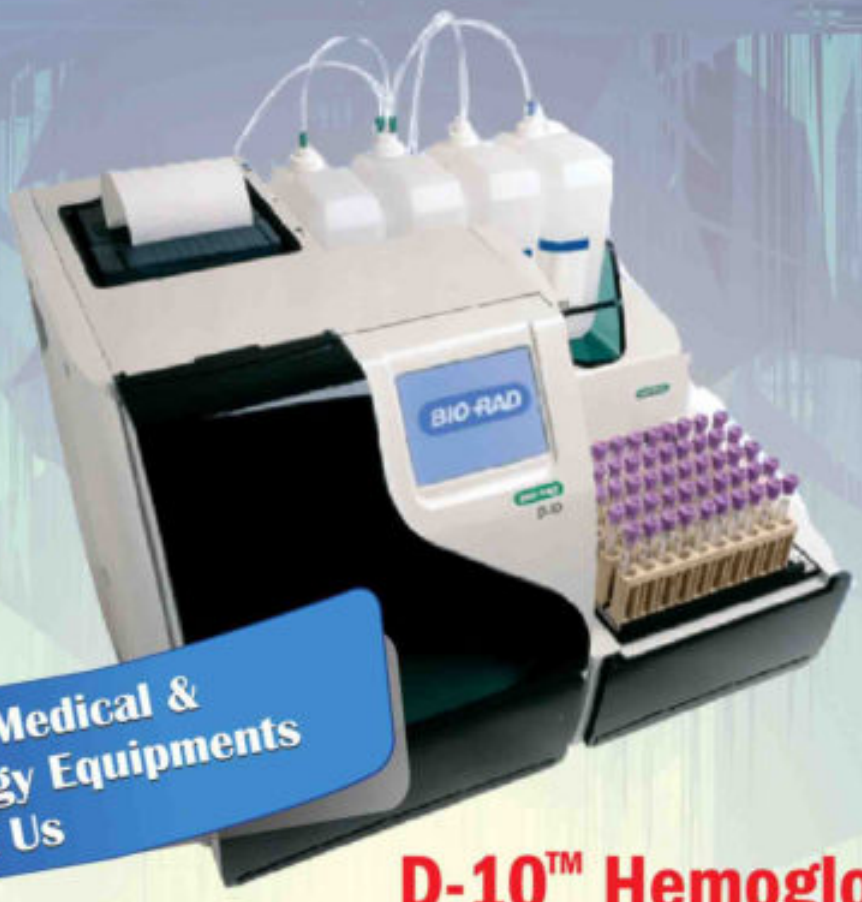

For Any Medical & Pathology Equipments Contact Us

D-10™ Hemoglobin Testing System

For HbA_{1c}, HbA_2 and HbF

Flexible
to solve more testing needs

Comprehensive
B-thalassemia and diabetes testing

Easy
for simple operation

Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; It's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.

A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA_{1c} or $HbA_2/F/A_{1c}$ testing using pripary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps, With the D-10™ System, It's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress-and that can be the difference for the people who count on you most.

SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.

C-65, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbple@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687

इस अंक में

प्रशासनिक

8 | पूर्व मुख्य सचिवों पर भ्रष्टाचार...

मप्र में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर डॉ. मोहन यादव सरकार ने मार्च में एक और बड़ा निर्णय लेते हुए सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय अधिकारियों और सेवानिवृत्त हो चुके अधिकारियों के खिलाफ जांच...

राजपथ

10-11 | नए नेतृत्व की अग्निपरीक्षा

विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद भाजपा लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतने का दम भर रही है। वहीं कांग्रेस दर्जनभर सीटों पर जीत का दावा कर रही है। जनता किसका साथ देती है यह तो 4 जून...

आर्थिकी

13 | खर्च की लिमिट तय

नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही वित्त विभाग ने विभागों के खर्च की लिमिट तय कर दी है। अब योजनाओं के भुगतान पर वित्त विभाग की परमिशन अनिवार्य है। अब अगले 4 महीनों में 43 विभागों की कुल 102 योजनाओं पर फाइनेंस की परमिशन...

राजकाज

15 | छिंदवाड़ा बना साख

भाजपा ने मप्र की सभी 29 लोकसभा सीटें जीतने के लिए हर सीट के हिसाब से चुनावी जमावट कर ली है। छिंदवाड़ा में भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने डेरा डालकर कमलनाथ के विश्वस्त कांग्रेसी नेताओं को अपने पाले में लाने की मुहिम चला रखी है। यह इंगित करता है कि इस बार...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

तारीखों के ऐलान के साथ ही अब लोकसभा का समर और गरमा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार और उनकी पार्टी भाजपा भ्रष्टाचार पर और वार के लिए 'मोदी सरकार तीसरी बार' का नारा बुलंद कर रही है। वहीं कांग्रेस समर्थित इंडिया गठबंधन मोदी सरकार के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान (ईडी, सीबीआई और आईटी के छापों) को सियासी अत्याचार बताकर जनता से सरकार बदलने की गुहार लगा रही है। एक तरफ भाजपा का दावा है कि मोदी सरकार ने 'अमृतकाल' में...

राजनीति

30-31 | परिवारवाद से विस्तारवाद

यदि किसी परिवार में एक से अधिक लोग जनसमर्थन से अपने बलबूते पर राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो उसे हम परिवारवाद नहीं कहते हैं। हम परिवारवाद उसे कहते हैं जो पार्टी परिवार चलाता है। पार्टी के सारे निर्णय परिवार के लोग करते हैं वो परिवारवाद है। प्रधानमंत्री...

महाराष्ट्र

35 | सीट बंटवारे की फांस...

पिछले लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में दो गठबंधन थे, एनडीए और यूपीए। एनडीए में भाजपा ने 25 और शिवसेना ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था। दूसरी तरफ यूपीए में कांग्रेस ने 26 और एनसीपी ने 22 सीटों पर चुनाव लड़ा था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना एनडीए छोड़कर...

बिहार

38 | भ्रष्टाचार, जंगलराज...

लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों के ऐलान से पहले बिहार में परिवारवाद का मुद्दा खूब हावी रहा। एनडीए सबसे आक्रामक रही। हालांकि, अब उसके ही नेता चुप्पी साध लिए हैं। मौका तेजस्वी यादव के हाथ लगा और चुनाव प्रचार के दौरान वे एनडीए...

6-7 अंदर की बात
41 महिला जगत
42 अध्यात्म
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

अपनी बात

आचार संहिता...अफसरों की मौजा ही मौजा

किसी शायर ने क्या खूब लिखा है...

लफ्ज़ों पर बंदिशें हैं तो तू ये इलाज कर,
आचार संहिता लगी है तो ईशारों में बात कर!

वैसे तो उपरोक्त पंक्तियां राजनीतिक पार्टियों और नेताओं के लिए कही गई हैं, लेकिन इन्हें आचार संहिता के दौरान शासकीय गतिविधियों में अमल लाया जा सकता है। यानी आचार संहिता के दौर में भी विकास और जनता की जरूरतों से संबंधित कार्य किए जा सकते हैं। बशर्ते कि अफसरों में अपने पद की गरिमा का अहसास हो। लेकिन 18वीं लोकसभा के चुनाव की जबसे आचार संहिता लगी है, मप्र के अफसरों की मौजा ही मौजा हो गई है। राज्य मंत्रालय हो या अन्य दफ्तर वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ अफसर अपने दफ्तर तो आते हैं, लेकिन खानापूर्ति कर वे कब चले जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। दरअसल, प्रशासनिक मुखिया यानी मुख्य सचिव की कार्यप्रणाली ही ऐसी है कि सालभर अफसरों और कर्मचारियों की धमक से जागृत रहने वाले मंत्रालय में सन्नाटा पसरा हुआ है। इसकी वजह यह है कि प्रशासनिक मुखिया ने आचार संहिता के दौरान कामकाज की कोई कार्ययोजना ही नहीं बनाई। इस कारण आचार संहिता लगने के बाद अफसरों के पास कोई काम है ही नहीं। वे दफ्तर तो आते हैं, लेकिन काम नहीं होने के कारण गपशप में जुट जाते हैं। वे दफ्तर में बैठकर कितना गपशप करें? ऐसे में वे भी अपना बोरिया-बिस्तर समेटकर घर चले जाते हैं। यह केवल अफसर ही नहीं बल्कि मुख्य सचिव की भी दैनिक क्रिया बन गई है। वे भी कुछ देर के लिए मंत्रालय में मुंह दिखाई के लिए आती हैं और थोड़ी देर बाद चली जाती हैं। उनके जाते ही बाकी लोग भी पलायन कर जाते हैं। जबकि पूर्व में यह देखा गया है कि जब भी आचार संहिता लगने का समय आता था, प्रशासनिक मुखिया अफसरों के साथ बैठक कर आचार संहिता के दौरान किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा बनाते थे। फिर जैसे ही आचार संहिता लगती थी, अफसरों को होमवर्क थमा दिया जाता था। इसका असर यह देखने को मिलता था कि अफसर समय पर मंत्रालय या अपने दफ्तर पहुंचते थे और शाम तक अपना कामकाज निपटाने में व्यस्त रहते थे। हैरानी तो इस बात की है कि वर्तमान मुख्य सचिव पर विश्वास करते हुए सरकार ने उनके कार्यकाल में 6 महीने की वृद्धि करवा दी है, ताकि चुनाव के दौरान विकास के कार्य प्रभावित न हों। लेकिन विडंबना यह है कि मुख्य सचिव ने आचार संहिता के दौरान किए जाने वाले कार्यों के लिए कोई प्लानिंग की ही नहीं। इसका परिणाम यह हो गया है कि सरकारी दफ्तरों में कामकाज की बजाय चुनावी चर्चा की महफिलें सज रही हैं। प्रशासनिक अधिकारी ही नहीं बल्कि आमजन भी इस बात को भलीभांति जानते हैं कि लंबी चुनावी प्रक्रिया खर्चीली ही नहीं, उबाऊ भी होती है और आचार संहिता के चलते बहुत से सरकारी काम ठप हो जाते हैं। ऐसे में प्रशासनिक मुखिया का कर्त्तव्य होता है कि वह वर्तमान स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए अफसरों के साथ मिल-बैठकर आचार संहिता के दौरान किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा तैयार करवा लेता है। ताकि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद भी आमजन के कामकाज न रुकें और विकास के काम भी ठप न हों। मप्र में पूर्ववर्ती मुख्य सचिवों द्वारा ऐसा ही किया जाता रहा है, लेकिन वर्तमान समय में हालात इनके बिलकुल उलटे हैं। अब यह प्रशासनिक मुखिया की अनुभवहीनता है या निष्क्रियता यह तो वही जानें, लेकिन इससे सरकारी मशीनरी पूरी तरह ठप पड़ी है।

- राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 22, अंक 14, पृष्ठ-48, 16 से 30 अप्रैल, 2024

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

ब्यूरो
कोलकाता:- इंद्रकुमार, **छत्तीसगढ़:**- संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी,
जयपुर:- आर.के. बिन्नानी, **लखनऊ :**- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
089823 27267, (रतलाम) सुभाष सोमानी
075666 71111, (विदिशा) मोहित बंसल

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी
फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान)
मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर,
फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर,
भिलाई, मोबाइल 094241 08015
इंदौर : नवीन रघुवंशी, रघुवंशी कॉलोनी, इंदौर,
मो.-9827227000
देवास : जय सिंह, देवास
मो.-7000526104, 9907353976

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र–संपादक के नाम

akshnews.com

ठोस कदम उठाएं...

2050 तक दुनियाभर की आबादी लगभग 10 अरब तक पहुंचने का पूर्वानुमान है और अनुमान है कि इस बढ़ी हुई आबादी को खिलाने के लिए 50 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि की आवश्यकता होगी। सरकार को इस बारे में सोच-विचार करना चाहिए और ठोस कदम उठाने चाहिए।

● **सुरभि दीक्षित,** इटारसी (म.प्र.)

स्वास्थ्य का ध्यान रखें...

महामारियों ने करोड़ों इंसानों को मारा है। वजह वायरस, पैथोजेन और बैक्टीरिया रहे हैं। जूनोसिस यानी जानवरों से इंसानों में आने वाली बीमारियों को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है। इंसानों में मौजूद वायरसों की वजह कहीं न कहीं जानवर ही हैं। लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए।

● **प्रवीण वर्मा,** सागर (म.प्र.)

नदियों का हाल बेहाल...

अगर यह कहा जाए कि सरकारी लापरवाही से प्रदेश की नदियां दम तोड़ रही हैं, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। राज्य को अमृत देने वाली मां नर्मदा और क्षिप्रा को जिम्मेदार ही मैली कर रहे हैं। नर्मदा और क्षिप्रा के किनारे बसे शहरों के नालों से गंदा पानी नदियों में डाला जा रहा है।

● **गौरव जैन,** मक्सी (म.प्र.)

राजनीतिक दलों की तीखी टिप्पणियां

लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं राजनीतिक दलों में वाद-विवाद की स्थिति भी देखने को मिल रही है। सभी दल एक-दूसरे पर टिप्पणियां करने से नहीं चूक रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति का दावा करती है, लेकिन चुनावी चंदे में हुई हेरा-फेरी को लेकर खुद दबे पांव बच निकलने की कोशिश भी करती है। शराब घोटाले में जांच एजेंसियों को पहले से पता था कि घोटाले में केजरीवाल की संलिप्तता है तो उन्हें पहले ही क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया क्योंकि तीसरे समन के बाद गिरफ्तार करने का अधिकार प्रवर्तन निदेशालय के पास था। फिर दो साल तक इंतजार करने के पीछे की मंशा क्या थी।

● **मुकेश मोटवानी,** भोपाल (म.प्र.)

प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त हो

मप्र में कई आईएएस अफसर ऐसे हैं जो कई बार कलेक्टरी का सुख प्राप्त कर चुके हैं, वहीं कई अफसर ऐसे हैं जिन्हें अभी तक कलेक्टरी ही नहीं मिली है। साथ ही कुछ ऐसे अफसर भी हैं जो बिना कलेक्टर बने रिटायर हो चुके हैं। ऐसे अफसरों की संख्या एक दर्जन तक पहुंच चुकी है। कहा तो यह भी जा रहा है कि अगले दो सालों में यह संख्या दर्जनों में हो जाएगी। इसके उलट कई अफसर ऐसे हैं जो लगातार मैदानी पदस्थापना पा रहे हैं। सरकार को नए युवाओं को आगे लाकर प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त करनी चाहिए।

● **शमीम खान,** इंदौर (म.प्र.)

मजदूरों की सोचे सरकार

प्रदेश में मनरेगा योजना का हाल सही नहीं है। दरअसल इस स्थिति की वजह है केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के हिस्से की राशि का भुगतान नहीं किया जाना। प्रदेश के मजदूरों को बामुश्किल काम मिला, तो अब उनकी मजदूरी अटक गई है। त्यौहारी और शादी ब्याह के सीजन में भी उन्हें मजबूरी का भुगतान नहीं किया गया, जिसकी वजह से गरीबों के सामने गहरा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। सरकार को मजदूरों के बारे में सोचना चाहिए।

● **प्रफुल मिश्रा,** रीवा (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

फिर मोदी परिवार से जुड़ा पारस

बिहार में एनडीए के बाद महागठबंधन में भी लोकसभा सीटों के बंटवारे के साथ ही पशुपति पारस का आरजेडी से गठबंधन नहीं हो पाया। इससे पहले एनडीए में भी पारस को जगह नहीं मिली थी। ऐसे में रालोजपा के अकेले चुनावी मैदान में उतरने की अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन पारस एक बार फिर से एनडीए में होकर मोदी का परिवार बन गए हैं। पारस ने एनडीए गठबंधन को अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के समर्थन की घोषणा की है। इसके बाद उनके अगले कदम पर अटकलबाजी बंद हो गई है। पारस ने कुछ दिन पहले ही उनकी पार्टी को लोकसभा चुनाव के लिए कोई सीट नहीं दिए जाने के खिलाफ इस्तीफा दे दिया था। उस वक्त पारस ने अपने एक्स से मोदी का परिवार भी हटा लिया था। अब फिर से पशुपति पारस मोदी के परिवार में शामिल हो गए। पारस ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि उनकी पार्टी (राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी) भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का अटूट हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके भी नेता हैं। उन्होंने कहा मोदी का फैसला सर्वोपरि है। एनडीए देशभर में 400 से ज्यादा सीटें जीतकर तीसरी बार अपनी सरकार बनाएगा। पशुपति पारस के इस कदम से सवाल उठ रहा है कि जो पशुपति पारस नाराज होकर एनडीए छोड़कर चले गए थे, अचानक उनका मन क्यों बदल गया?

क्या अब ममता की बारी है?

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद भाजपा के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष ने कहा कि जो इस समय दिल्ली में हो रहा है वैसा ही दृश्य बंगाल में भी दिख सकता है। उनके इस बयान को लेकर तरह-तरह के सवाल उठने लगे हैं। पूछा जा रहा है कि क्या बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या अन्य नेताओं के खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई हो सकती है, जिसे विपक्ष राजनीतिक विद्वेष और लोकतंत्र की हत्या बता रहा है। असल में भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में भी राष्ट्रीय राजधानी जैसा दृश्य दिखाई दे सकता है। बकौल मजूमदार पिछले महीने, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। यह दिखाता है कि यदि आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो मुख्यमंत्री होने से आपको किसी तरह की छूट नहीं मिल जाती। पश्चिम बंगाल में भी पिछले कुछ सालों में भ्रष्टाचार के इस तरह के आरोप सामने आए हैं। तृणमूल कांग्रेस भी आप की तरह ही भ्रष्ट है और इसलिए उन्हें भी अपने शीर्ष नेताओं की इसी तरह गिरफ्तारी का डर है।

भाजपा को नुकसान पहुंचा सकते हैं सहयोगी

भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पंजाब प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि पार्टी शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। इससे पहले दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन के कयास लगाए जा रहे थे। ऐसे में माना जा रहा है कि चुनाव के पहले एनडीए से गठबंधन तोड़ने वाले दल भाजपा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन सभी दलों का अपने-अपने राज्य में काफी वर्चस्व है और अपना बड़ा वोटबैंक भी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या भाजपा इन दलों का वोट बैंक अपने पाले में ला पाएगी? पंजाब में अकाली दल एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में अकाली दल और भाजपा ने मिलकर चुनाव लड़ा, हालांकि दोनों ही दलों के खाते में दो-दो सीटें आई थीं। इस चुनाव में अकाली दल को 27 फीसदी से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि भाजपा को 10 फीसदी से भी कम वोट मिले थे। इसी तरह हरियाणा में जेजेपी की जाट वोटर्स पर मजबूत पकड़ है, जहां 25 फीसदी जाट वोट हैं। यहां भी भाजपा ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की है। कहा जा रहा है कि भाजपा ने जाटव वोटबैंक में सेंध लगाने के लिए जेजेपी से गठबंधन खत्म किया है, क्योंकि पिछली बार यह वोट कांग्रेस के पाले में ज्यादा गया था।

आनंद ने उतारा नीतीश का कर्ज!

आम चुनाव से ठीक पहले बिहार में राजद को बड़ा झटका लगा। पूर्व सांसद लवली आनंद अपने समर्थकों के साथ राजद को छोड़कर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में शामिल हो गई हैं। जदयू के प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक समारोह में पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने लवली आनंद को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर ललन सिंह ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि समता पार्टी के गठन के समय भी ये हम लोगों के साथ थीं और अब फिर से अच्छी जगह आ गई हैं। कहा जा रहा है कि लवली आनंद ने जदयू में शामिल होकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उन अहसानों का कर्ज उतार दिया है जो नीतीश ने उनके पति आनंद मोहन पर किए थे। जदयू की सदस्यता ग्रहण करने के बाद लवली ने कहा कि पार्टी उन्हें जो जिम्मेदारी देगी, उसे पूरी ईमानदारी से निभाएंगी। इसके बाद से संभावना जताई जा रही है कि जदयू लवली को शिवहर से उम्मीदवार बना सकती है। इससे पहले बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद राजद विधायक चेतन आनंद विश्वासमत के दौरान पाला बदलकर एनडीए के खेमे में चले गए थे।

मोदी सुनामी क्षत्रपों से फुस्स!

महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे (ठाकरे पार्टी को 21, कांग्रेस 17, शरद पवार पार्टी 10 सीट) ने महाराष्ट्र की जनता की निगाह में उद्धव ठाकरे बनाम नरेंद्र मोदी की सीधी प्रतिद्वंद्विता बना दी है। इसका अर्थ है लोगों में, समर्थकों में एकनाथ शिंदे और अजित पवार की वोट दुकान खत्म। इनकी वही दशा होनी है जो बिहार में भाजपा के पार्टनर नीतीश, मांझी, पासवान आदि की होनी है। इन दिनों अपने वेंकटेश केसरी औरंगाबाद, मराठवाड़ा में घूम रहे हैं। उनकी मानें तो उद्धव ठाकरे मेहनत कर रहे हैं। खूब सभाएं कर रहे हैं। वही भाजपा ने अपने ही हाथों एकनाथ शिंदे और अजित पवार का बोरिया बिस्तर बंधवा दिया है। इसलिए 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में मोदी बनाम उद्धव ठाकरे में पचास-पचास फीसदी जीत-हार हो तो वह भाजपा-एनडीए को झटका होगा। मतलब उन सभी राज्यों में नरेंद्र मोदी की कथित सुनामी याकि अबकी बार 400 पार सीटों का आंकड़ा बुरी तरह फेल होना है, जहां अभी तक मोदी ने सर्वाधिक रैलियां की हैं।

सोशल मीडिया पर छाने की लत

प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की चर्चा लोग चटखारे लेकर कर रहे हैं। दरअसल, साहब को सोशल मीडिया पर छाए रहने की लत कुछ इस कदर लग गई है कि वे वीडियो बनाने का कोई भी मौका नहीं चूकते हैं। साहब पुलिस विभाग में सबसे फिट अफसरों में शुमार हैं। वर्तमान समय में साहब विंध्य क्षेत्र में एडीजी के पद पर पदस्थ हैं। 1992 बैच के ये आईपीएस अधिकारी इन दिनों अपने जोन में मतदाताओं को जागरूक करने के अभियान में जुटे हुए हैं। इसी से जुड़ा उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साहब मतदान करने की अपील करते घूम रहे हैं। इस संदर्भ में चर्चा है कि साहब ने पूरे सिस्टम को हाईजैक कर रखा है। एसपी, डीआईजी को तो छोड़िए, उन्होंने कमिश्नर और कलेक्टर को भी अपने मायाजाल में फंसा लिया है। साहब पर खुमारी कुछ इस कदर छाई हुई है कि वे 24 घंटे कैमरामेन को लेकर घूमते हैं। जहां भी लोगों की भीड़ देखते हैं, वहां ज्ञान बखारने लगते हैं। यही नहीं बकायदा इसकी रिकॉर्डिंग करवाते हैं और फोटो खराब होने या रिकॉर्डिंग ठीक से नहीं होने पर वे कई बार रीटेक भी करवाते हैं। गौरतलब है कि पूर्व में उक्त सीनियर आईपीएस अधिकारी के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर छाया हुआ था। मकर संक्रांति पर साहब पतंग उड़ाते हुए शिव शंभू गाने पर डांस करते दिखे थे।

हाथी के दांत दिखाने के और, खाने के और...

प्रदेश में वर्तमान सरकार का सबसे अधिक जोर सुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर है। लेकिन स्थिति हाथी के दांत दिखाने के और, खाने के और वाली है। इसका ताजा मामला गृह विभाग में आर्म्स लाइसेंस की नई प्रक्रिया में सामने आया है। सूत्रों का कहना है कि दिखावे के लिए सरकार ने आर्म्स लाइसेंस देने के लिए 4 कैटेगिरी बना दी है। पहली कैटेगिरी में सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक आदि, दूसरी कैटेगिरी में आईएएस-आईपीएस, तीसरी कैटेगिरी में रिटायर्ड आईएएस-आईपीएस और चौथी कैटेगिरी में राज्यपाल, पूर्व राज्यपाल व अन्य। लेकिन कहा जा रहा है कि आर्म्स लाइसेंस देने की ये कैटेगिरी केवल दिखावा मात्र है। यानी आर्म्स लाइसेंस लेने वाला जिस भी माध्यम से आए उसे लाइसेंस देना है या नहीं यह तो उसकी हैसियत से ही तय होगा। यानी जिसको लाइसेंस देना है, उसे उसकी हैसियत यानी पैसा, पावर और पॉलिटिकल अप्रोच के आधार पर अनुशंसा कर दी जाएगी। और जिसे नहीं देना है, उसके आवेदन में कोई न कोई पेंच फंसाकर लौटा दिया जाएगा। गौरतलब है कि पूर्ववर्ती सरकार में आर्म्स लाइसेंस के नाम पर जमकर कमाई की गई थी। इस बार फॉर्मूला भले ही बदला है, लेकिन टारगेट लगभग वही है।

पांचवी मंजिल पर मची धमाचौकड़ी

प्रदेश में मंत्रालय की पांचवी मंजिल का पावर सबको पता है। प्रदेश के प्रशासनिक फैसले इसी मंजिल से किए जाते हैं। यानी इस मंजिल पर जो अफसर पदस्थ रहता है, वह अपने आप काफी पावरफुल हो जाता है। लेकिन इन दिनों मंत्रालय की पांचवी मंजिल अफसरों के बीच मची खींचतान और वर्चस्व की लड़ाई के लिए चर्चा में है। सूत्रों का कहना है कि पांचवी मंजिल पर बैठने वाले अफसरों में एक-दूसरे की टांग खींचने की होड़ लगी हुई है। इनके पास एक-दूसरे की बुराई करने के अलावा कोई काम नहीं रहता है। हालांकि सभी अपने आपको काम के बोझ तले दबा बताते हैं। यही नहीं एक अफसर दूसरे अफसर की कार्यप्रणाली को संदेह से देखता है। इस कारण अफसरों में सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। इसका असर यह हो रहा है कि प्रशासनिक मशीनरी का कामकाज पटरी पर नहीं आ पा रहा है। सूत्रों का कहना है कि पांचवी मंजिल पर इस तरह की धमाचौकड़ी मची हुई है कि प्रशासनिक मुखिया भी दरकिनार हैं। नियमत: कोई भी फाइल प्रशासनिक मुखिया के माध्यम से ही आगे बढ़ेगी। लेकिन राजनीतिक संरक्षण और रसूख प्राप्त अफसरों ने वर्षों से चल रही प्रशासनिक प्रक्रिया को मनमाने ढंग से चलाना शुरू कर दिया है। इससे पांचवी मंजिल पर बैठने वाले अफसर कई धड़ों में बंट गए। इसका असर यह हो रहा है कि एक-दूसरे के कामकाज और उनकी फाइलों को लेकर नोंकझोंक और टोकाटोकी के मामले बढ़ गए हैं। इस अव्यवस्था से प्रशासनिक वीथिका के अन्य अफसर भी परेशानी का सामना कर रहे हैं।

बिन मुस्कान, ऊंची दुकान

किसी व्यक्ति को देखकर उसके व्यक्तित्व और उसके कृतित्व की पहचान नहीं की जा सकती है। ऐसे ही एक डिप्टी डायरेक्टर इन दिनों चर्चा में हैं। साहब गुमसुम और शांत स्वभाव के हैं, लेकिन उनके कारनामे उतने ही बड़े हैं। सूत्रों का कहना है कि आजकल साहब कहां कौनसा काम चालू कराना है, इसकी कंसल्टेंसी दे रहे हैं। कंसल्टेंसी ऐसी-वैसी नहीं, बल्कि रेत, मार्बल, ग्रेनाइट जैसे खनिज संपदा की। बताया जाता है कि साहब की कंसल्टेंसी का यह धंधा पूरे शबाब पर है। इससे साहब की लंबी-चौड़ी कमाई भी हो रही है। पता चला है कि महाकौशल क्षेत्र में साहब और उनके परिजन मिलकर एक दूध डेयरी भी चला रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि यह दूध डेयरी हाथी के दिखावे के दांत की तरह हो सकती है। क्योंकि साहब की कमाई बेहिसाब हो रही है। ऐसे में कोई उनकी कमाई पर नजर न लगा दे, शायद इसीलिए दूध डेयरी को पर्दे की तरह उपयोग किया जा रहा है। हालांकि साहब की काली कमाई करने की करतूत अब प्रशासनिक और राजनीतिक वीथिका में भी चर्चा का विषय बन गई है।

मैडम को मालदार का साथ

विवादों में रहने वाले जमीनों के नक्शे पास करने वाले एक विभाग की चर्चित ज्वाइंट डायरेक्टर इस समय राजधानी के एक मालदार व्यक्ति के माध्यम से काम कर रही हैं। बताया जाता है कि मैडम इन्हीं के माध्यम से बड़े-बड़े मामलों का निपटारा करती हैं। यहां बता दें कि मैडम ने जिस मालदार व्यक्ति को अपना राजदार बनाया है, उनका अतीत विवादों में रहा है। दरअसल, ये भाईसाहब अफसरों की काली कमाई का मैनेजमेंट संभालते हैं। इसी मैनेजमेंट के गुण के कारण इन्होंने एक आईएएस दंपत्ति के परिवार में अपनी धौंस जमा ली थी। आलम यह था कि उन्हें उक्त दंपत्ति का अघोषित दत्तकपुत्र भी कहा जाने लगा था। विगत दिनों जब रिटायरमेंट के बाद उक्त आईएएस अधिकारी का देहांत हुआ तो उनकी संपत्तियों को लेकर झगड़े शुरू हो गए। बताया जाता है कि उक्त भाईसाहब ने आईएएस दंपत्ति की कई संपत्तियों को अपने नाम करा लिया था। सूत्रों का कहना है कि भाईसाहब के चंगुल में कई नौकरशाह फंसे हुए हैं। ऐसे में वे मैडम के साथ कितने वफादार बने रहेंगे, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है।

पूर्व मुख्य सचिवों पर भ्रष्टाचार के दाग

मप्र में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर डॉ. मोहन यादव सरकार ने मार्च में एक और बड़ा निर्णय लेते हुए सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय अधिकारियों और सेवानिवृत्त हो चुके अधिकारियों के खिलाफ जांच पर जल्द निर्णय लेने के लिए कमेटी गठित की है। सामान्य प्रशासन विभाग के सूत्रों के अनुसार भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ मिली शिकायतों की जांच हो रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्रदेश के उन पूर्व प्रशासनिक मुखियाओं यानी पूर्व मुख्य सचिवों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी जिन पर भ्रष्टाचार के दाग लगे हैं।

गौरतलब है कि डॉ. मोहन यादव ने जबसे मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है उन्होंने भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की कोशिश शुरू कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग के सूत्रों के अनुसार हर विभाग में जितने भी अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं सभी की कुंडली बनाई जा रही है। इन सभी मामलों की जांच कर दागियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में प्रदेश के करीब आधा दर्जन पूर्व मुख्य सचिव भी चर्चा में हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ऐसे देखा जाए तो मप्र ही नहीं देश के कई राज्यों के पूर्व मुख्य सचिवों पर गंभीर आरोप लगे हैं। बीते साल सीएस नरेश कुमार और दिल्ली सरकार का विवाद चर्चित रहा। सीएस पर द्वारका एक्सप्रेस-वे में बेटे को 315 करोड़ का लाभ पहुंचाने का आरोप है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएस पर दुरुपयोग करने, भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग सहित कई मामलों में अनियमितता का आरोप लगा है। अमन ने जमानत याचिका लगाई तो हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। उत्तराखंड के पूर्व सीएस राकेश शर्मा पर राज्यसभा चुनाव में वोटों की खरीद-फरोख्त करने और करोड़ों का केस दर्ज हुआ था। ये भी देश का चर्चित केस रहा।

एक तरफ प्रदेश में भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी चल रही है, वहीं कई ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। लेकिन अभी तक किसी भी पूर्व मुख्य सचिव पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। नवंबर 2023 में सेवानिवृत्त हुए प्रदेश के पूर्व सीएस इकबाल सिंह बैंस घोटालों के आरोपों के कारण चर्चाओं में हैं। केवल इकबाल ही नहीं इससे पहले भी प्रदेश के कई पूर्व सीएस आरोपों में घिरे हैं, लेकिन किसी को दंड नहीं मिला। अगर कानून का डंडा चला भी, तो किसी ने अग्रिम जमानत ले ली, तो कोई कैट तक जाकर जांच पर ही स्टे ले आया। नौकरशाहों ने भी आरोपों से घिरे सीएस का साथ देकर जांच में खामियां निकाल दी, ताकि क्लीनिचिट की राह आसान हो जाए। नतीजा ये कि दागदार तो कई हैं, लेकिन दंडित कोई भी नहीं। गौरतलब है कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की आंच से सबसे ज्यादा सीएस पद घिरा रहा है। 2003 में जब दस साल की कांग्रेस सरकार को ध्वस्त करके भाजपा आई तो तत्कालीन सीएम उमा भारती ने तत्कालीन सीएस एवी सिंह को हटा दिया। ये मामला सुर्खियों में रहा। फिर नवंबर 2018 में जब कांग्रेस वापस सत्ता में आई तो बीपी सिंह को एक महीने का कार्यकाल पूरा करने दिया गया। उलटे बीपी का पुनर्वास किया। फिर एसआर मोहंती को सीएस बनाया। मोहंती की सेवानिवृत्ति पर, गोपाल रेड्डी को सीएस बनाया गया, लेकिन भाजपा जैसे ही सत्ता में आई, तो रेड्डी को महज 9 दिन में हटा दिया।

मप्र के कड़क और ईमानदार अफसरों में शुमार पूर्व सीएस इकबाल सिंह बैंस का नाम दो घोटालों में सामने आया है। पहला उज्जैन के देवास रोड पर दताना-मताना हवाई पट्टी की लीज व पार्किंग में आर्थिक गड़बड़ी का है। लोकायुक्त संगठन जांच कर रहा है। दूसरा आजीविका मिशन में भर्ती घोटाला है। वर्ष 2017-18 में हुई इन नियुक्तियों को फर्जी माना गया है। आईएएस नेहा मारव्या ने 2022 में जांच में गड़बड़ी को स्वीकारा था। इसमें भी इकबाल घिरे हैं। जानकारी के अनुसार ईओडब्ल्यू ने माना है कि ग्रामीण एवं पंचायत विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस के खिलाफ शिकायत मिली है। इसका परीक्षण भी कराया गया। इसमें पता चला कि इन अफसरों द्वारा किए गए विवादित कार्य या आदेश शासकीय पद पर रहते हुए जारी किए गए हैं। ऐसे में इनके खिलाफ जांच के लिए सामान्य प्रशासन विभाग की अनुमति जरूरी है। ईओडब्ल्यू की ओर से सामान्य प्रशासन के प्रमुख सचिव को पत्र लिखा गया है।

प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के ठीक पहले मार्च 2020 में महज 9 दिन सीएस रहने वाले गोपाल रेड्डी सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद आर्थिक अनियमितता के केस में घिर गए थे। दिसंबर 2020 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग में रेड्डी पर केस दर्ज किया था। इस पर रेड्डी ने तेलंगाना हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत ले ली, पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। मामला अप्रैल 2019 में ईओडब्ल्यू के ई-टेंडर घोटाले में केस दर्ज करने के बाद सामने आया था। हैदराबाद की मेसर्स मेंटोना कंपनी का मामले में नाम आने पर यह और बड़ा हो गया। कमलनाथ सरकार में जनवरी 2019 से मार्च 2020 तक सीएस रहे एसआर मोहंती के खिलाफ 719 करोड़ के उद्योग घोटाले में जांच का पेच बरसों रहा। एमपीआईडीसी में उद्योगों को करीब 719 करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाने के आरोप में मोहंती के खिलाफ जनवरी 2007 में जांच शुरू हुई थी। बाद में क्लीनचिट दे दी गई। मोहंती कमलनाथ सरकार के समय सीएस बने। कैट से मोहंती ने जांच पर स्टे लिया। लेकिन, जबलपुर हाईकोर्ट ने अप्रैल 2022 में स्टे को खारिज कर दिया। जांच फिर शुरू हो गई।

● **सुनील सिंह**

विवादों में रहे परशुराम और डिसा

वहीं प्रदेश के दो पूर्व सीएस अपने विवादों के कारण चर्चा में रहे हैं। पूर्व सीएस आर परशुराम भी विवादों से घिरे थे। आर परशुराम सीएस पद से सेवानिवृत्त होने के बाद सुशासन संस्थान के डीजी बने, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद जब फिर से शिवराज सरकार बनी तो उनका तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से विवाद हो गया। जबकि, पूर्व में वे शिवराज के करीबी रहे थे। लेकिन इस बार विवाद के बाद परशुराम को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद परशुराम के मतभेद लगातार भाजपा सरकार से सामने आए। वहीं पूर्व सीएस अंटोनी डिसा को मप्र भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) के अध्यक्ष पद से सत्ता परिवर्तन के बाद शिवराज सरकार ने हटा दिया था। इस पर भी खूब विवाद हुआ था। डिसा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के करीबी थे। इसलिए सीएस पद से सेवानिवृत्त के बाद रेरा अध्यक्ष बन गए थे। इस बीच 2018 में कमलनाथ सरकार बनी, तो डिसा के साथ कमलनाथ की खूब पटरी बैठी। मार्च 2020 में सत्ता के बाद शिवराज मुख्यमंत्री बने, तो डिसा की पटरी नहीं बैठी। उपचुनाव के ठीक पहले डिसा से इस्तीफा लिया गया।

खुले बोरवेल निगल रहे बच्चों को

खुले बोरवेल काल बनकर बच्चों को निगले जा रहे हैं और सरकार आंकड़े तक नहीं जुटा पा रही है। मप्र में पिछले पांच वर्षों में ही 10 बच्चों की मौत हो चुकी है। वहीं देशभर में 11 वर्षों में 16,282 बच्चे जान गंवा चुके हैं। मप्र सरकार की योजना थी कि इसके लिए एक विशेष पोर्टल बने, जिस पर प्रदेश के सभी बोरवेल का डाटा तो हो ही, खनन करने वाले ठेकेदारों और मशीनों तक का पंजीयन हो। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। उधर, बोरवेल में गिरकर बच्चों के मरने का सिलसिला निरंतर जारी है। अभी हाल ही में रीवा जिले के मनिका गांव में बीते दिनों एक मासूम की बोरवेल में गिरने से मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी खेत मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। रीवा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने इस मामले में बताया कि परिजनों की रिपोर्ट पर आईपीसी की धारा 304 के तहत आरोपी ब्रजेंद्र मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। बोर 2 से 3 साल पुराना है और इसे उन्होंने असुरक्षित तरीके से खोलकर रखा था।

बोरवेल में गिरे मासूम मयंक की मौत के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अनुपयोगी बोरवेल को बंद कराने के आदेश का पालन न करने, अपने कार्यक्षेत्र में अनुपयोगी एवं खुले बोरवेल का सत्यापन कराए बिना भ्रामक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर कमिश्नर गोपालचंद्र डाड ने त्योंथर विकासखंड के सीईओ राहुल पांडेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए हैं। खुले बोरवेल से हुई दुर्घटना का संज्ञान लेते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. सौरभ सोनवडे ने पंचायत समन्वयक अधिकारी प्रेम कुमार मिश्र और ग्राम रोजगार सहायक मनिका विकास मिश्र को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। गांव में अनुपयोगी तथा खुले बोरवेल को बंद न करने एवं दिए गए निर्देशों के पालन में लापरवाही बरतने और भ्रामक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. सौरभ सोनवड़े ने त्योंथर जनपद पंचायत के मनिका ग्राम पंचायत सचिव अशोक कुमार तिवारी को निलंबित कर दिया है। रीवा एसपी विवेक सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जहां खुले बोरवेल में गिरने की वजह से कई मासूमों की मौत हो चुकी है। जिन-जिन लोगों के बोरवेल खुले हैं वे सभी सुरक्षित तरीके से बोर को भरवाएं। अगर वे सक्षम नहीं हैं तो इसके लिए प्रशासन से मदद लें। प्रशासन पूरी मदद करेगा ताकि इसके बाद इस तरह की कोई भी जनहानि किसी भी बच्चे के साथ न हो। अगर पहले की मप्र में सरकार और कोर्ट के निर्देशों का पालन होता तो बच्चों की असमय मौत नहीं होती। इस संदर्भ में मप्र सरकार की योजना थी कि इसके लिए एक विशेष पोर्टल बने, जिस पर प्रदेश के सभी बोरवेल का डाटा तो हो ही, खनन करने वाले ठेकेदारों और मशीनों तक का पंजीयन हो। इस संबंध में 14 दिसंबर 2023 को पीएचई के तत्कालीन प्रमुख सचिव संजय शुक्ल ने निर्देश भी जारी किए थे, लेकिन योजना कागजों से बाहर ही नहीं आ सकी। इसके बाद हाल ही में 7 फरवरी को अपर मुख्य सचिव मलय श्रीवास्तव ने भी प्रदेश के सभी कलेक्टरों को पत्र लिखा। इसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2010 में जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार सुरक्षा के इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। इस पत्र में भी नलकूप खनन से जुड़े कामों की मॉनिटरिंग के लिए पोर्टल बनाने से जुड़ी जानकारी दी गई है। मुख्य सचिव वीरा राणा ने भी प्रदेश के समस्त कलेक्टर, सीईओ, नगर पालिका के कमिश्नर व सीएमओ को इस संबंध में आदेश जारी किया था।

खुले बोरवेल को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि सरपंच, कृषि विभाग के अफसर मॉनिटरिंग करें और खुले बोर बंद करवाएं। कलेक्टर व ग्राम पंचायत को लिखित सूचना के बाद बोरवेल खोदे जाए। बोरवेल खुदाई वाले स्थानों पर साइन बोर्ड लगाए जाएं। बोरवेल, कुएं की तार फेंसिंग की जाए। बोरवेल के पाइप के चारों ओर 0.30 मीटर ऊंचा प्लेटफार्म बनाया जाए। बोर के मुहाने पर स्टील की प्लेट बेल्ड की जाए या नट-बोल्ड से कसा जाए।

खुले बोरवेल की लापरवाही के लिए प्रदेश में सिर्फ चार मामलों में आठ लोगों पर केस दर्ज किया गया है। खास बात यह है कि सभी आरोपी जमानत पर हैं। अब तक सिर्फ एक ही मामले में सजा हुई है। देवास जिले के खातेगांव में चार साल का रोशन 10 मार्च 2018 को बोरवेल में गिरा था। उसे सुरक्षित निकाल लिया गया था। मामले में खेत मालिक हीरालाल जाट को दो साल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि तीन दिन में ही उसे जमानत भी मिल गई थी। वर्तमान में यह मामला हाईकोर्ट में लंबित है। रोशन को निकालते समय तत्कालीन एसडीएम जीवन रजक ने उसकी पढ़ाई का खर्च उठाने का वादा किया था। वे उसे आज भी निभा रहे हैं। भोपाल में कैबिनेट मंत्री के निज सहायक रजक हर साल स्कूल फीस व किताबों सहित ड्रेस का इंतजाम कर रहे हैं। रोशन एक निजी स्कूल में कक्षा तीसरी का छात्र है।

● **कुमार विनोद**

मप्र में इन बच्चों ने गंवाई जान

प्रदेश में खुले बोरवेल में गिरकर कई बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। प्रदेश में सबसे पहला मामला 10 मार्च 2018 को सामने आया जब रोशन (4) निवासी खातेगांव देवास की बोरवेल में गिरने से मौत हुई। उसके बाद 28 फरवरी 2022 में प्रिंस (3) बरखेरा जिला दमोह, 29 जून 2022 में अखिलेश (4) नारायणपुरा जिला छतरपुर, 14 मार्च 2023 में लोकेश (7) निवासी लटेरी, 6 जून 2023 में सृष्टि (ढाई साल) श्यामपुर सीहोर, 5 दिसंबर 2023 में माही (5) निवासी पिपलिया रसोड़ा जिला राजगढ़, 12 दिसंबर 2023 में विजय (5) निवासी खंडाला आलीराजपुर, 18 जुलाई 2023 में अस्मिता (ढाई साल) निवासी कजरी बरखेड़ा विदिशा और 15 मार्च 2023 में सागर बारेला (6) निवासी बुरहानपुर, अहमदनगर महाराष्ट्र में बोरवेल में गिरने से मौत हुई है।

विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद भाजपा लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतने का दम भर रही है। वहीं कांग्रेस दर्जनभर सीटों पर जीत का दावा कर रही है। जनता किसका साथ देती है यह तो 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन इस चुनाव में असली परीक्षा भाजपा और कांग्रेस के पीढ़ी परिवर्तन की है। दरअसल, भाजपा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की जोड़ी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है।

नए नेतृत्व की अग्निपरीक्षा

मप्र में 2023 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सियासी तौर पर बदलाव का काम किया। जनता ने इतना बड़ा जनादेश दिया कि भाजपा ने दो दशक से सत्ता की बागडोर संभाल रहे शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया और डॉ. मोहन यादव को सत्ता के शीर्ष पर बैठा दिया। कांग्रेस की बुरी हार के बाद केंद्रीय नेतृत्व ने युवा नेता जीतू पटवारी को पार्टी की कमान दी है। यानी विधानसभा चुनाव के बाद दोनों ही पार्टियों में पीढ़ी परिवर्तन हो चुका है। इसके बाद यहां लोकसभा का पहला चुनाव होने जा रहा है। भाजपा पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस या विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है। चुनावी रणनीति पर इसका भी असर है। मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव के लिए यह पहला चुनाव है। उनकी कोशिश सभी 29 सीटें जीतकर 2019 का रिकॉर्ड ध्वस्त करने की है, जिससे उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर खुद को स्थापित करने में आसानी हो सके। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की कोशिश है कि 2014 और 2019 के चुनावी आंकड़ों को सुधारा जाए और आलाकमान के सामने अपनी रणनीति का लोहा मनवाया जाए। इसलिए यह लोकसभा चुनाव पीढ़ी परिवर्तन की परीक्षा भी बन गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अबकी बार 400 पार के नारे को साकार करने के लिए मप्र में भाजपा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ रही है। मिशन-29 के लिए पार्टी ने बड़े-बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया है। हालांकि, छिंदवाड़ा, मंडला और झाबुआ सीट सबसे अधिक चर्चा में है, क्योंकि कांग्रेस को आदिवासी वोट बैंक पर सबसे अधिक भरोसा है। राहुल गांधी की प्रदेश में पहली जनसभा 8 अप्रैल को आदिवासी इलाके मंडला और शहडोल संसदीय क्षेत्र में ही हुई। कांग्रेस की कमान संभालने के बाद जीतू पटवारी के लिए भी यह पहला चुनाव है। जिस तरह से कांग्रेस के विधायक और कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं, उसको रोकना पटवारी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। कमलनाथ के बेहद करीबी रहे तीन बार के विधायक कमलेश शाह, दीपक सक्सेना कांग्रेस को अलविदा कह चुके हैं। इससे पार्टी की स्थिति नाजुक बनी हुई है। हर इलाके से कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में पटवारी की कोशिश है कि किसी भी तरह से प्रतिष्ठा बचाई जाए। 29 में से कुछ सीटें किसी भी तरह से कांग्रेस के खाते में चलीं जाएं, जिससे वे अपने नेतृत्व को साबित कर सकें, लेकिन मोदी के मैजिक के आगे पटवारी किस तरह से लड़ाई लड़ते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। कांग्रेस ने उमंग सिंघार को नए और आदिवासी चेहरे के तौर पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया है। पटवारी और सिंघार के कंधों पर ही पार्टी को आगे ले जाने की जिम्मेदारी है। प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी 50 फीसदी से ज्यादा है। इसलिए भाजपा ने मप्र में पिछड़े वर्ग से आने वाले शिवराज सिंह को हटाया तो उनकी जगह ओबीसी से ही आने वाले डॉ. मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया। ताकि किसी भी सूरत में ओबीसी वर्ग नाराज न होने पाए। राहुल गांधी की ओर से कुछ महीने पहले तक ओबीसी को लेकर प्रमुखता से मुद्दा उठाया जा रहा था।

मप्र में इस बार चार चरणों में चुनाव संपन्न होंगे। मतदान 19 व 26 अप्रैल और 7 व 13 मई को होगा। एक तरफ भाजपा ने राज्य में लोकसभा की सभी 29 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, वहीं कांग्रेस भी यहां 28 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। महागठबंधन के तहत कांग्रेस ने खजुराहो की एक सीट समाजवादी पार्टी के

कौन रोकेगा भाजपा को

विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस लोकसभा चुनाव में स्थिति सुधारना चाहती है। इसलिए पार्टी ने जहां राजगढ़ से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को मैदान में उतार दिया है, वहीं कमलनाथ ने छिंदवाड़ा सीट बचाने का भार अपने ऊपर ले लिया है। इससे पार्टी के दो बड़े दिग्गज अपने-अपने गढ़ में फंस गए हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की स्थिति दो नाव पर सवार जैसी हो गई है। वे तय नहीं कर पा रहे हैं कि चुनाव प्रचार पर जोर दें या संगठन में मची भगदड़ पर ध्यान दें। गौरतलब है कि भाजपा मिशन-29 के तहत प्रदेश की सभी सीटें जीतने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके लिए पार्टी ने चुनावी चौसर इस तरह बिछाई है कि कमलनाथ से लेकर दिग्विजय सिंह तक अपने गढ़ों यानी चुनाव क्षेत्रों में सिमटे हुए हैं। वे प्रदेश के दूसरे हिस्सों में जा नहीं पा रहे हैं। कमलनाथ अपने बेटे की जीत तय करने के लिए छिंदवाड़ा से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो दिग्विजय सिंह अपनी साख बचाने के लिए राजगढ़ में ही सीमित हैं।

लिए छोड़ी थी। सपा प्रत्याशी ने नामांकन भी किया, लेकिन तकनीकी खामियों की वजह से पर्चा निरस्त हो गया। ऐसे में अब भाजपा के मुकाबले में गठबंधन की ओर से 28 सीटों पर प्रत्याशी शेष बचे हैं। इसी के साथ देखा जाए तो राज्य की सभी सीटों पर स्थिति भी लगभग साफ हो गई है। ऐसे में हर तरफ एक ही सवाल चर्चा में है कि क्या मप्र में भाजपा 29-0 से जीत दर्ज कर पाएगी? दरअसल, भाजपा का दावा है कि वह इस बार मप्र में 29-0 से जीत दर्ज करने जा रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा सीट भाजपा हार गई थी लेकिन इस बार यह सीट भी भाजपा के पाले में आ सकती है। वहीं कांग्रेस दावा कर रही है कि लगभग 15 से अधिक सीटें वह जीत सकती है और अन्य सीटों पर भाजपा को कड़ी चुनौती पेश की जाएगी। दोनों पार्टियों के दावों पर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि युद्ध और चुनाव संसाधन से लड़े जाते हैं लेकिन जीते मनोबल से जाते हैं। न सिर्फ मप्र में बल्कि पूरे देश में चुनाव शुरू होने से पहले ही कांग्रेस का मनोबल शून्य की ओर है और भाजपा बड़ी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। बात मप्र की करें तो कांग्रेस के पास दो बड़े चेहरे कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ही हैं। अब कमलनाथ भाजपा में शामिल होने की खबरों के चक्कर में अपनी विश्वसनीयता खो दिए, जिसके कारण ही उनके गढ़ छिंदवाड़ा में उनका मेयर, दो विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष सहित ग्राउंड के नेता उनका साथ छोड़कर भाजपा में आ गए तो वहीं दिग्विजय सिंह तो शुरू से ही अनिच्छा से राजगढ़ सीट पर चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं।

जानकारों का कहना है कि कि मप्र के विधानसभा चुनाव की शर्मनाक हार के बाद से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल तो पहले से ही टूटा हुआ था लेकिन अब जिस तरह से उप्र में सपा, बिहार में आरजेडी, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस से कई ऐसी सीटें छोड़ने पर मजबूर कर चुके हैं, जहां कांग्रेस के उम्मीदवारों का हक मारा गया। इन राज्यों की खबरों का असर भी मप्र में कांग्रेस पर पड़ता दिख रहा है। वहीं इसकी तुलना में भाजपा ने मप्र में शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी के संकेत देकर विदिशा

में चुनाव में उतारा तो भाजपा संगठन के तीसरी लाइन के नेता डॉ. मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर पार्टी कार्यकर्ताओं को यह संदेश भी दे दिया कि दूसरी पार्टी से आने वाले नेताओं के ऊपर तव्वजो भाजपा कैडर को ही दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा भाजपा की सभी 29 सीटों पर आगे रखा गया है। ये सभी फैक्टर भाजपा के हित में काम करते हुए दिख रहे हैं। यह बात सही है कि मप्र में कांग्रेस की हालत ठीक नहीं है। लेकिन ग्राउंड से जिस तरह के समीकरण सामने आ रहे हैं, उसके अनुसार रतलाम से कांतिलाल भूरिया, राजगढ़ से दिग्विजय सिंह, मुरैना सीट से नीटू सिकरवार ये वो तीन नाम हैं, जो कांग्रेस की उम्मीदें जिंदा रख सकते हैं और जीत भी दर्ज कर सकते हैं। ग्वालियर-चंबल संभाग में बड़े पैमाने पर जाति की राजनीति होती है और उसका असर चुनाव परिणामों पर देखने को मिलेगा। मुरैना के अलावा ग्वालियर और भिंड लोकसभा सीट पर कांग्रेस कड़ी चुनौती दे सकती है। मालवा की रतलाम सीट पर कांतिलाल भूरिया के रूप में कांग्रेस ने बड़ा आदिवासी चेहरा उतारा है और वे कई बार इस क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव पूर्व में जीत भी चुके हैं। हालांकि भाजपा को पीएम नरेंद्र मोदी का चेहरा और कांग्रेस की बिखरी हुई टीम की वजह से बड़ा लाभ होना तय है।

भाजपा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से बड़ा लाभ मिलना तय है। मप्र में भाजपा का कैंडिडेट कोई भी हो, लोग तो प्रधानमंत्री मोदी को देख रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने राजगढ़, मुरैना, सतना, रतलाम, ग्वालियर सहित कुछ सीटों पर अच्छे कैंडिडेट उतारे हैं, जिनकी वजह से चुनाव कुछ सीटों पर कांटे का हो सकता है। लेकिन कांग्रेस को जीत मिल जाएगी, ऐसा नजर नहीं आता है। भाजपा ने कुछ सीटों पर अति आत्मविश्वास में टिकट दिए हैं, जिसकी वजह से भी कांग्रेस के उम्मीदवारों के साथ मुकाबला टक्कर का हो सकता है। लेकिन फिलहाल के जो समीकरण बनते दिख रहे हैं, उसमें भाजपा ही मप्र में बड़ी जीत दर्ज करती दिख रही है। भले ही चुनाव को देखते हुए भाजपा बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेताओं को पार्टी में शामिल करा रही है लेकिन भविष्य में इसके कुछ दुष्परिणाम भाजपा को भी झेलने पड़ सकते हैं। भाजपा संगठन के लिए चुनाव के बाद चुनौती होगी, कांग्रेस से आए नेताओं को भाजपामय बनाने और भाजपा के पुराने नेताओं के साथ सभी को एडजस्ट करने में। भाजपा और संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि इस बार भाजपा 29-0 से जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड बना सकती है। सिर्फ छिंदवाड़ा ही वह सीट थी, जिसे कांग्रेस बचा सकती थी। लेकिन जिस तरह से भाजपा ने पूरी योजना के तहत छिंदवाड़ा सीट की घेराबंदी की और एक-एक करके कमलनाथ के सभी खास और करीबी नेताओं को तोड़कर भाजपा में शामिल करा दिया, उसके बाद अब छिंदवाड़ा सीट भी कांग्रेस के हाथ से फिसलती हुई नजर आ रही है।

● **कुमार राजेन्द्र**

लगातार कमजोर हो रही कांग्रेस

छत्तीसगढ़ के मप्र से अलग होने के बाद हुए अब तक के चार आम चुनावों में केवल 2009 में मप्र में कांग्रेस ने 12 सीटें जीती हैं। राज्य विभाजन के बाद उसका यह अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। यहां तक कि छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद हुए पहले आम चुनाव में कांग्रेस ने 145 सीटें जीतकर केंद्र में सरकार बना ली थी, लेकिन तब उसे मप्र में महज चार सीटों से ही संतोष करना पड़ा। पार्टी के उम्मीदवार केवल गुना, छिंदवाड़ा, ग्वालियर व झाबुआ में ही जीत पाए थे। मप्र में लोकसभा की 29 सीटें हैं। नवंबर, 2000 में मप्र से अलग कर छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। तब से अब तक चार लोकसभा चुनाव हुए हैं, जिनमें कांग्रेस अपने कुल 19 प्रत्याशियों को ही संसद की दहलीज तक पहुंचा पाई है। दरअसल, अविभाजित मप्र के छत्तीसगढ़ अंचल में कांग्रेस की स्थिति शुरुआत से ही अच्छी थी। लेकिन, शेष मप्र में पार्टी की स्थिति उतनी अच्छी नहीं रही। ऐसे में 2004 के आम चुनावों में कांग्रेस को यहां से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन उसे अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी।

टारगेट पर हिडमा

मप्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में नक्सलवाद को बढ़ावा देने वाला खूंखार नक्सली मांडवी हिडमा सुरक्षा बलों के टारगेट पर है। पांच राज्यों के सुरक्षा बलों के बीच खतरे का पर्याय बने मांडवी हिडमा का सफाया करने के लिए विशेष प्लान बनाया गया है। सुरक्षा बलों के सूत्रों ने जानकारी दी है कि छत्तीसगढ़ के सुकमा में मांडवी हिडमा के गांव के नजदीक सुरक्षा बलों ने अपना बड़ा कैंप बना लिया है। यह कैंप गृह मंत्रालय के आदेश पर फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस योजना के तहत बनाया गया है। वहीं मप्र के बालाघाट, मंडला आदि क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी गई है।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सुकमा जिले के माड़ इलाके में मोस्टवांटेड नक्सली हिडमा का गांव है। यहां पर सुरक्षाबलों का जाना एक तरीके से अबूझ पहेली जैसा है। लेकिन एरिया डोमिनेशन की रणनीति पर काम करते हुए सुरक्षाबलों ने हिडमा के गांव पुरवर्ती में जाकर कैंप बना दिया है। अब ये कैंप यानी फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस बनने से इस पूरे इलाके में जल्द ही पक्की सड़कों का जाल बिछेगा। सुरक्षा महकमे के सूत्रों ने बताया है कि पीएलजीए-1 के कमांडरों ने हिडमा को भी ढेर करने का प्लान तैयार कर लिया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के कुछ जिले हैं, जहां पर मुट्ठीभर नक्सली बचे हैं।

सूत्रों के अनुसार गृह मंत्रालय का प्लान ये है कि अगले 3 साल के भीतर पूरे बस्तर को नक्सल मुक्त कर दिया जाए। घने जंगल जो कि छत्तीसगढ़ का दंडकारण्य का इलाका कहलाता है। इस इलाके तक पहुंचना काफी मुश्किल है। ऐसे में यहां सुरक्षा बलों की धमक कायम रखना जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय के आदेश पर लगातार फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस इन इलाकों में बनाए जा रहे हैं। इसका मकसद साफ है कि यहां पर सुरक्षा बलों की मौजूदगी रहे और नक्सली यहां से भाग खड़े हों। वहीं आशंका जताई जा रही है कि छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव के चलते हिडमा सहित अन्य नक्सली मप्र के बालाघाट, मंडला का रुख कर सकते हैं। इसलिए इन जिलों में सुरक्षा बलों के साथ ही गुप्तचरों को सतर्क कर दिया गया है।

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में आए दिन फॉरवर्ड ऑपरेशन बेस एफओबी स्थापित किए जा रहे हैं। नतीजा ये हो रहा है कि नक्सली अपने पुराने ठिकाने छोड़कर घने जंगल की तरफ भागने लगे हैं। छत्तीसगढ़ में कुल 25 से ज्यादा एफओबी यानी फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस बनाए गए हैं। एफओबी आसपास के क्षेत्रों में अभियान चलाकर नक्सलियों का सफाया कर रही है। एफओबी नक्सलियों के खिलाफ उनके ठिकानों के करीब आक्रामक अभियानों को अंजाम देने के लिए लॉन्च पैड के रूप में काम कर रही है। इसी रणनीति के तहत बस्तर में लगातार बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है। पिछले कुछ सालों में दंडकारण्य के इलाके में जो भी बड़े नक्सली हमले हुए हैं, उसमें ज्यादातर जगहों पर एनआईए और दूसरी एजेंसियों का 25 लाख के वांछित हिडमा का ही नाम सामने आता रहा है। साउथ सुकमा के पुरवर्ती गांव में जन्में हिडमा को हिडमालू और संतोष के नाम से भी जाना जाता है। साल 2001 में वो नक्सलियों से जुड़ा था। हिडमा को ऐसा नक्सल कमांडर मानते हैं, जिसने पूरे क्षेत्र में अपना सूचना तंत्र फैला रखा है।

हिडमा, बस्तर क्षेत्र के मुरिया जनजाति से आता है। उसके गांव में आज तक पुलिस नहीं पहुंच सकी है। लेकिन अब सुरक्षा बलों ने हिडमा के गांव मे अपना कैंप खोल लिया है। हिडमा के बारे में जानकार ये भी कहते हैं कि हिडमा को गोरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग विदेश में मिली है और वो एके-47 का सबसे पुराना जानकार है। जो इसके कुछ ही मिनटों में फायरिंग कर सकता है। हिडमा ने पहले ही खुद को एक ऐसे कमांडर के तौर पर कायम कर लिया है, जिसके पास रणनीति की कमी नहीं है। एनआईए के दस्तावेजों के मुताबिक हिडमा की उम्र इस समय 51 साल की है। एनआईए जिसकी गहन तलाश कर रही है।

सुरक्षा एजेंसियों ने एक्सक्लूसिव जानकारी दी है कि नक्सली टीसीओसी यानी टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन इन महीनों (अप्रैल से जून) में चला रहे हैं। जिसमें उनका मकसद होता है कि ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा बलों पर हमला कर इस दौरान नुकसान पहुंचाएं। सूत्रों ने ये बताया है कि नक्सलियों ने केवल छत्तीसगढ़ के साउथ बस्तर में ही टीसीओसी चलाने का प्लान नहीं बनाया है, बल्कि उन्होंने काफी सालों बाद नए ट्राई जंक्शन के नजदीक सुरक्षा बलों पर हमला करने का प्लान तैयार किया है।

● **बृजेश साहू**

...तो मारा जाएगा हिडमा

सुरक्षा बलों की रिपोर्ट को मानें तो नक्सली पीएलजीए बीएन-1 का कमांडर मांडवी उर्फ हिडमा सुरक्षा बलों के छीने हथियार और बीजीएल-रॉकेट लॉन्चर से हमले की फिराक में है। उधर सूत्रों की मानें तो हिडमा को पकड़ने और मारने का पूरा प्लान तैयार है। सुरक्षा बलों के इसी डर की वजह से नक्सली कमांडर हिडमा डीप फॉरेस्ट एरिया में छिपता फिर रहा है। पर अब नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने पिन पॉइंटेड ऑपरेशन का बड़ा प्लान तैयार किया है, जिसमें आने वाले दिनों में हिडमा मारा जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्स छत्तीसगढ़, मप्र, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित करीब गांवों का थर्मल इमेजिंग करवा रही है। यह इलाके नक्सलियों से प्रभावित हैं, जहां हिडमा के छिपे होने की आशंका है। इसके साथ ही इन इलाकों में नक्सलियों के बेस बने हुए हैं, सिक्योरिटी फोर्स इस काम में एनटीआरओ की मदद ले सकती हैं, जिससे इन इलाकों की मैपिंग की जा सके इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जब भी सिक्योरिटी फोर्सेज इन इलाकों में ऑपरेशन के लिए निकलेंगे तो उन्हें सारे रास्तों की जानकारी भी होगी साथ में ही नक्सलियों के खिलाफ बेहतर ऑपरेशन कोऑर्डिनेट करने में मदद मिलेगी।

खर्च की लिमिट तय

सोलर पंप योजना से लेकर देवारण्य योजना भी अटकेगी

नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही वित्त विभाग ने विभागों के खर्च की लिमिट तय कर दी है। अब योजनाओं के भुगतान पर वित्त विभाग की परमिशन अनिवार्य है। अब अगले 4 महीनों में 43 विभागों की कुल 102 योजनाओं पर फाइनेंस की परमिशन बगैर पेमेंट नहीं किए जा सकेंगे। इनमें चार स्मार्ट सिटी, लाड़ली लक्ष्मी योजना, महाकाल परिसर विकास योजना, राम वनगमन अंचल विकास योजना, वेदांत पीठ की स्थापना, बालिका स्कूटी योजना, सड़कों के निर्माण, तीर्थ यात्रा योजना, ग्रामीण परिवहन नीति, नक्सल जिलों में आईटीआई, देवारण्य योजना शामिल हैं। वहीं, सरकार ने 30 विभागों की 60 योजनाओं और कार्यक्रमों में होने वाले खर्च के भुगतान के लिए सक्षम अधिकारियों की अनुमति से पेमेंट को मंजूरी दी है। इस आदेश की खास बात यह है कि आमजन से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं के काम को भले ही वित्त विभाग की सहमति के बाद भुगतान के लिए कहा है। लेकिन, राजधानी और अन्य स्थानों पर कैबिनेट मंत्रियों के बंगलों की साज सज्जा और यहां किए जाने वाले मरम्मत और निर्माण के काम के लिए किसी तरह की रोक नहीं है। इसके लिए गृह विभाग और लोक निर्माण विभाग दोनों ही विभागों को अधिकार दिए गए हैं।

जिन विभागों की योजनाओं में वित्त विभाग की अनुमति बगैर भुगतान नहीं हो सकेंगे उसमें नगरीय विकास और आवास विभाग के अंतर्गत जबलपुर स्मार्ट सिटी, ग्वालियर स्मार्ट सिटी, उज्जैन स्मार्ट सिटी, सागर स्मार्ट सिटी, सतना स्मार्ट सिटी, शहरों में अधोसंरचना निर्माण, मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के चौथे चरण, कायाकल्प अभियान, एमपी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (वर्ल्ड बैंक), एमपी अर्बन सर्विस इक्युपमेंट प्रोग्राम फेस-2 व फेस-3, महाकाल परिसर विकास योजना तथा एमपी अर्बन सेनिटेशन एंड एनवायरनमेंट सेक्टर प्रोग्राम के पेमेंट शामिल हैं। साथ ही, गृह विभाग की मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना, महिला और बाल विकास की लाड़ली लक्ष्मी योजना और महिलाओं के लिए रोजगार मूलक आर्थिक सहायता के मामले में भी परमिशन जरूरी होगी।

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत मानसिक चिकित्सालय इंदौर और मानसिक आरोग्य शाला ग्वालियर का उन्नयन, नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना, नए नर्सिंग कॉलेजों का निर्माण करने के लिए अनुमति लेनी होगी। सहकारिता विभाग के अधीन सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को अल्पकालिक ऋण पर ब्याज अनुदान, मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना, प्राथमिक साख सहकारी समितियों का प्रबंधकीय अनुदान, औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग में औद्योगिकीकरण अधोसंरचना विकास, डेस्टिनेशन मप्र- इन्वेस्टमेंट ड्राइव और औद्योगिक क्षेत्रों का लैंडपूलिंग योजना से विकास तथा एमएसएमई विभाग की क्लस्टरों की स्थापना का काम भी फाइनेंस की स्वीकृति के बाद ही होगा। जारी आदेश के बाद संस्कृति विभाग के अंतर्गत सांची बौद्ध एवं भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय, वेदांत पीठ की स्थापना, राम वनगमन अंचल विकास योजना, हिंदी भवन निर्माण के लिए सहायता के काम वित्त विभाग की अनुमति के बिना नहीं होंगे। साथ ही जनजातीय कार्य विभाग शिक्षा उपकर से ग्रामीण शालाओं का उन्नयन और संधारण, आदिवासी पंचायतों के लिए बर्तन प्रदाय योजना, वन्या प्रकाशन, पीएम जनमन बहुउद्देशीय केंद्र निर्माण योजना, डॉ. टंट्या भील मंदिर का जीर्णोद्धार और राजा संग्राम सिंह पुरस्कार योजना के काम के लिए भी परमिशन लेना होगा।

परमिशन के दायरे में श्रम विभाग की मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना, पीएम फसल बीमा योजना भी है। साथ ही प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन के लिए प्रचार प्रसार योजना, खाद भंडारण पर ब्याज अनुदान, कृषि अधोसंरचना निधि का संचालन, कृषि यंत्रीकरण के क्षेत्र में कौशल विकास कार्यक्रम, कृषि क्षेत्र में अधोसंरचना विकास, कृषक उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन का काम करने के लिए भी अनुमति जरूरी की गई है। वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत डिजिटल इंडिया भूमि रिकार्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम, लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत मुख्य जिला मार्गों का नवीनीकरण, उन्नतिकरण व डामरीकरण, प्रवास भारतीय विभाग में फ्रेंड्स ऑफ एमपी कॉन्क्लेव, स्कूल शिक्षा विभाग में महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में पढ़ने-लिखने के लिए बैठक व्यवस्था और प्रयोगशाला, उत्कृष्ट विद्यालयों का अनुदान, मदरसों में गुणवत्ता परक शिक्षा एवं अधो संरचनात्मक विकास, मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना के भुगतान के लिए वित्त विभाग की परमिशन जरूरी होगी।

बजट नियंत्रण की इस व्यवस्था के चलते जारी किए गए आदेश के बाद नवीन और नवकरणीय ऊर्जा विभाग की मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के अंतर्गत आयुष्मान भारत, सीएम श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के काम भी प्रभावित होंगे। इसके अलावा उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना, पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, सिकल सेल एनिमिया, आशा कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन तथा आयुष विभाग की राष्ट्रीय आयुष मिशन और देवारण्य योजना भी फाइनेंस की अनुमति के दायरे में शामिल हैं। वित्त विभाग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के बाद धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग की तीर्थ यात्रा योजना, परिवहन विभाग के अंतर्गत ग्रामीण परिवहन नीति का क्रियान्वयन, पर्यटन विभाग के अंतर्गत पर्यटन अधोसंरचना का विकास, विमानन विभाग के अंतर्गत भू-अर्जन के लिए मुआवजा और हवाई पट्टियों का निर्माण और विस्तार करने पर भी ब्रेक लगेगा क्योंकि विभागों को इसके लिए भी परमिशन लेना होगी। वित्त विभाग द्वारा अलग-अलग 30 विभागों की 60 योजनाओं को सक्षम अधिकारियों की अनुमति से खर्च करने के लिए अधिकृत भी किया है। इसमें नगरीय विकास और आवास विभाग की ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अग्निशमन व्यवस्था के लिए अनुदान, स्थानीय निकायों के लिए प्रोत्साहन योजना, सीएम ग्रीन फील्ड सिटी चैलेंज, गृह विभाग के अधीन कैबिनेट मंत्रियों के आवास की साज-सज्जा और संधारण, पुलिस हाउसिंग विशेष केंद्रीय सहायता, महिला और बाल विकास विभाग की नारी अदालत समेत अन्य योजनाएं शामिल हैं।

● **विकास दुबे**

ईडी के रडार पर धंधेबाज

मप्र में खनन, जमीन और शराब माफिया केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की रडार पर हैं। ईडी इन सभी की कमाई का हिसाब-किताब लगा रही है। सूत्रों का कहना है कि ईडी को इनपुट मिला है कि मप्र में खनन और जमीन के कारोबार में अधिकारियों और नेताओं का कालाधन लगा हुआ है। वहीं इनके दम पर प्रदेश में खनन और जमीनों को काम अवैध रूप से किया जा रहा है। इस धंधे में दिन दुना रात चौगुना कमाई की जा रही है। ऐसे में अब ईडी ने कारोबारियों की कुंडली बनानी शुरू कर दी है। सूत्रों का दावा है कि जल्द ही राजधानी भोपाल सहित प्रदेशभर में ईडी के ताबड़तोड़ छापे पड़ेंगे।

सूत्रों का कहना है कि विगत वर्ष आयकर विभाग ने कुछ कारोबारियों के यहां छापा मारा था तो उसे अवैध कमाई और अफसर की काली कमाई के निवेश के प्रमाण मिले थे। वहीं दूसरे राज्यों में ईडी और आयकर विभाग की छापेमारी में भी मप्र से लिंक मिला है। इसलिए केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के अफसरों ने अचानक सक्रियता बढ़ा दी है। कुछ राज्यों में मारे गए ईडी व इनकम टैक्स के छापे के बाद मिले रिकार्ड के आधार पर कार्रवाई की तैयारी है। इसके लिए इनकम टैक्स, सीबीआई, ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त में दर्ज एफआईआर के साथ ही कई अन्य विभागों से भी आधा दर्जन लोगों के व्यवसाय के संबंध में गोपनीय जानकारी मांगी गई है। इसमें अधिकांश खनिज तथा जमीन के कारोबारी हैं। कारोबारियों की लंबी राजनीतिक व प्रशासनिक पहुंच है। इस कारण ईडी की टीम पहले सारे पुख्ता कागजात जुटा रही है, उसके बाद ही आगे कदम बढ़ाएगी।

जानकारी के अनुसार दो साल पहले इनकम टैक्स ने मप्र के एक बड़े खनिज कारोबारी के यहां छापा मारा था। छापे के दौरान कई सनसनीखेज जानकारियां मिली थीं। खनिज कारोबारी के तार दक्षिण भारत के एक बड़े उद्योगपति से जुड़े हैं। जिसके उद्योग में मप्र के कुछ लोगों के इवेस्टमेंट की जानकारी मिली थी। लंबे समय तक मामले की जांच काफी धीमी थी। अचानक इस जांच में तेजी आ गई है। इसको लेकर ईडी ने लगभग आधा दर्जन कारोबारियों को नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी होते ही कारोबारियों में हड़कंप मच गया है, क्योंकि खनिज व जमीन से जुड़े दोनों कारोबारी लंबी राजनीतिक व प्रशासनिक पहुंच वाले हैं। कई अधिकारियों व नेताओं की नंबर दो की कमाई भी उनके कारोबार में लगी हुई है, जिसका हिसाब-किताब लगाना मुश्किल है। इस नोटिस के बाद एक-दूसरे के धुर विरोधी दो खनिज कारोबारियों के बीच रंगपंचमी पर लंबी बैठक हुई, जिसमें दोनों ने अपने गिले-शिकवे दूर किए। साथ वहीं दोनों में संपत्ति व पैसे को लेकर जो विवाद था, वह भी समाप्त हो गया है। अब दोनों जांच एजेसियों से बचने की तकनीक खोज रहे हैं। खनिज कारोबारियों के तार भोपाल में जमीन का काम करने वाले एक कथित ठेकेदार से जुड़े हैं। उक्त ठेकेदार कई लोगों के पैसे भी डकार गया है। जिससे उसके विरोधी सक्रिय हो गए हैं और वे जांच एजेंसियों को वह सारे कागज भेज रहे हैं, जो अभी तक पड़े हुए थे। ईडी की खोजी टीम सूचना को पुख्ता करने के लिए पूरा रिकार्ड एकत्रित कर रही है, ताकि उसकी कार्रवाई पर कोई उंगली न उठा सके। राजधानी के आउटर एरिया में एक बड़ी कंपनी से औने-पौने दाम में खरीदी गई लगभग 100 एकड़ जमीन के कागजात खंगाले जा रहे हैं। जमीन की कीमत का भुगतान खनिज और जमीन कारोबारी के परिजनों के खाते से किया गया है। जमीन जिसने खरीदी उसके बारे में उक्त जमीन के आसपास रहने वाले किसानों से पूछा जा चुका है। किसानों ने जो जानकारी दी, उससे जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। इसी कारण ईडी ने जांच तेज कर दी है। अतिविश्वसनीय सूत्रों के अनुसार ईडी की टीम जल्द ही मप्र में बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। इससे कई सफेदपोश बेनकाब हो सकते हैं।

● **लोकेश शर्मा**

पूर्व सांसद का कटनी लिंक

तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा सदस्य रहे कंवर दीप सिंह का कटनी से करप्शन का लिंक निकला है। इसके बाद ईडी दिल्ली की टीम ने इस नेता और कारोबारी की मप्र और हिमाचल प्रदेश में मौजूद 29.45 करोड़ की चल अचल संपत्ति जब्त कर ली है। कंवर दीप सिंह द्वारा बेनामी प्रापर्टी खरीदी करने के साथ मोटी ब्याज पर पैसा, घर बनाने का सब्जबाग दिखाकर रुपए जमा कराए जा रहे थे लेकिन बाद में कंपनी इससे मुकर गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने कटनी के एक कारोबारी की 29.45 करोड़ की चल और अचल संपत्ति अटैच कर ली है। मनी लांड्रिंग के मामले में यह कार्रवाई एल्केमिस्ट ग्रुप कंपनीज के खिलाफ की गई जांच के बाद की गई है। अटैच की गई प्रापर्टीज में एक एयरक्राफ्ट बीच किंग एयर सी90ए भी शामिल है। इसके साथ ही फ्लैट और शिमला में मौजूद जमीन भी अटैच की गई है। हिमाचल प्रदेश के शिमला के अलावा इस कंपनी की सिरमौर (हिमाचल प्रदेश) और कटनी (मप्र) में मौजूद संपत्ति अटैच की गई है। एल्केमिस्ट ग्रुप एआईटीसी (ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस) से जुड़े पूर्व राज्यसभा सदस्य कंवर दीप सिंह का है। विवेचना के दौरान ईडी के जानकारी में यह बात सामने आई थी कि कुल 18 फ्लैट एल्केमिस्ट रियलिटी लिमिटेड द्वारा पार्श्वनाथ रायल प्रोजेक्ट से खरीदे गए थे। यह पार्श्वनाथ रायल प्रोजेक्ट पंचकूला, हरियाणा में काम करता है। यह जमीन 250 बीघा है जिसमें से 78 बीघा किओंथल में है। यह पूरी जमीन हिमाचल प्रदेश के शिमला रूरल डिस्ट्रिक्ट और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। बताया जाता है कि ईडी ने यह कार्रवाई सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर की है। यह एफआईआर लखनऊ और कोलकाता पुलिस और उप्र पुलिस द्वारा मल्टीपल इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप ऑफ एल्केमिस्ट ग्रुप के विरूद्ध की गई थी। ईडी की जांच में यह बात सामने आई है कि एल्केमिस्ट ग्रुप द्वारा 1800 करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स और गवाहों से अपनी कंपनी के नाम पर लिए गए थे। यह राशि मेसर्स एल्केमिस्ट होल्डिंग लिमिटेड और एल्केमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड के नाम पर जमा कराई गई।

छिंदवाड़ा बना साख

मुश्किल में हैं कमलनाथ

अब तक जितने भी कांग्रेसियों ने कमलनाथ का साथ छोड़ा है, वे सभी कमलनाथ के प्रभाव के चलते ही बड़े नेता बने हैं। कई नेताओं को राजनीति का ककहरा भी कमलनाथ ने सिखाया है। चूंकि कमलनाथ ने लंबे समय तक दिल्ली की राजनीति की है, अतः ये सभी नेता ही कमलनाथ के गढ़ को मजबूत करते थे। इन सभी ने कांग्रेस को नहीं बल्कि कमलनाथ को छोड़ा है क्योंकि अधिकांश का राजनीतिक भविष्य कमलनाथ के बिना संभव ही नहीं है। ऐसे में इनके भाजपा में जाने से कमलनाथ पर दबाव बना है और यही कारण है कि अब वे अपनी हर चुनावी सभा में छिंदवाड़ा से अपने राजनीतिक एवं पारिवारिक संबंधों का भावुक साथ गिना रहे हैं। एक समय अपने बेटे सहित भाजपा में प्रवेश की अटकलों से भी उन्हें नुकसान हुआ है और उनके करीबियों ने उनका साथ छोड़ दिया है।

भाजपा ने मप्र की सभी 29 लोकसभा सीटें जीतने के लिए हर सीट के हिसाब से चुनावी जमावट कर ली है। छिंदवाड़ा में भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने डेरा डालकर कमलनाथ के विश्वस्त कांग्रेसी नेताओं को अपने पाले में लाने की मुहिम चला रखी है। यह इंगित करता है कि इस बार भाजपा कमलनाथ को उनके ही गढ़ से मुक्त करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती। इसी कड़ी के तहत भाजपा ने अपना पूरा फोकस छिंदवाड़ा पर कर रखा है। कमलनाथ के किले को फतह करने के लिए भाजपा साम, दाम, दंड, भेद से भी नहीं चूक रही है। इसका ताजा उदाहरण यह है कि संसदीय क्षेत्र की पांढुर्ना सीट के विधायक नीलेश उइके के यहां छापामार कार्यवाही की गई है। कमलनाथ के पीए आरके मिगलानी के खिलाफ अश्लील वीडियो वायरल करने के मामले में केस दर्ज किया गया है। यही नहीं पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर छिंदवाड़ा में कमलनाथ के खिलाफ प्रचार करने का ऐलान किया है। सूत्रों का कहना है कि इसके पीछे भी भाजपा का ही हाथ है।

2019 के आम चुनाव में प्रदेश की 29 में से 28 सीटें जीतने वाली भाजपा को तब भी छिंदवाड़ा में हार मिली थी जबकि तत्कालीन कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी परंपरागत सीट गुना-शिवपुरी तक नहीं बचा पाए थे। कहने का तात्पर्य है कि छिंदवाड़ा तब भी भाजपा के लिए अबूझ पहेली था जब कमलनाथ के स्थान पर उनके पुत्र नकुलनाथ बतौर सांसद प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे। इस बार भी नकुलनाथ कांग्रेस की ओर से किला लड़ा रहे हैं जिनके सामने भाजपा के विवेक बंटी साहू विधानसभा चुनाव में मिली हार की कसर पूरी करने का दम भर रहे हैं। इस पूरी कवायद में उन्हें भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है, जबकि नकुलनाथ मात्र कमलनाथ की राजनीतिक विरासत के भरोसे हो गए हैं जो दिन-प्रतिदिन दरक रही है।

छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र 1951 में अस्तित्व में आया और तब से लेकर अब तक यहां 66 वर्षों से कांग्रेस का सांसद चुना जाता रहा है। सबसे अधिक 9 बार कमलनाथ (1980-1996, 1998-2014) यहां से सांसद रहे जबकि उनकी पत्नी अलकानाथ (1996) और पुत्र नकुलनाथ (2019) एक बार सांसद रहे हैं। तीन बार गार्गी शंकर मिश्र (1967-80), दो बार भीकूलाल चांडक (1957-1967) और एक बार रायचंद भाई शाह (1952) बतौर कांग्रेस सांसद छिंदवाड़ा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। मात्र 1997 के उपचुनाव में भाजपा के दिग्गज नेता सुंदरलाल पटवा ने कमलनाथ को हराकर इस सीट से कमलनाथ परिवार का तिलस्म तोड़ा था किंतु 1998 में हुए लोकसभा चुनाव में कमलनाथ ने पुनः अपनी पारंपरिक सीट पर अपना दबदबा सिद्ध कर दिया था।

छिंदवाड़ा संसदीय सीट पर कमलनाथ का कितना प्रभाव है यह इससे समझा जा सकता है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में इस संसदीय सीट की सातों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों को जीत प्राप्त हुई थी जबकि उक्त चुनाव में भाजपा ने प्रदेश में अपने इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। 2022 में महापौर चुनाव में भी छिंदवाड़ा से कमलनाथ के करीबी विक्रम अहाके ने बड़ी जीत दर्ज की थी। इसके अलावा कांग्रेस के 28 पार्षद भी निर्वाचित हुए थे। अभी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली पंचायतों, नगर पालिकाओं आदि पर भी कमलनाथ के समर्थक काबिज हैं किंतु इस बार भाजपा की रणनीति के चलते वे कमलनाथ का साथ छोड़ते जा रहे हैं।

भाजपा ने छिंदवाड़ा को कमलनाथ मुक्त करने के लिए 50 हजार से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भाजपा में शामिल करवाने का लक्ष्य रखा है ताकि कमलनाथ पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के साथ ही जनता के मन-मस्तिष्क में भी यह बात बिठा दी जाए कि अब कमलनाथ अकेले और कमजोर पड़ गए हैं। ऐसा होगा तो संभव है जनता भी उन्हें दरकिनार करने का मन बनाने लगे। अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आम से लेकर खास तक का भाजपा में प्रवेश सुनिश्चित हो रहा है ताकि कमलनाथ का हाथ छूटे। 22 फरवरी, 2024 को कमलनाथ के करीबी कांग्रेस के प्रदेश महासचिव उज्जवल सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने अपने 1,500 से अधिक समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ले ली। इसके बाद तो जैसे कांग्रेस में मची भगदड़ रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। 6 मार्च, 2024 को कांग्रेस के 7 पार्षदों को मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भाजपा में शामिल किया, जिससे नगर निगम में भाजपा के पार्षदों की संख्या बढ़कर 27 हो गई और कांग्रेस पार्षद 20 रह गए। दो सप्ताह के भीतर ही भाजपा ने कमलनाथ के करीबी और पूर्व प्रदेश कांग्रेस महामंत्री, पूर्व मीडिया उपाध्यक्ष सैयद जफर को भगवा दुपट्टा पहना दिया। 21 मार्च, 2024 को कमलनाथ को सबसे बड़ा झटका लगा जब उनके सबसे भरोसेमंद दीपक सक्सेना ने अपने बेटे अजय सक्सेना को भाजपा में शामिल करवा दिया। इसके बाद वे स्वयं भी भाजपा में शामिल हो गए। ये वही दीपक सक्सेना हैं जिन्होंने 2019 के विधानसभा उपचुनाव में कमलनाथ के लिए अपनी सीट छोड़ दी थी। इससे पहले कमलनाथ ने इन्हें विधानसभा में प्रोटम स्पीकर भी बनाया था।

● **अरविंद नारद**

देश में बढ़ रहा कुष्ठ रोग

दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले भारत में कुष्ठ रोग के मरीज सबसे ज्यादा हैं और विश्व भर में सालाना कुष्ठ रोग के जो मामले सामने आते हैं, उसमें भारत की हिस्सेदारी 55 प्रतिशत है। भारत में भी ऐतिहासिक तौर पर सात राज्यों (बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, उप्र और पश्चिम बंगाल) में कुष्ठ रोग के मामले सबसे अधिक हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशालय के मुताबिक, देश में हर साल जितने मामले सामने आते हैं, उनमें 70-80 प्रतिशत हिस्सेदारी इन सात राज्यों की होती है।

साल 2021 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की तरफ से जारी एक रिपोर्ट (क्लाइमेट वल्नरबिलिटी असेसमेंट फॉर एडॉप्शन प्लानिंग इन इंडिया यूजिंग ए कॉमन फ्रेमवर्क) में ऐसे जिलों की शिनाख्त की गई है, जहां जलवायु परिवर्तन का खतरा अधिक है। वहीं, द लेप्रोसी मिशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के विश्लेषण से पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन का खतरा झेलने वाले जिलों में ही कुष्ठ रोग व अन्य उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों (एनटीडीएस) जैसे हाथी पांव रोग (फाइलेरिया) का अधिक फैलाव होता है। हाथी पांव एक विषाणु-जनित संक्रमण है, जिससे पैर, बांह और जननांगों में सूजन हो जाता है। नीति आयोग की रिपोर्ट इंडिया नेशनल मल्टीडायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स 2021 (जो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के मानदंडों को आंकती है) से भी पता चलता है कि जो जिले पौष्टिक आहार व अन्य संकेतकों में खराब हैं, उन्हीं जिलों में कुष्ठरोग और अन्य उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग ज्यादा होते हैं।

मिसाल के तौर पर बिहार को लिया जा सकता है। केंद्रीय कुष्ठ रोग विभाग के मुताबिक, भारत में हर साल कुष्ठ रोग के जितने नए मामले सामने आते हैं, उनमें से 15 प्रतिशत मामले बिहार से होते हैं। राज्य की आधी आबादी (51.9 प्रतिशत) बहुआयामी गरीब है। यहां के तीन उत्तरी जिलों सीतामढ़ी, सुपौल और किशनगंज में प्रति 10,000 की आबादी में से 2.32 लोगों में कुष्ठ रोग है, जबकि राष्ट्रीय औसत 0.57 है। यहां यह भी गौरतलब है कि इन तीन जिलों की 63-65 प्रतिशत आबादी बहुआयामी गरीब है।

राज्य के कुछ जिलों में कुष्ठ रोग के 75 प्रतिशत मामले स्मीयर-पॉजिटिव (मल्टीबैसिलरी यानी एमबी) हैं। इस तरह के मामलों में मरीजों में विषाणुओं की मौजूदगी काफी ज्यादा होती है, जिससे और अधिक संक्रमण हो सकता है। प्रतिक्रिया विकसित होने के परिणामस्वरूप इस रोग से ग्रसित लोगों की नस क्षतिग्रस्त हो सकती है। प्लोस नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज में साल 2017 में प्रकाशित एक अध्ययन (जिसे ब्राजील और अमेरिका के शोधकर्ताओं ने तैयार किया था) में कहा गया है कि एमबी कुष्ठ रोग के मामले कम या कमजोर कोशिका-मध्यस्थ प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया वाले रोगियों में विकसित होते हैं, जिसका कारण प्रोटीन-ऊर्जा कुपोषण होता है। भारत में अनुकूलन संबंधी योजना के लिए एक साझा फ्रेमवर्क का उपयोग करते हुए जलवायु भेद्यता आंकलन-2021, इंडिया नेशनल मल्टीडायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स-2021 और सेंट्रल लेप्रोसी डिवीजन से मिले आंकड़ों का द लेप्रोसी मिशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा विश्लेषण यह देखते हुए बिहार में खाद्य सुरक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है। देशभर के शीर्ष 25 प्रतिशत जलवायु-संवेदनशीलता जिलों में बिहार के 31 जिले (राज्य में 38 जिले) शामिल हैं। बिहार के 94 लाख हेक्टेयर में से 68 लाख हेक्टेयर (उत्तर बिहार के 76 प्रतिशत और दक्षिण बिहार के 73 प्रतिशत) क्षेत्र बाढ़ प्रभावित हैं।

गर्मी के मौसम में सुखाड़ की लंबी अवधि, अनियमित मानसून बारिश और सर्दी के मौसम में रबी सीजन की बुआई के वक्त तापमान में असामान्य गिरावट व बढ़ोतरी से खाद्यान्न उत्पादन खासकर विविधतापूर्ण व पौष्टिक फसलों के उत्पादन के मामले में विषमता आती है, जो लोगों की आवश्यक पौष्टिक खुराक को प्रभावित कर सकता है। बिहार की तरह ही उप्र में भी इसी तरह के कारण और प्रभाव नजर आते हैं। साल 2020 में उप्र में कुष्ठ रोग के 15,848 नए मामले सामने आए और राज्य तीसरे स्थान पर रहा। उप्र के श्रावस्ती और बहराइच जिलों में कुष्ठ रोग की मौजूदगी काफी ज्यादा है और इन जिलों की 70 प्रतिशत आबादी बहुआयामी गरीबी में जी रही है। इन जिलों में उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के दूसरे मामले भी सामने आते हैं। साल 2019-2020 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक, उप्र की 31.2 प्रतिशत आबादी के पास पर्याप्त साफ-सफाई की व्यवस्था नहीं है। राज्य में स्वास्थ्य पर जितना खर्च होता है, उनमें से 72.6 प्रतिशत खर्च लोग अपनी जेब से करते हैं। यह राष्ट्रीय औसत (राष्ट्रीय औसत 48.8 प्रतिशत) की तुलना में काफी अधिक है। और इसके चलते लोगों को खाद्य सुरक्षा से समझौता करना पड़ता है।

● **प्रवीण सक्सेना**

स्वास्थ्य पर फोकस

राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम में साल 2027 तक के लिए दो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। पहला लक्ष्य संक्रमण को जिले स्तर पर ही रोकना या लगातार कम से कम पांच वर्षों तक बच्चों में कुष्ठ रोग के शून्य नए मामले लाना है और दूसरा लक्ष्य कुष्ठ रोग का बीमारी के तौर पर उन्मूलन या लगातार कम से कम तीन सालों तक कुष्ठ रोग के नए मामले नहीं आए, यह सुनिश्चित करना है। इसके लिए हमें स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में मांग और पूर्ति में हस्तक्षेप करने की जरूरत है। यह बहुत जरूरी है कि जिस आबादी पर जोखिम है, वह स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने में समर्थ बने। लेकिन जलवायु विसंगतियों से प्रभावित होने के चलते खाद्य असुरक्षा और कर्ज की चिंता बढ़ जाए, तो यह संभव नहीं। अतः अब राष्ट्रीय स्तर पर सोचने की जगह अति स्थानीय महामारी विज्ञान और मौसम संबंधी आंकड़ों के जरिए ब्लॉक स्तर पर भेद्यता मूल्यांकन पर फोकस करने की जरूरत है। वहीं, आपूर्ति की तरफ देखें, तो जलवायु व स्वास्थ्य में संबंध को लेकर फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को संवेदनशील बनाने के साथ-साथ उनमें जोखिम की शिनाख्त और रोकथाम के लिए हस्तक्षेप करने की योजना बनाने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। कुष्ठरोग को खत्म करने के लिए समग्र वन हेल्थ दृष्टिकोण को लागू करने की जरूरत है, जो बीमारी के नैदानिक पहलुओं से आगे जाकर स्वास्थ्य, आदिवासी मामलों, कृषि और पर्यावरण विभागों के बीच आपसी सहयोग पर फोकस करता है।

नौकरी भी गई...राजनीति भी खत्म

राजनीति की चाह में सरकारी नौकरी का लात मारने वाली पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे का कुछ ही महीनों में राजनीति से मोह भंग हो गया है। अब वे फिर से सरकारी नौकरी करना चाहती हैं।

निशा बांगरे ने कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ने के लिए डिप्टी कलेक्टर पद छोड़ा था, लेकिन अब वह फिर सरकारी नौकरी करना चाहती हैं। विधानसभा और लोकसभा चुनाव का टिकट न मिलने के बाद उनका राजनीति से अब मोहभंग हो गया है। उन्होंने शासन से अपना पद वापस मांगा है। निशा ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है, जिसमें इस बात का जिक्र किया है कि उन्हें डिप्टी कलेक्टर का पद वापस चाहिए। लेकिन सूत्रों का कहना है कि अब उनकी नौकरी में वापसी की संभावना खत्म हो गई है। ऐसे में लोग सवाल कर रहे हैं कि अब तेरा क्या होगा निशा बांगरे... ?

बता दें कि निशा बांगरे पर राजनीति का नशा इस कदर सवार था कि इस्तीफा स्वीकार कराने के लिए निशा बांगरे ने तत्कालीन शिवराज सरकार के सामने बड़ा आंदोलन खड़ा किया था। बैतूल से भोपाल तक पदयात्रा निकाली थी। इस दौरान भोपाल के एमपी नगर स्थित बोर्ड ऑफिस पर बाबा साहब भीवराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास पुलिस से नोकझोंक भी हुई थी, जिसमें निशा के कपड़े भी फट गए थे और जेल भी जाना पड़ा था। सही समय पर उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ और कांग्रेस ने बैतूल की अमला सीट से प्रत्याशी घोषित कर दिया था। इसके बाद निशा बांगरे का इस्तीफा स्वीकार हुआ था। हाल ही में निशा बांगरे को कांग्रेस ने प्रदेश प्रवक्ता बनाया था, लेकिन अब निशा बांगरे फिर सरकारी नौकरी में जाना चाहती हैं। वहीं कभी भाजपा को संविधान विरोधी बताकर कांग्रेस में शामिल होने वाली निशा अब कांग्रेस पर आरोप लगा रही हैं। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद वे भाजपा में जाने को तैयार हैं। भाजपा की न्यू जॉइनिंग टोली के पदाधिकारी के अनुसार अभी निशा बांगरे से कोई चर्चा नहीं हुई है। न ही इस मामले में कोई विचार किया है। हालांकि निशा के भाजपा में शामिल होने के पीछे यह वजह बताई जा रही है कि इस तरह नौकरी में वापसी में आसानी होगी। प्रदेश प्रवक्ता बना दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी। आखिरकार कांग्रेस को अंबेडकर विरोधी बताते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया।

राजनीति के लिए शासन-प्रशासन से लड़कर डिप्टी कलेक्टर की नौकरी से इस्तीफा दे चुकीं निशा बांगरे ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले वे नौकरी में वापस आने के लिए मप्र की मुख्य सचिव वीरा राणा को पत्र लिख चुकी हैं। सिविल सेवा नियम के अनुसार इस्तीफा स्वीकार होने के बाद फिर से नौकरी में वापसी का कोई प्रावधान ही नहीं है। मप्र में अभी तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को राजनीतिक कारणों से नौकरी छोड़ने पर इस्तीफा मंजूर होने के बाद वापस नौकरी नहीं मिली है। ऐसे में निशा बांगरे के मामले में भी वापस नौकरी मिलने की संभावना नहीं है। निशा बांगरे ने छतरपुर जिले में लवकुशनगर एसडीएम रहते सितंबर 2023 में नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने इस्तीफा मंजूर नहीं किया, तो उन्होंने बैतूल से लेकर भोपाल तक पदयात्रा निकाली। भाजपा सरकार पर महिला विरोधी होने के गंभीर आरोप लगाए। इस्तीफा मंजूर कराने उच्च न्यायालय तक पहुंची। न्यायालय के दखल के बाद सरकार ने 22 अक्टूबर 2023 को निशा का इस्तीफा मंजूर कर लिया था। निशा बांगरे का मामला राजनीतिक और चुनाव से जुड़ा होने की वजह से इस मामले में सरकारी अधिकारी अधिकृत तौर पर बोलने से बच रहे हैं। हालांकि सिविल सेवा नियम के अनुसार एक बार इस्तीफा मंजूर होने के बाद फिर से उसी पद पर नौकरी में लौटने की संभावना पूरी तरह समाप्त रहती हैं। अखिल भारतीय सेवा नियम, 1958 के रूत 5 क्लॉज ए के मुताबिक, यदि इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है तो 3 महीने के भीतर इस्तीफा वापस लिया जा सकता है। इस्तीफा मंजूर होने के बाद पद पर वापस नहीं आ सकते हैं। हालांकि कैबिनेट को अधिकार है, लेकिन कैबिनेट का फैसला दूसरे मामलों में नजीर बन जाएगा। ऐसे में कैबिनेट भी ऐसे फैसला लेने से बचेगी।

भारतरत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को भेजे दो पेज के इस्तीफे में कांग्रेस पर वादाखिलाफी समेत कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कांग्रेस को जलता हुआ घर बताया। साथ ही कहा कि कांग्रेस ने कभी बाबा साहब को टिकट नहीं दिया, बल्कि उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़े करके उन्हें चुनाव में हरा दिया। कांग्रेस ने न्याय तब भी नहीं किया था और कांग्रेस अब भी न्याय नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा- भारतरत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मानसपुत्री होने के नाते बाबा साहब हमेशा मेरे प्रेरणास्त्रोत रहे हैं।

● **राकेश ग्रोवर**

टिकट का वादा कर दिलवाया इस्तीफा

पूर्व प्रशासनिक अधिकारी निशा बांगरे ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर कहा कि जब कमलनाथ को टिकट ही नहीं देना था तो फिर इस्तीफा क्यों दिलवाया। पहले विधानसभा चुनाव में टिकट का वादा किया था और बाद में लोकसभा चुनाव में टिकट देने का वादा किया था लेकिन टिकट नहीं दिया। जब टिकट नहीं देना था तो फिर सर्विस से इस्तीफा क्यों दिलवाया। निशा बांगरे ने कहा कि कमलनाथ ने महिला और दलित समाज का अपमान भी किया है। निशा बांगरे ने कहा कि पिछले छह महीने से कांग्रेस की नीयत को करीब से आंकलन कर मैंने यह पाया कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे विधानसभा में टिकट देने का वादा किया। 229 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए और एक सीट आमला मेरे लिए होल्ड पर रखने का केवल दिखावा कर समाज का वोट बटोरना चाहा एवं खुद षड्यंत्र कर मुझे चुनाव लड़ने से रोका। ये मेरे लिए एक धक्का है। मेरे परिवार को लगता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है। मुझे भी लगता है कि कहीं न कहीं गलत तो हुआ है। अन्याय हुआ है। अगर समय पर इस्तीफा स्वीकार नहीं करना अन्याय है, तो यह भी एक तरह का अन्याय है। उन्होंने मेरा करियर खराब किया है।

मप्र कुपोषण बनाम कुनीति

मप्र में 1.36 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण से जूझ रहे हैं। कुपोषित श्रेणी के सबसे अधिक बच्चे जनजातीय बाहुल्य जिलों में हैं। बच्चों में कुपोषण होने के दो कारण हो सकते हैं- पहला तो यह कि देश-समाज में गंभीर खाद्य असुरक्षा की स्थिति हो, उत्पादन न हो रहा हो और प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो। दूसरा कारण यह हो सकता है कि शासन व्यवस्था नीति, नैतिकता और नियत के मानकों पर कमजोर हो। मप्र में निश्चित रूप से भोजन-पोषण के उत्पादन और उपलब्धता में कमी नहीं है। इस वक्त मप्र समग्रता में देश के सबसे ज्यादा भोजन उत्पादन करने वाले तीन राज्यों में शुमार होता है। ऐसे में 35.7 प्रतिशत बच्चों का ठिगनापन से और 19 प्रतिशत बच्चों का अल्प पोषण से ग्रसित होना यही दर्शाता है कि शासन व्यवस्था ने आर्थिक-सामाजिक-राजनीतिक विकास के मानकों में बच्चों के कुपोषण को कोई खास महत्व नहीं दिया है। मप्र में 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती-धात्री महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा स्थापित 7 पोषण आहार उत्पादन प्लांटों से हर हफ्ते पोषण आहार के पैकेट उपलब्ध करवाए जाते हैं। इसे टेक होम राशन कहा जाता है, जबकि 3 वर्ष से 6 वर्ष की उम्र के बच्चों को स्थानीय स्तर पर यानी गांव-बस्तियों में ही महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गरम पका हुआ पोषण आहार दिए जाने की व्यवस्था है। जमीनी अनुभव बताते हैं कि दोनों की व्यवस्थाओं में गंभीर उपेक्षा और गैर-जवाबदेहिता विराजमान है।

मप्र में 3 से 6 साल के बच्चों को गांवों में ही महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गरम पका हुआ पोषण प्रदान किया जाता है। इसके लिए गेहूं और चावल का आवंटन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा किया जाता है; लेकिन कम्प्यूटरीकरण की व्यवस्था के विकास के कारण मार्च 22 से 38 लाख बच्चों के लिए आवंटित होने वाला अनाज चार महीने जारी ही नहीं हो पाया। बच्चों को गरम पका हुआ पोषण आहार प्रदान करने का काम ग्रामीण क्षेत्रों में 50 हजार और शहरी क्षेत्रों में 2076 स्वयं सहायता समूह कर रहे हैं। आज की स्थिति यह है कि जो महिलाएं भोजन पकाने का काम करती हैं, उन्हें दिए जाने वाला 2000 हजार रुपए का मानदेय 3-4 महीने तक जारी ही नहीं होता है। इन स्थितियों में जब अनुसूचित जाति-जनजाति की महिलाएं पोषण आहार उपलब्ध नहीं करा पाती हैं, तब उनके विरूद्ध संगठित दुष्प्रचार भी शासन व्यवस्था के माध्यम से ही कराया जाता है। इस पोषण आहार पकाने वाले समूहों को खाद्य सामग्री के लिए मिलने वाली राशि 3 से 6 महीने की देरी से पहुंचती है। जिस आंगनवाड़ी केंद्र की स्थिति का जिक्र हमने किया है, वहां से स्वयं सहायता समूह के रसोइये को मार्च 2020 यानी कोविड-19 महामारी वाले महीने से मानदेय का भुगतान ही नहीं हुआ है।

यह मत मान लीजिएगा कि ऐसे उदाहरण इक्का-दुक्का होंगे। ऐसा होना वास्तव में नीति ही है। मप्र के महिला एवं बाल विकास विभाग के अनुसार राज्य में पोषण आहार कार्यक्रम में 69.44 बच्चे और 13.66 लाख महिलाएं दर्ज हैं, जिन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के मुताबिक वर्ष में 300 दिन पोषण आहार प्रदान किए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। भारत सरकार ने मानकों के मुताबिक बच्चों के पोषण आहार के लिए 8 रुपए, महिलाओं के लिए 9.50 रुपए और अति गंभीर तीव्र कुपोषित बच्चों के लिए 12 रुपए प्रतिदिन के मान से आवंटन किया जाना चाहिए। अगर यह मानक वास्तव में लागू किया जाए तो मप्र में पोषण आहार के लिए 2253.87 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाना चाहिए, लेकिन वर्ष 2021 में इसके लिए केवल 1450 करोड़ रुपए का ही आवंटन किया गया था। वर्ष 2022-23 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम-विशेष पोषण आहार कार्यक्रम के लिए 1272.24 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जब सरकार की मंशा ही कुपोषित है, तब बच्चे कुपोषण से मुक्त कैसे होंगे। उल्लेखनीय है कि अगर राज्य में उत्सवों, भीड़ जुटाने वाले कार्यक्रमों और महिला एवं बाल विकास विभाग के बजट से राजनीतिक कार्यक्रमों के आयोजनों का मोह त्यागा जा सके, तो पोषण आहार कार्यक्रम के लिए शेष एक हजार करोड़ रुपए जुटाए जा सकते हैं। वर्तमान बजट आवंटन से बच्चों और महिलाओं को 300 के स्थान पर केवल 187 दिन का ही पोषण आहार उपलब्ध करवाया जा सकता है। एक तरफ कुपोषण कम नहीं हो रहा है, तो दूसरी तरफ उनके लिए चलाई जाने वाली योजनाएं आर्थिक तंगी का शिकार हो रही हैं।

● **रजनीकांत पारे**

आर्थिक विकास बनाम कुपोषण

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 2005-06 में मप्र का राज्य सकल घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्य पर 1242 अरब रुपए था, जो वर्ष 2015-16 में लगभग चार गुना बढ़कर 5410 अरब रुपए और फिर वर्ष 2020-21 में साढ़े सात गुना बढ़कर 9175 अरब रुपए हो गया। राज्य की आर्थिक विकास दर लगभग 11.5 प्रतिशत रही है। खेती में अद्भुत चमत्कारिक विकास करने के लिए कई मर्तबा कृषि कर्मण पुरस्कार हासिल किया गया है, लेकिन ठीक इसी अवधि में बच्चों में कुपोषण की स्थिति क्या रही? जब आर्थिक विकास दर 11.5 प्रतिशत थी, तब वृद्धिबाधित (ठिगनापन) कुपोषण में केवल 1 प्रतिशत की दर से कमी हो रही थी। अल्प पोषण में केवल 1.1 प्रतिशत की दर से और कम वजन के बच्चों में 1.8 प्रतिशत की दर से कमी हो रही थी। इसका मतलब है कि आर्थिक विकास की नीतियों के स्वरूप और परिणामों का खाद्य असुरक्षा, आजीविका और बच्चों में कुपोषण के नजरिए से कभी भी कोई आंकलन नहीं किया गया। यह एक चिंतनीय स्थिति है कि मप्र में बच्चों में एनीमिया में कमी की दर 0.1 प्रतिशत और गर्भवती महिलाओं में 0.3 प्रतिशत है। ऐसे सूचकों के सामने होने के बाद भी मप्र आठ में चार पहर राजनीतिक उत्सव मनाता है और लोगों को अहसास करवाता है कि कुपोषण समाप्त हो गया है। कुपोषण एक ऐसी आपदा है, जिसमें अवसर, राजनीतिक लाभ और मुनाफा खोजने की प्रवृत्ति समाज और राज्य व्यवस्था के अनैतिक होने का प्रमाण देती है।

जल स्रोतों का टोटा

10 साल में 10 मीटर गिरा वॉटर लेवल

जानकारी के मुताबिक, इंदौर में भूजल का स्तर 2012 में 150 मीटर था, जो 2023 में 160 मीटर से अधिक हो गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि भूजल दोहन इसी गति से जारी रहा, तो 2030 तक भूजल स्तर 200 मीटर से अधिक गहरा हो सकता है। भूजल स्तर में गिरावट के कई गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इंदौर शहर में पानी की आपूर्ति का मुख्य स्रोत नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी का पानी शहर में पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाता है। हालांकि, बढ़ती आबादी और अनियंत्रित भूजल दोहन के कारण नर्मदा नदी पर भी दबाव बढ़ रहा है। इसके साथ ही शहर में पानी सप्लाई के लिए यशवंत सागर भी मददगार साबित होता है, लेकिन रिपोर्ट में हवाला दिया गया कि इंदौर और आसपास के क्षेत्र में जितना पानी का दोहन किया जा रहा है, उससे कम जल संचय और पुनर्भरण किया जा रहा है, जो घातक है। शहर में पिछले कई सालों से पानी बचाने की बातें की जा रही हैं, लेकिन पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए।

मप्र में लोकसभा चुनाव के प्रचार के साथ ही पारे में भी गर्माहट बढ़ने लगी है। पारा जैसे-जैसे बढ़ रहा है जल स्रोत सूखने लगे हैं। इस कारण प्रदेश के कई गांवों में अभी से जल संकट गहराने लगा है। हालात बिगड़ने लगे हैं। सरकारी आंकड़ों को देखें तो कई पेयजल स्रोत सूखने लगे हैं। कुएं, हैंडपंप और ट्यूबवेल में पानी नहीं है। इसके अलावा कई जगह तो विभिन्न कारणों से भी यह संकट पैदा हुआ है। चुनाव की आचार संहिता के कारण सरकारी मशीनरी भी कुछ करने की स्थिति में नहीं है। गांवों में पेयजल के लिए परेशान होना पड़ रहा है। कहीं बिजली कनेक्शन नहीं मिलने तो कहीं मोटर पंप खराब होने से और कहीं पेयजल स्रोत सूखने से गांवों और पंचायतों में नल-जल योजनाएं बंद पड़ी होने से ऐसे हालात बने हैं।

मप्र में पानी की कहानी रुलाने वाली है। मार्च 2023 में इंदौर हादसे में 36 लोगों की जान जाने के बाद प्रदेशभर में कुओं-बावड़ियों के सर्वे कराने और अवैध कब्जे हटाने के आदेश हुए। यह रिपोर्ट भले ही तैयार न हो पाई हो, लेकिन सरकार की एक अन्य रिपोर्ट ने चौंका दिया है। प्रदेश के 8 हजार जल स्रोत पूरी तरह से सूख चुके हैं। 1366 वॉटर बॉडीज पर न सिर्फ कब्जा है, बल्कि इन पर निर्माण भी हो चुका है। यह स्थिति तब है, जब गर्मियों में प्रदेश के कई ग्रामीण इलाकों में लोग पानी के लिए रोते हैं। प्रदेश के आधे से ज्यादा तालाबों का पानी न पीने के लिए उपयोग हो पता है और न दूसरे काम में। जलशक्ति मंत्रालय द्वारा देशभर की वॉटर बॉडीज की रिपोर्ट तैयार कराई गई है। इस रिपोर्ट में मप्र की जल संरचनाओं को लेकर स्थिति चिंताजनक मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक देशभर में कुल 16 फीसदी वॉटर बॉडीज का उपयोग ही नहीं किया जा रहा, जबकि मप्र में यह आंकड़ा करीब 45 फीसदी है। यानी प्रदेश में करीबन आधे जल स्रोतों का उपयोग किया ही नहीं जा रहा, जबकि मप्र के ग्रामीण इलाकों में पानी को लेकर परेशानी पैदा होती है।

रिपोर्ट के मुताबिक मप्र में कुल मिलाकार 82 हजार 643 वॉटर बॉडीज मौजूद हैं। इसमें से शहरों में 1520 तालाब, 1 वॉटर कंजर्वेशन स्कीम और 110 दूसरे जल स्रोत हैं, इस तरह कुल 1631 वॉटर बॉडीज हैं। प्रदेश के गांवों में 78298 तालाब हैं। इसके अलावा 71 टैंक, 30 झील, 75 तालाब और 337 जल संरक्षण स्कीम और डेम, इसके अलावा 2201 दूसरे तरह के जलस्रोत मौजूद हैं। मप्र में मौजूद कुल जल स्रोतों में से 36 हजार 628 तालाबों का उपयोग सिंचाई, उद्योग और पेयजल के लिए उपयोग हो रहे हैं। 43190 तालाबों के पानी का कोई उपयोग ही नहीं हो रहा है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट में सामने आया है कि प्रदेश की 8 हजार 36 वॉटर बॉडीज सूख चुकी हैं। जिसकी वजह से इसका उपयोग निस्तार और पेयजल के लिए किया जाना संभव नहीं हैं। प्रदेश में 1366 वॉटर बॉडीज ऐसी हैं, जिस पर न सिर्फ अतिक्रमण हो चुका है, बल्कि उन पर निर्माण भी किया जा चुका है। 917 जल स्रोतों की हालत तो यह है कि इसमें अब सुधार कर पाना भी संभव नहीं है।

जल स्रोतों पर अतिक्रमण के कई उदाहरण हाल ही में सामने आ चुके हैं। इसमें एक इंदौर का है, जिसमें मंदिर में मौजूद बावड़ी के ऊपर पक्का निर्माण किया गया था। जिसके टूटने से 36 लोगों की जान गई थी। घटना के बाद यहां से प्रशासन ने अतिक्रमण को हटाया। ग्वालियर में एक बावड़ी के ऊपर मल्टी का निर्माण कर दिया गया, जिसकी जांच जिला प्रशासन द्वारा कराई जा रही है। झीलों की नगरी के रूप में पहचानी जाने वाली भोपाल के कई छोटे तालाबों पर कब्जे किए जा चुके हैं, जिससे वह खत्म होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। इन पर से अतिक्रमण हटाने कोर्ट तक निर्देश दे चुका है। सागर जिले की प्रसिद्ध बंजारा झील अतिक्रमण की चपेट में है। रसूखदारों के कब्जे को हटाने के लिए एनजीटी भी आदेश दे चुकी है।

प्रदेश में वर्तमान में 16 शहरों में बड़ा जल संकट देखने को मिल रहा है। इंदौर शहर के कई हिस्सों में पिछले 10 सालों की तुलना में 10 मीटर तक भूजल स्तर कम हुआ है, लेकिन वॉटर लेवल बढ़ाने के लिए जिम्मेदारों के प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। बल्कि वह आंख बंदकर भयावह स्थिति बनने का इंतजार कर रहे हैं। कई साल पहले जल संचय के लिए बने रिचार्ज पिट पिछले कुछ सालों से खराब हैं। गर्मी शुरू होने से पहले जिम्मेदारों ने टैंकर संचालन और उसकी योजना तैयार कर ली, लेकिन रिचार्ज पिट सुधारने पर ध्यान नहीं दिया और ना ही रेन वॉटर हार्वेस्टिंग को लेकर योजना बनाई है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) की रिपोर्ट के अनुसार, इंदौर में भूजल का स्तर क्रिटिकल स्थिति में पहुंच गया है। इसी तरह लगातार भूजल दोहन के कारण भविष्य में सूखे का खतरा बढ़ सकता है। भूजल स्तर पिछले 10 वर्षों में 10 मीटर से अधिक गिर गया है। यह गिरावट बढ़ती आबादी, अनियंत्रित भूजल दोहन, अनियंत्रित शहर विस्तार और जल संचय की कमी के कारण हुई है। इसके लिए करीब 8-10 वर्ष पहले शहरभर में 100 से अधिक रिचार्ज पिट बनाए गए थे। यह रहवासी, व्यवसायिक और सार्वजनिक स्थानों पर थे, ताकि बल्क में निकलने वाला पानी यहां पहुंचे और फिर से यह पानी भूमि जल में मिल सके। यह रिचार्ज पिट अब खराब हो चुके हैं। पिट में जमा गाद को निकालकर फिल्टर मटेरियल डालना है। इसमें मामूली खर्च ही होगा।

● **श्याम सिंह सिकरवार**

मतदाता बिन मतदान

मप्र की 29 लोकसभा सीटों के लिए प्रचार जोरों पर है। लेकिन प्रत्याशियों के सामने सबसे बड़ी समस्या है प्रवासी श्रमिकों की। कई संसदीय क्षेत्रों में हजारों की संख्या में श्रमिक दूसरे प्रदेश या क्षेत्र में काम करने गए हैं। इन श्रमिकों को लाना शासन और प्रशासन दोनों के लिए बड़ी चुनौती है। जैसे-जैसे भारत 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयार हो रहा है, मतदाताओं का एक महत्वपूर्ण वर्ग खुद को एक अप्रत्याशित बाधा का सामना कर रहा है। यह वर्ग है प्रवासी मजदूर, जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने गृहक्षेत्र तो जाना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक संकट के चलते वह ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए खासे उत्सुक हैं, लेकिन आर्थिक कठिनाई की कठोर हकीकत उन्हें अपने इस मौलिक अधिकार से दूर कर रही हैं। कम वेतन और घर तक की महंगी यात्रा इन प्रवासी श्रमिकों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है।

प्रवासी श्रमिक संजय झा अप्रैल-मई में होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर उत्साहित हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के इच्छुक हैं। लगभग 30 वर्षीय संजय मुंबई, महाराष्ट्र में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करते हैं। जहां से उन्हें बिहार में अपने पैतृक गांव जाना फिलहाल संभव नहीं लगता। झा कहते हैं कि वह पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान मतदान करने में विफल रहे थे, क्योंकि वह बिहार में सीतामढ़ी जिले के रून्नीसैदपुर ब्लॉक में अपने रूपौली गांव जाने का प्रबंध नहीं कर सके थे। उन्होंने कहा, हर कोई वोट देना चाहता है। मैं वास्तव में वोट देने के लिए उत्सुक हूं; यह मेरा मौलिक अधिकार है। लेकिन वित्तीय संकट के कारण मुझे संदेह है कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। मैं अपने परिवार के लिए आजीविका कमाने के लिए संघर्ष कर रहा हूं और हर दिन बारह घंटे कड़ी मेहनत करने के बाद किसी तरह जीवित रह रहा हूं।

झा हर महीने 15,000 रुपए कमाते हैं और सिर्फ वोट देने के लिए घर वापस जाने के लिए 5,000 से 6,000 रुपए खर्च करना पड़ता है। उन्होंने कहा, यह मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है। अगर मैं यात्रा का खर्च वहन कर पाता तो कोई समस्या नहीं होती। मैं अकेला नहीं हूं; अधिकांश अप्रवासी मजदूर (प्रवासी श्रमिक) इस वास्तविकता का सामना कर रहे हैं जो उन्हें वोट न देने के लिए मजबूर करता है। झा जैसे हजारों प्रवासी श्रमिकों को हर बार चुनाव के दौरान इस मुद्दे का सामना करना पड़ता है और उन्हें मतदान के अधिकार का प्रयोग करने का मौका नहीं मिलता है।

मुंबई में गोरेगांव के पास एक संगमरमर की दुकान पर काम करने वाले मजदूर शब्बीर शेख की कहानी भी झा से मिलती-जुलती है। उन्होंने कहा, प्रवासी श्रमिकों के पास वोट देने के लिए घर जाने के लिए अतिरिक्त पैसे नहीं हैं। हमें अपने परिवारों का भरण-पोषण करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। शेख की उम्र 40 साल के आसपास है और वह बिहार के किशनगंज जिले के ठाकुरगंज ब्लॉक के एक गांव के रहने वाले हैं। यहां तक कि गांव में भी उनके परिवार के पास कोई जमीन या पक्का घर नहीं है। उन्होंने स्वीकार किया कि यदि उनके गांव में निशुल्क जाने की सुविधा हो तो वे मतदान करना चाहते हैं और उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि उनके जैसे लोगों के लिए स्थानीय स्तर पर मतदान करने की व्यवस्था है या नहीं। शेख ने कहा, छह लोगों का मेरा परिवार साल में एक बार से अधिक हमारे गांव जाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि यात्रा के लिए कम से कम 5,000 रुपए खर्च होते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो प्रति माह 15,000 रुपए कमाता है, यह बहुत बड़ी रकम है।

बिहार के किशनगंज जिले के बहादुरगंज ब्लॉक के एक गांव के निवासी सेफायत हुसैन एक युवा प्रवासी श्रमिक हैं। वह कहते हैं, मैं मुंबई में काम करता हूं और रहने का खर्च उठाने और अपने परिवार को पैसे भेजने के बाद मैं कुछ बचा नहीं पाता। अपने घर के पास कोई काम उपलब्ध नहीं होने के कारण हुसैन को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा, अन्यथा मैं अपने परिवार को घर छोड़कर कम वेतन वाली आजीविका के लिए इतनी लंबी दूरी की यात्रा क्यों करूंगा। बिहार में मधेपुरा जिले के मुरलीगंज ब्लॉक के डुमरिया गांव के निवासी हरेंद्र मंडल को अफसोस है कि अविकसित क्षेत्रों के गरीब प्रवासी कामगार नौकरियों की तलाश में दूर जाने के लिए मजबूर हैं, और उन्हें मतदान के लिए घर लौटने की सुविधा के लिए मालिकों से कोई मदद नहीं मिलती है। तमिलनाडु के तिरुपुर में एक कपड़ा कारखाने में काम करने वाले मंडल कहते हैं, हमें काम की तलाश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से सैकड़ों किलोमीटर दूर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। सरकार मतदान के लिए हमारे घर वापस आने का कोई इंतजाम क्यों नहीं करती? आखिरकार हमारे पास अन्य लोगों की तरह समान अधिकार हैं, लेकिन सफर के लिए पैसे की कमी के कारण हम मतदान से वंचित हैं।

● **जितेंद्र तिवारी**

प्रवासियों को बुलाने की हो सरकारी व्यवस्था

राज्य श्रम विभाग के एक अधिकारी का कहना है कि प्रदेश के एक दर्जन जिले गरीबी की उच्च दर के कारण प्रवासी श्रमिकों का केंद्र हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान हजारों प्रवासी श्रमिक इन क्षेत्रों में घर लौट आए और घर वापसी के कठिन सफर के दौरान उन्हें दर्द, संघर्ष और दुख का सामना करना पड़ा। मुंबई में फुटपाथ पर फल बेचने वाले प्रवासी जय प्रकाश यादव मार्च 2024 में एक शादी में शामिल होने के लिए सागर जिले के अपने गांव आए थे। उन्होंने कहा, मैं अब केवल अगले साल ही गांव का दौरा कर सकता हूं। लोकसभा चुनाव में मतदान पर उन्होंने कहा कि अधिकारियों को प्रवासी श्रमिकों के लिए विशेष व्यवस्था करनी चाहिए या वोट डालने के लिए मुफ्त यात्रा कूपन देना चाहिए। मप्र राज्य चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, राज्य में हजारों प्रवासी श्रमिकों की वापसी के कारण 2023 में मप्र विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत में वृद्धि हुई, खासकर उन जिलों में जहां लौटने वाले प्रवासियों का प्रतिशत अधिक था। मतदाताओं में वृद्धि मुख्य रूप से प्रवासी श्रमिकों की वापसी के कारण हुई, जो सामान्य परिस्थितियों में मतदान के लिए उपस्थित नहीं होते।

जेल से सरकार, नफा या नुकसान

फैसला उपराज्यपाल करेंगे या सुप्रीम कोर्ट

संवैधानिक संकट अब शुरू हुआ है। उपराज्यपाल पहले ही कह चुके हैं कि वह जेल से सरकार नहीं चलने देंगे। दिल्ली हाईकोर्ट पहले ही कह चुकी है कि संवैधानिक संकट का समाधान उपराज्यपाल या राष्ट्रपति को निकालना है। सवाल यह है कि क्या उपराज्यपाल किसी अन्य मंत्री को मुख्यमंत्री नियुक्त करके नई सरकार बनाने को कह सकते हैं। जैसे तमिलनाडु के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इसका फैसला आम आदमी पार्टी नहीं करेगी, फैसला उपराज्यपाल करेंगे या सुप्रीम कोर्ट करेगा। उपराज्यपाल यानी मोदी सरकार। पहली जिम्मेदारी मोदी सरकार की ही है। दिल्ली सरकार के बारे में मोदी सरकार जो भी फैसला करेगी, उसका चुनावी राजनीति पर असर पड़ेगा। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनावों के समय केजरीवाल की गिरफ्तारी और उनकी सरकार का बर्खास्त किया जाना भाजपा को महंगा पड़ सकता है। जबकि दूसरी तरफ मोदी सरकार ने चुनावों की घोषणा के बाद ईडी को केजरीवाल की गिरफ्तारी की हरी झंडी भी तो कुछ सोच समझकर दी होगी। भाजपा में भी इसे लेकर मतभेद हैं।

पिछले साल फरवरी में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने तिहाड़ जेल में पहुंचते ही इस्तीफा दे दिया था। तब से आशंका व्यक्त की जा रही थी कि शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी होगी। कम से कम अरविंद केजरीवाल को तो आशंका थी ही, इसलिए उन्होंने खुद कहा था कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया, तो वह इस्तीफा नहीं देंगे, बल्कि जेल से ही सरकार चलाएंगे। जेल से सरकार चलाने का जनादेश लेने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में कुछ घरों में जाकर लोगों से पूछा था कि अगर केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है, तो उन्हें जेल से ही सरकार चलानी चाहिए या इस्तीफा दे देना चाहिए। बाद में आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि 98 प्रतिशत जनता ने कहा है कि अगर केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है, तो वह जेल से ही सरकार चलाएं। गौरतलब है कि आप के नेताओं के साथ ही सरकार के करीबी अफसरों के खिलाफ भी कार्यवाही की जा रही है। दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार समेत दो अफसरों पर फाइलें चोरी की शिकायत के मामले में केस दर्ज किया गया है।

ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को हिरासत में लिया था, वह तब से ईडी के रिमांड पर चल रहे थे। लेकिन रिमांड खत्म होने के बाद अब उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। इससे पहले रिमांड के दौरान भी किसी के मुख्यमंत्री बने रहने का कोई उदाहरण मौजूद नहीं था, लेकिन अब तो केजरीवाल को बाकायदा जेल भेज दिया गया है। वह पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं, जो पद पर रहते हुए जेल में प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक लालू यादव और जे जयललिता के दो उदाहरण दिए जाते थे, जिन्होंने जेल में जाने से पहले इस्तीफा दे दिया था। हालांकि इन दोनों से पहले 1982 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एआर अंतुले को भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाने से पहले इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि बाद में उसी केस में वह सुप्रीम कोर्ट से बरी हो गए थे। उमा भारती ने तो सिर्फ कोर्ट का समन आने पर इस्तीफा दे दिया था। मदनलाल खुराना ने सिर्फ आरोप लगने पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अब उस लिस्ट में हेमंत सोरेन का नाम भी जुड़ गया है।

केजरीवाल के वकीलों और खुद केजरीवाल को भी नहीं लगता कि उन्हें जल्दी जमानत मिलेगी, इसलिए उन्होंने जेल में पढ़ने के लिए तीन किताबों की मांग की। अरविंद केजरीवाल की तरफ से दलील दी जा रही है कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जेल जाने पर उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। वह ठीक कह रहे हैं, संविधान में ऐसा बिलकुल नहीं लिखा। संविधान सभा के 389 सदस्यों की नैतिकता का स्तर इतना ऊंचा था कि किसी एक ने भी इस मुद्दे पर सोचा ही नहीं कि भविष्य में ऐसी नौबत आ सकती है। लेकिन जो बात संविधान में नहीं लिखी हो उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही परंपरा बनता है, और उसे ही कानून भी माना जाता है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला पहले से मौजूद है, इसलिए 28 मार्च को जब हाईकोर्ट ने केजरीवाल को हटाने के बारे में पीआईएल नामंजूर की, तो आश्चर्य हुआ। इसलिए यह मामला नए सिरे से हाईकोर्ट के सामने आया हुआ है। पहली बार याचिका अस्वीकार करते हुए कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई **संवैधानिक संकट है,** तो उस पर उपराज्यपाल या राष्ट्रपति को फैसला करना है।

अब नई याचिका में कहा गया है कि कोर्ट उपराज्यपाल को आदेश दे कि वह केजरीवाल को बर्खास्त करें। लेकिन लगता नहीं कि हाईकोर्ट इसमें दखल देगा। संभावना यही है कि हाईकोर्ट इस संबंध में यह मामला उपराज्यपाल और राष्ट्रपति पर ही छोड़ने की बात कहेगी। निश्चित है यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। यहां महत्वपूर्ण यह है कि सुप्रीम कोर्ट का पहले का एक फैसला केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद पर रहने की इजाजत नहीं देता। जयललिता दो बार जेल गई थी, पहले 2001 में और दूसरी बार 2011 में। उन्होंने दोनों ही बार इस्तीफा दे दिया था। लेकिन जयललिता के इस्तीफे से पहले तमिलनाडु सरकार का एडवोकेट जनरल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उनके पास जनता का जनादेश है। तमिलनाडु की सरकार जयललिता को ही मुख्यमंत्री देखना चाहती हैं और लोकतंत्र में जनादेश का सम्मान होना चाहिए। बिलकुल वैसे ही जैसे केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सभी नेता कह रहे हैं। लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार संविधान के अंतर्गत बनती है। सम्मान संविधान का होता है, संविधान के कारण ही जनादेश मिला है। जनादेश के आधार पर किसी अपराधी या आरोपी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बिठाया जा सकता। इसलिए जो कुछ भी होगा, वह संविधान के माध्यम से होगा और संविधान इजाजत नहीं देता है कि जेल के अंदर से सरकार चलाई जाए। सुप्रीम कोर्ट का एक और जजमेंट है- आरएस नायक बनाम एआर अंतुले। इस मामले में अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुख्यमंत्री पब्लिक सर्वेंट होता है। क्योंकि वह पब्लिक सर्वेंट होता है, इसलिए उस पर पब्लिक सर्वेंट के सारे नियम लागू होंगे।

● **जय सिंह सेंधव**

जंगल पर मंडरा रहा आग का खतरा

मप्र में 94,689 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। इसमें 61,886 वर्ग किलोमीटर आरक्षित वन, 31,098 वर्ग किलोमीटर संरक्षित वन और 1705 वर्ग किलोमीटर अन्य वन क्षेत्र है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार जंगलों में आग लगने की घटनाओं के मामले में ओडिशा के बाद मप्र दूसरे नंबर पर है। हर साल आगजनी की घटनाओं के कारण जंगल में चारे का संकट खड़ा हो जाता है। इससे पेड़-पौधों के साथ जीव-जंतुओं को भी नुकसान होता है। वन्य प्राणियों को भोजन की तलाश में दूर तक प्रवास करना पड़ता है। 2019 में केंद्र ने जंगल की आग की घटनाओं को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया था। राष्ट्रीय आपदा मिशन के अनुसार 95 प्रतिशत घटनाएं मानवजनित होती हैं। ट्राइबल बेल्ट में अब भी आस्था के नाम पर मन्नत पूरी होने पर जंगलों में आग लगा दी जाती है। इससे भी हर साल हजारों हेक्टेयर जंगल नष्ट हो जाता है। विदिशा, दमोह, डिंडोरी और देवास में सबसे ज्यादा घटनाएं होती हैं।

जंगल की आग बार-बार होने वाला पर्यावरणीय मुद्दा बन गई है, जिसके दुनिया भर के पर्यावरण और मानव समुदायों पर विनाशकारी परिणाम हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट में कहा गया है कि जंगल की आग की आवृत्ति और तीव्रता तेजी से बढ़ रही है। भारत में, मप्र 77,493 वर्ग किमी के वन क्षेत्र वाला राज्य (राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 25.14 प्रतिशत) गर्मी के मौसम के दौरान जंगल की आग के लिए अतिसंवेदनशील है। पर्णपाती जंगलों का प्रभुत्व, जो जंगल की आग की चपेट में हैं, मानवीय गतिविधियों, उनके संबंधित प्रभावों और जलवायु परिवर्तन के कारण स्थिति खराब हो गई है। यहां बार-बार होने वाली आग की घटनाओं से वन क्षेत्र के साथ-साथ सामाजिक आर्थिक संपत्तियों को भी काफी नुकसान होता है। भारत राज्य वन रिपोर्ट ने भी पुष्टि की है कि राज्य में स्थान और समय के साथ जंगल की आग की घटनाओं की संख्या बढ़ रही है।

मप्र के वन क्षेत्रों में विविध आदिवासी समुदाय रहते हैं जो सदियों से प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व में हैं। हालांकि, बढ़ती आग की घटनाएं आजीविका, सांस्कृतिक विरासत और समग्र कल्याण सहित उनके सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों को परेशान कर रही हैं। राज्य के प्रमुख आदिवासी समुदाय, जिनमें गोंड, बैगा और कोरकू शामिल हैं, जंगल के करीब रह रहे हैं और अपने निर्वाह के लिए वन पारिस्थितिकी तंत्र पर अत्यधिक निर्भर हैं। ये समुदाय ज्यादातर गैर-लकड़ी वन उत्पादों (एनटीएफपी) जैसे महुआ के फूल और बीज, आंवला, तेंदू पत्ते, साज, करवा चिराग, बीज, सफेद मूसली, अशोक की छाल, सेमल कपास और शहद पर निर्भर हैं। इसके साथ ही, ईंधन की लकड़ी का संग्रह और चराई भी उनके अस्तित्व का प्रमुख इंजन है। लेकिन जंगल की आग की पुनरावृत्ति इन पारंपरिक प्रथाओं को बाधित करती है, प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट कर देती है और जैव विविधता के साथ-साथ लघु वन उत्पादों की उपलब्धता को भी कम कर देती है।

परिणामस्वरूप, आदिवासी समुदायों को अपनी आर्थिक गतिविधियों के लिए आजीविका, भोजन, चिकित्सा और कच्चे माल को सुरक्षित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। रोजगार के अवसरों के खत्म होने से उनकी असुरक्षा बढ़ जाती है और जीविका के लिए बाहरी स्रोतों पर निर्भरता बढ़ जाती है। जंगलों पर अपनी निर्भरता के अलावा, मप्र में कई आदिवासी समुदाय, विशेष रूप से गोंड और कोरकू, स्थानीय सरकार, निजी धर्मार्थ ट्रस्टों और गैर-लाभकारी संस्थाओं के सहयोग से कृषि और पशुपालन करते हैं। गर्मियों के दौरान, जंगल की आग कृषि क्षेत्रों और चरागाहों तक फैल जाती है, जिससे फसलें और चरागाह नष्ट हो जाते हैं। फसलों का नुकसान न केवल इन समुदायों की खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करता है, बल्कि स्थानीय कृषि अर्थव्यवस्था को भी बाधित करता है, जिससे गरीबी और खाद्य असुरक्षा में वृद्धि होती है।

जनजातीय समुदाय अपनी भूमि से गहराई से जुड़े हुए हैं, अपनी सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों से जटिल रूप से जुड़े हुए हैं। जंगल की आग न केवल भौतिक परिदृश्य को प्रभावित करती है बल्कि पीढ़ियों से चले आ रहे सदियों पुराने ज्ञान को भी नष्ट कर देती है। औषधीय पौधों, पवित्र स्थलों और पारंपरिक कृषि पद्धतियों का नुकसान इन समुदायों के सांस्कृतिक ताने-बाने को बाधित करता है, जिससे उनकी पहचान, आध्यात्मिकता और सामाजिक एकजुटता की भावना प्रभावित होती है। इसके अलावा, जंगल की आग के कारण होने वाले विस्थापन और व्यवधान से पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं और सामुदायिक बंधनों का भी नुकसान होता है, जिससे उनकी सांस्कृतिक लचीलापन और भी कमजोर हो जाती है।

● **धर्मेंद्र सिंह कथूरिया**

अब ऐप की मदद से हो रही मॉनीटरिंग

वन विभाग फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की मदद से दो सैटेलाइट से आगजनी की घटनाओं की लगातार जानकारी हासिल करता है। अधिकारियों का कहना है कि हर दो घंटे में जंगल का डाटा मिलता रहता है। इसके बाद सैटेलाइट इमेज की मदद से संबंधित क्षेत्र में आग को फैलने से रोकने और बुझाने का काम होता है। प्रदेश में जंगलों के आसपास रहने वाले 35 हजार लोगों को जोड़ा गया है। जिन्हें मैसेज भेजकर आग लगने की सूचना दी जाती है। हालांकि, कई मामलों में मैसेज पहुंचने में 6 से 12 घंटे तक का समय लग जाता है। जब तक आग बड़े वन क्षेत्र को नष्ट कर चुकी होती है। हालांकि, अफसरों का दावा है कि इस बार तैयारियां पूरी है। पिछले बार आगजनी के 40 हजार मैसेज आए थे। इस बार सतकर्ता से ये आंकड़ा 15 हजार के आसपास ही रहेंगे। नवंबर से अब तक सिर्फ 11 हजार अलर्ट मैसेज ही आए हैं। 15 मार्च से 15 मई तक सबसे ज्यादा घटनाएं होती हैं। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि हमने 966 लीफ ब्लोअर खरीदे हैं। 40 डिविजन में 45 ड्रोन की मदद से लगातार जंगलों की निगरानी की जा रही है। विभाग के पास 7 हजार फायर बिटर्स भी हैं। ग्रामीणों को रोककर भी आग को रोकने का काम किया जा रहा है। मप्र में आगजनी रोकने को लेकर सबसे अच्छा काम हो रहा है। अब हम पहले से 8वें नंबर पर पहुंच गए हैं। जल्द ही स्थिति ओर बेहतर होगी।

ठिगनी हो रही बुंदेलखंड में नई पीढ़ी

बुंदेलखंड में कुपोषण के गंभीर परिणाम सामने आ रहे हैं, यहां की नई पीढ़ी कम वजन के साथ अब ठिगनी भी हो रही है। बच्चों की औसत ऊंचाई तेजी से घट रही है। दरअसल, कुपोषण के कारण ऐसा हो रहा है। बुंदेलखंड में कुपोषण के गंभीर परिणाम सामने आ रहे हैं। यहां की नई पीढ़ी कम वजन के साथ अब ठिगनी भी हो रही है। बच्चों की औसत ऊंचाई तेजी से घट रही है। छतरपुर में 44768, दमोह में 18751, पन्ना में 7004, सागर में 35970, टीकमगढ़ में 20219 और निवाड़ी में 8645 यानी कुल 135,357 बच्चे कम ऊंचाई वाले मिले हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों और डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय के मानव विज्ञान विभाग के शोध पत्र में यह तथ्य सामने आया है। सागर संभाग के आंगनबाड़ी केंद्रों में जनवरी माह में औसत से कम ऊंचाई वाले बच्चों की संख्या करीब 1 लाख 35 हजार है। जिले में ही करीब 35 हजार बच्चों की ऊंचाई कम है। वृद्धि रुकने से बच्चों का विकास ही नहीं हो रहा है। सामान्य कुपोषण के साथ कम ऊंचाई वाले बच्चों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जिले में करीब 2200 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। जानकारी के अनुसार इन केंद्रों पर दर्ज 35970 बच्चों की ऊंचाई से कम है। केंद्रों पर बच्चों के वजन के साथ ऊंचाई भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नापती हैं।

केंद्रों के साथ डॉ. हरिसिंह गौर विवि के मानव विज्ञान विभाग ने भी स्टंटिंग पर शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं। इससे इस बात का खुलासा हुआ है कि मानक के अनुसार बच्चों की ऊंचाई घट रही है। 0 से 18 वर्ष तक बच्चों की ऊंचाई का अलग-अलग स्टैंडर्ड होता है। उसके मुताबिक सागर में भी बच्चों की ऊंचाई घट रही है। मानव विज्ञान विभाग के प्रो. राजेश गौतम का कहना है कि मानव विज्ञान विभाग के द्वारा स्टंटिंग और वासटिंग (वजन कम होना) दोनों पर अध्ययन किया गया है। इसके शोध पत्र भी प्रस्तुत हुए हैं। जिसमें यह सामने आया है कि 1960-1970 दशक की तुलना में बड़े लोगों की एवरेज ऊंचाई बढ़ी है, लेकिन बच्चों की ऊंचाई घटी है। 5 से 18 साल तक के बच्चों की ऊंचाई कम पाई गई है। बच्चों की वृद्धि रुक रही है। सागर के बच्चों की ऊंचाई पर मैंने शोधपत्र प्रस्तुत किए हैं।

स्वास्थ्य विभाग की क्षेत्रीय संचालक डॉ. ज्योति चौहान के अनुसार महिलाओं में आयरन, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो रही है। गर्भवती होने के तीन माह पहले से ही फोलिक एसिड का प्रयोग करें। उससे बच्चा स्वस्थ होगा। हड्डियों की लंबाई नहीं रुकेगी। दालें, दूध और उससे बने उत्पाद नहीं खाती हैं। शासन द्वारा 1000 मिलीग्राम आयरन की गोलियां भी दी जाती हैं। कई महिलाएं समय पर वे गोलियां भी नहीं खाती हैं। खानपान में पोषक तत्वों की कमी से कुपोषण बढ़ रहा है। महिला बाल विकास जिला कार्यक्रम अधिकारी ब्रजेश त्रिपाठी का कहना है कुपोषण तीन प्रकार से होता है। कम वजन वाले बच्चों को हम कुपोषित होने से रोकने के लिए अच्छा खाना खिला सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों की ऊंचाई कम मिल रही है उसे जल्दी नहीं बढ़ाई जा सकती हैं। यही वजह है कि स्टंटिंग कुपोषण के मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसके लिए गर्भावस्था के साथ ही माताओं को ध्यान रखना होगा। खानपान में पोषक तत्वों की कमी इसकी प्रमुख वजह है। इसके अलावा ऊंचाई कम होने का कारण आनुवांशिक भी है।

दमोह जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में औसत से कम ऊंचाई वाले बच्चों की संख्या करीब 18 हजार 751 है। वृद्धि रुकने से बच्चों का विकास ही नहीं हो रहा है, सामान्य कुपोषण के साथ कम ऊंचाई वाले बच्चों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जिले में करीब एक हजार 742 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जानकारी अनुसार इन केंद्रों में दर्ज 18 हजार 751 बच्चों की ऊंचाई से कम है। केंद्रों पर बच्चों की वजन के साथ ऊंचाई भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नापती हैं, स्वास्थ्य विभाग अनुसार बच्चों की ऊंचाई लगातार घट ही रही है। 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों की ऊंचाई का अलग-अलग स्टैंडर्ड होता है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अनुसार जिले में भी बच्चों की ऊंचाई लगातार घट रही है। महिला बाल विकास की प्रभारी अधिकारी संजीव मिश्रा का कहना है कि कुपोषण तीन प्रकार से होता है। कम वजन वाले बच्चों को हम कुपोषित होने से रोकने के लिए अच्छा खाना खिला सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों की ऊंचाई कम मिल रही है। उसे जल्दी नहीं बढ़ाई जा सकती यही वजह है कि स्टार्टिंग कुपोषण के मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसके लिए गर्भावस्था के साथ ही माता को ध्यान रखना होगा, खानपान में पोषक तत्वों की कमी इसकी प्रमुख वजह है। इसके अलावा ऊंचाई कम होने का कारण अनुवांशिक भी है।

● **सिद्धार्थ पांडे**

कुपोषण के लिए रामबाण है बुंदेलखंड का कठिया गेहूं

उप्र के बुंदेलखंड क्षेत्र में कठिया गेहूं का दायरा हर साल अब घट रहा है। इस बार हमीरपुर जिले में ही चार फीसदी से भी कम किसानों ने ही कठिया गेहूं की खेती की है जबकि पूरे क्षेत्र में कठिया गेहूं की खेती करने वाले किसानों में भारी गिरावट आई है। चिकित्सकों के मुताबिक इस गेहूं का दलिया न सिर्फ कुपोषण के लिए रामबाण है बल्कि पेट संबंधी तमाम बीमारियां भी इसके सेवन से छूमंतर हो जाती है। बुंदेलखंड के हमीरपुर, महोबा, जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट और बांदा के अलावा मप्र के तमाम इलाकों में किसी जमाने में किसानों की पहली पसंद कठिया गेहूं की खेती थी लेकिन पिछले कुछ दशकों से यह खेती करने वाले किसानों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। हमीरपुर जिले के सुमेरपुर, कुरारा, सरीला और मौदहा क्षेत्र के ज्यादातर गांवों में किसानों के लिए कठिया गेहूं की खेती बड़ी मुफीद थी। बाजार में भी इसकी डिमांड ज्यादा होने के कारण कठिया गेहूं की खेती बड़े क्षेत्रफल में होती थी लेकिन उपज कम मिलने के कारण किसानों ने इसकी खेती का दायरा अब सीमित कर रखा है। बुंदेलखंड की ऊबड़-खाबड़ जमीन में कठिया गेहूं की खेती में कोई लागत नहीं लगती है। सिंचाई से वंचित भूमि में इसकी खेती होती है। ये आम गेहूं की तरह होता है लेकिन पिसने के बाद इसमें लालिमा रहती है। इसकी बनी रोटी का अलग ही स्वाद होता है मगर ज्यादातर लोग दलिया खाना पसंद करते है। जिला कृषि अधिकारी सरस कुमार तिवारी का कहना है कि मौजूदा स्थिति में जिले के सरीला, कुरारा और सुमेरपुर क्षेत्र में ही करीब पांच हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में ही किसान कठिया गेहूं की खेती कर रहे है।

मिशन 2024 का घमासान
भ्रष्टाचार बनाम... सियासी अत्याचार!

तारीखों के ऐलान के साथ ही अब लोकसभा का समर और गरमा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार और उनकी पार्टी भाजपा भ्रष्टाचार पर और वार के लिए 'मोदी सरकार तीसरी बार' का नारा बुलंद कर रही है। वहीं कांग्रेस समर्थित इंडिया गठबंधन मोदी सरकार के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान (ईडी, सीबीआई और आईटी के छापों) को सियासी अत्याचार बताकर जनता से सरकार बदलने की गुहार लगा रही है। एक तरफ भाजपा का दावा है कि मोदी सरकार ने 'अमृतकाल' में सुशासन, तेज गति से विकास और भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण का आश्वासन दिया है तो वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस ने मोदी सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल पर सवाल उठाए हैं।

● राजेंद्र आगाल

लोकसभा के चुनावी रण का शंखनाद हो गया है। 543 सीटों के लिए चुनाव सात फेज में होगा। लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामांकन शुरू हो चुके हैं और साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए होने वाली खेमेबंदी लगभग पूरी हो चुकी है। वादों के दांव चले जा रहे हैं, एक-एक सीट पर रणनीति की बिसात बिछाई जा रही है। सत्ताधारी भाजपा ने अबकी बार, 400 पार का नारा दिया है। विपक्षी कांग्रेस नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को जीत की हैट्रिक लगाने से रोकने के लिए पूरा जोर लगा रही है। आरोप और प्रत्यारोप के बीच यह चुनाव भ्रष्टाचार बनाम सियासी अत्याचार पर आकर अटक गया है। पूरा चुनाव प्रचार मोदी बनाम मुद्दों पर सिमटता जा रहा है। एनडीए मोदी की गारंटी को भुनाने पर जोर दे रही है। इस कारण 18वीं लोकसभा का यह चुनाव मोदी की गारंटी बनाम राहुल की न्याय गारंटी हो गया है।

मिशन 2024 के लिए भाजपानीत एनडीए ने 400 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य बनाया है। गौरतलब है कि पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा को 37.7 फीसदी वोट शेयर के साथ 303 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस ने 19.7 फीसदी वोट शेयर के साथ 52 और अन्य ने 30.9 फीसदी वोट शेयर के साथ 116 सीटें जीती थीं। अन्य में उप्र की सपा-बसपा, ओडिशा की बीजेडी, तेलंगाना में बीआरएस और केरल में लेफ्ट की जीती सीटों का आंकड़ा भी शामिल है। कांग्रेस ने भाजपा का विजयरथ रोकने के लिए उप्र और बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक, क्षेत्रीय क्षत्रपों से हाथ मिला लिया है और पार्टी को उम्मीद है कि यह गठबंधन एनडीए का विजयरथ रोकने में सफल रहेगा। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या गठबंधनों के गणित से ही कांग्रेस भाजपा का विजयरथ रोक लेगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सत्ताधारी एनडीए गठबंधन में विपक्षी इंडिया गठबंधन के दो क्षत्रप नीतीश कुमार और जयंत चौधरी के शामिल होने के साथ भाजपा को भरोसा है कि बिहार और पश्चिमी उप्र में अपने सियासी किले सेंधमारी का जो खतरा था, उसे रोकने में पार्टी को कामयाबी मिल गई। उधर नीतीश और जयंत के पाला बदल से लड़खड़ाया इंडिया गठबंधन शुरुआती झटकों के बाद अब फिर खड़ा होकर मैदान में मुकाबले के लिए डट गया है। आम आदमी पार्टी के सांसद और जुझारू नेता संजय सिंह की जमानत होने और उनके जेल से बाहर आने से भी विपक्ष को राहत और नई ताकत मिली है। इसी दौरान कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र जिसे पार्टी ने न्याय पत्र का नाम दिया है, अपने पांच न्याय के जरिए 25 गारंटियों के वादे के साथ जनता के सामने नए सपने रखे हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों का जवाब माना जा सकता है।

विपक्षी दिख रहे एकजुट

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारियों ने विपक्षी गठबंधन के घटक दलों जो कुछ दिनों तक आपस में ही सिर फुटौव्वल में जुटे थे, को एकजुट कर दिया है। इसका सबसे बड़ा सबूत और संकेत 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई इंडिया गठबंधन की सफल रैली है। इस रैली में इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने सरकार पर विपक्ष पर अत्याचार और प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा एकतरफा चुनाव चाहती है। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उप्र के मेरठ में अपनी पहली चुनावी रैली में विपक्षी नेताओं को निशाने पर लेते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी मुहिम जारी रहेगी और कोई भी भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। इस तरह दोनों ही खेमों ने लोकसभा चुनाव के अपने-अपने केंद्रीय मुद्दे तय कर लिए हैं। जहां सत्तापक्ष विपक्षी नेताओं को भ्रष्टाचारी बताते हुए उनके कथित भ्रष्टाचार को केंद्रीय मुद्दा बना रहा है तो वहीं विपक्षी गठबंधन अपने नेताओं के खिलाफ होने वाली ईडी, सीबीआई, आयकर की कार्रवाई और गिरफ्तारियों को विपक्ष पर सरकार के कथित अत्याचार को प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाकर जनता की सहानुभूति जुटाने की कोशिश में जुट गया है। जेल से बाहर आते ही जिस तरह आप नेता संजय सिंह सक्रिय हुए हैं और उन्होंने मीडिया के जरिए भाजपा और मोदी सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं, उससे साफ जाहिर है कि जैसे-जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा विपक्ष और सत्तापक्ष के बीच लड़ाई और धारदार होती जाएगी।

चुनाव आते ही नेताओं का दल बदलना आम बात है। लेकिन इस बार कांग्रेस के नेताओं का एक के बाद एक भाजपा में जाना सत्तापक्ष की एक सुनियोजित रणनीति है। इसीलिए मप्र वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी, बॉक्सर विजेंद्र सिंह, प्रखर प्रवक्ता गौरव वल्लभ और संजय निरुपम जैसे नेताओं का पार्टी से अलग होना और ज्यादातर का भाजपा में शामिल होना कांग्रेस को असहज तो करता ही है, लेकिन कांग्रेस ने भी भाजपा के तीन निवर्तमान सांसदों और अन्य कुछ महत्वपूर्ण नेताओं को कांग्रेस में शामिल करके जवाब देने की कोशिश की है। एनडीए और इंडिया गठबंधनों में शुरुआती खींचतान के बाद राज्यों में सीटों का बंटवारा लगभग हो गया है। भाजपा ने उप्र-बिहार में अपने सहयोगी दलों के साथ सीटें बांट ली हैं तो कांग्रेस ने भी दिल्ली, उप्र, बिहार, तमिलनाडु, झारखंड में अपने सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे पर सहमति बना ली है, लेकिन महाराष्ट्र में अभी दोनों ही गठबंधनों के सामने सीट बंटवारे में पेंच हैं। नीतीश कुमार और जयंत चौधरी के जाने से इंडिया गठबंधन को जो झटका लगा था, उससे अब वह उबर चुका है क्योंकि इनके अलावा कोई और बड़ा सहयोगी गठबंधन से बाहर नहीं गया। यहां तक कि पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने वाली तृणमूल कांग्रेस ने भी खुद को इंडिया गठबंधन से अलग नहीं किया और न ही केरल व पंजाब में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे वाम मोर्चे और आम आदमी पार्टी भी इंडिया गठबंधन में बने हुए हैं। इसका सबूत 31 मार्च को रामलीला मैदान में हुई विपक्ष की रैली में इंडिया गठबंधन

भाजपा को बड़ी जीत के साथ वापसी का भरोसा

भाजपा के घोषणापत्र से बहुत लोगों को निराशा हुई है। इसमें कोई फायरवर्क नहीं है। कोई धूम-धड़ाका नहीं है। चौंकाने वाला कोई बड़ा वादा नहीं है। मुफ्त की रेवड़ी वाली कोई नई घोषणा नहीं है। कांग्रेस का घोषणापत्र जारी होने के 10 दिन बाद जारी होने के बावजूद इसमें कांग्रेस के वादों का जवाब देने की इच्छा नहीं दिखती है। कोई भावनात्मक मुद्दा नहीं है। न एनआरसी का जिक्र है और न मथुरा, काशी की चर्चा है। बड़े वादों में से एक समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को दोहराया गया है। लेकिन इसे भी नया नहीं कहा जा सकता है क्योंकि भाजपा की उत्तराखंड सरकार ने इसे लागू कर दिया है और असम सरकार भी इसे लागू करने वाली है। इसलिए यह पहले से माना जा रहा था कि फिर से केंद्र में भाजपा की सरकार बनेगी तो वह इसे पूरे देश में लागू करेगी। सो, भाजपा का 78 पन्नों का घोषणापत्र देखकर कहा जा सकता है कि यह बहुत सीधा सपाट एक दस्तावेज है, जिसमें राजनीति कम और सरकारी कामकाज की झलक ज्यादा है। ऐसा लग रहा है कि भाजपा ने जान-बूझकर इस तरह का दस्तावेज तैयार कराया है, जिससे आम लोगों में यह मैसेज जाए कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पहले से जो काम कर रही है उन्हें आगे भी जारी रखा जाएगा और घोषणापत्र में जो भी वादे किए गए हैं उनको पूरा किया जाएगा।

के सभी घटक दलों के नेताओं का शामिल होना है। इस रैली ने विपक्ष को हौंसला और हिम्मत दोनों दी है, लेकिन चुनाव प्रचार में भाजपा विपक्ष के मुकाबले खासी आगे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उप्र, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मप्र के साथ-साथ दक्षिण भारत के तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के तूफानी दौरे लगातार कर रहे हैं।

भाजपा का लक्ष्य 370

भाजपा की पूरी कोशिश है कि 2019 के चुनावों में जिन राज्यों में उसने शानदार प्रदर्शन किया था, उसे वह बरकरार रखते हुए उन राज्यों में जहां पिछली बार उसे कामयाबी नहीं मिली थी, वहां अपनी सीटों में इजाफा करे। उप्र, मप्र, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, और पूर्वोत्तर के राज्यों तथा दक्षिण में कर्नाटक में भाजपा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। उसके सामने इन राज्यों में पिछला प्रदर्शन बनाए रखने की चुनौती है। जबकि तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना जैसे राज्यों में उसे अपनी सीटें बढ़ानी होंगी, तब ही वह अपने घोषित लक्ष्य 370 के आसपास पहुंच सकेगी और एनडीए के 400 पार का नारा भी तभी फलीभूत हो सकता है, जब भाजपानीत एनडीए कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक अपना परचम फहराए। इसलिए भाजपा का पूरा ध्यान दक्षिण भारत विशेषकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और तेलंगाना पर है। आंध्र प्रदेश में भाजपा ने पुरानी सहयोगी तेलुगू देशम के साथ चुनावी समझौता कर लिया है।

2019 में चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए से अलग राह पकड़ी और उन्होंने कांग्रेस के साथ समझौता करके चुनाव लड़ा। लेकिन कामयाबी वाईएसआर कांग्रेस को मिली। भाजपा को तब इस दक्षिणी राज्य में एक भी लोकसभा सीट नहीं मिली और उसका मत प्रतिशत भी कोई उल्लेखनीय नहीं था। जबकि तेलंगाना में भाजपा के चार सांसद जीते थे। भाजपा की कोशिश चंद्रबाबू नायडू की मदद से आंध्र में लोकसभा की कुछ सीटें जीतने और तेलंगाना में अपनी सीटें बढ़ाने पर है। इसी तरह केरल में भाजपा मोदी के नाम और कुछ नामी गिरामी चेहरों को मैदान में उतारकर कुछ कमाल करना चाहती है। धुर दक्षिण के इस राज्य में भाजपा का मत प्रतिशत तो बढ़ सकता है लेकिन कोई सीट पार्टी जीत सकती है इसकी संभावना बेहद कम है। तमिलनाडु में पहली बार भाजपा अपने दम और कुछ आंचलिक दलों के साथ चुनाव मैदान में है। लंबे समय तक एनडीए में उसकी सहयोगी रही अन्ना द्रमुक के साथ इस बार उसका गठबंधन नहीं है। भाजपा के बेहद मुखर प्रदेश अध्यक्ष अन्ना मलाई की तेजी अन्ना द्रमुक को रास नहीं आ रही थी और जब उन्होंने द्रविड़ राजनीति के संस्थापक नेताओं के खिलाफ बयानबाजी की तो अन्ना द्रमुक जो पहले से ही सनातन को लेकर भाजपा की **आक्रामक लाईन** से असहज थी, ने एनडीए से नाता तोड़ लिया। तमिलनाडु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंडे पर लंबे समय से है।

इसीलिए जब दिल्ली में नए संसद भवन के शीर्ष पर अशोक चिन्ह स्थापित किया गया तो उस समारोह का अनुष्ठान दक्षिण भारत (तमिलनाडु) के आचार्यों ने संपन्न कराया। अपने संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने काशी तमिल संगम का आयोजन करके भी तमिलनाडु को संबोधित किया। फिर संसद के नए भवन में तमिल गौरव के प्रतीक चोल साम्राज्य के राजेंद्र चोल के राजदंड सेंगोल को तमिल संतों की उपस्थिति में स्थापित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामेश्वरम से लेकर दक्षिण भारत के अनेक मंदिरों में दर्शन, पूजन-अर्चन करना भी दक्षिण भारत विशेषकर तमिलनाडु की जनभावनाओं को संतुष्ट करना था। हाल ही में अन्ना मलाई द्वारा सूचना अधिकार कानून के

विपक्ष के सामने चुनौतियां

लोकसभा की देश में कुल 543 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। इनमें राजस्थान, मप्र, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों को मिलाकर लगभग दो सौ सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा और कांग्रेस की सीधी फाइट है। 2014 और 2019 के चुनाव नतीजे देखें तो भाजपा पिछले दोनों चुनावों में इनमें से करीब 90 फीसदी सीटें जीतने में सफल रही है। कांग्रेस के सामने इन सीटों पर स्ट्राइक रेट सुधारने, वोट शेयर बढ़ाने की चुनौती है। पिछले चुनाव में भाजपा की जीती 40 सीटों पर हार-जीत का अंतर 50 हजार वोट से कम रहा था। इन 40 में से 11 सीटें भाजपा और कांग्रेस की सीधी फाइट वाली थीं। कांग्रेस अगर तीसरी बार मोदी सरकार के सपने को डेंट करना चाहती है तो उसे सीधी फाइट वाली इन सीटों पर स्ट्राइक रेट में सुधार करना होगा और विनिंग परसेंटेज बढ़ाना होगा। 2019 में 207 सीटें ऐसी थीं जहां कांग्रेस को 30 फीसदी या उससे अधिक वोट मिले थे। पार्टी को इन सीटों पर स्ट्राइक रेट सुधारना होगा। भाजपा को हिंदी पट्टी के उप्र, उत्तराखंड, राजस्थान, मप्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 50 फीसदी या उससे अधिक वोट मिले थे। इन राज्यों में कांग्रेस के सामने अपना वोट शेयर बढ़ाने की चुनौती है। उप्र में कांग्रेस ने इसी रणनीति के तहत सपा से हाथ मिलाया है जिससे विपक्ष का वोट न बंटे। कांग्रेस की उम्मीदों को पर तभी लग सकते हैं जब पार्टी इन राज्यों में अपना, गठबंधन सहयोगियों का वोट शेयर बढ़ाने में सफल रहे और भाजपा का वोट शेयर-सीटें घटे। कांग्रेस उप्र, बिहार, मप्र और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में एक-एक, पश्चिम बंगाल में दो सीटों पर सिमट गई थी। पार्टी राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में भी खाता तक नहीं खोल पाई थी। पार्टी के लिए इन राज्यों में खाता तक नहीं खोल सकी थी। इन राज्यों में कांग्रेस को अपना प्रदर्शन सुधारना होगा। कांग्रेस को छिटके वोटबैंक को फिर से अपने पाले में लाना होगा। सवर्ण, दलित, आदिवासी, पिछड़ा और अल्पसंख्यक कभी कांग्रेस का बेस वोटर हुआ करते थे जो अब अलग-अलग पार्टियों के साथ जा चुके हैं। कांग्रेस पुराना वोटबैंक फिर साथ ला पाती है तो उत्तर से पूर्वोत्तर तक उसके अधिक सीटों पर जीत की उम्मीदें मजबूत हो सकती हैं। पूर्वोत्तर भारत में लोकसभा की 25 सीटें हैं और इनमें से कांग्रेस के पास चार सीटें हैं।

तहत निकलवाई गई जानकारी कि किस तरह 1974-75 में इंदिरा गांधी की सरकार ने कच्चाईतिवू द्वीप को श्रीलंका को सौप दिया, को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश भी प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा कर रही है। प्रधानमंत्री इसे भाजपा के राष्ट्रवादी एजेंडे से जोड़कर कांग्रेस के साथ-साथ तत्कालीन द्रमुक सरकार को भी जिम्मेदार ठहराकर द्रमुक को भी घेर रहे हैं। हालांकि द्रमुक नेताओं ने इसका करारा जवाब देते हुए सवाल किया है कि मोदी के लिए अगर यह मुद्दा इतना अहम है तो पिछले दस साल से उनकी सरकार ने कच्चाईतिवू वापस लेने के लिए क्या किया? कांग्रेस ने भी कच्चाईतिवू के बदले भारत को हजारों समुद्री मील में मिले मछली शिकार अधिकार का हवाला देकर 2015 में इस मामले में आरटीआई के तहत विदेश मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी भी साझा करके जवाब दिया है। साथ ही कांग्रेस ने 2015 में भारत द्वारा बांग्लादेश को सीमा विवाद समाधान के लिए 50 एन्क्लेव के बदले 150 एन्क्लेव देने का मुद्दा भी उठाया है।

कुल मिलाकर कच्चाईतिवू का मुद्दा वैसा जोर नहीं पकड़ सका जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी को उम्मीद थी। इसलिए भाजपा को राष्ट्रवाद के मुद्दे से फिर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लौटना पड़ा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि भाजपा के सुपर स्टार प्रचारक हैं और जिनकी लोकप्रियता और विश्वसनीयता भाजपा व एनडीए की सबसे बड़ी ताकत है, अपने हर भाषण में विपक्षी नेताओं को भ्रष्टाचारी बताते हुए कह रहे हैं कि वह जनता के पैसों की लूट का पूरा हिसाब लेंगे और किसी भी भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं। यह पहली बार है कि कोई सरकार विपक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, वरना हमेशा हर चुनाव में सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन चुनाव बॉन्ड को अवैधानिक बताने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इनके जरिए हुए हजारों करोड़ रुपए के लेनदेन की जानकारी सार्वजनिक होने के बाद विपक्ष को सरकार पर हमला करने का एक नया हथियार मिल गया है। हालांकि भाजपा इसे यह कहकर कि चुनाव बॉन्ड का पैसा सबने लिया है, अपने ऊपर होने वाले हमलों की धार कुंद कर रही है, लेकिन विपक्ष चुनावी बॉन्ड के जरिए भाजपा को मिले चंदे के बदले चंदा देने वालों को दी गई राहत और लाभ का मुद्दा उठाकर सरकार को घेर रहा है। साथ ही विपक्ष लगातार भाजपा नेताओं और भाजपा के साथ आने वाले नेताओं के ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को गिनाते हुए प्रधानमंत्री मोदी के तीखे हमलों का जवाब देने की कोशिश कर रहा है। इस घमासान से भ्रष्टाचार का मुद्दा चुनाव में केंद्रीय मुद्दा बनने की बजाय आरोप-प्रत्यारोप का दलदल बनकर रह गया है।

साउथ में मोदी बनाम राहुल

कर्नाटक में कांग्रेस और भाजपा के बीच वोटों की जंग जारी है, इस बीच कर्नाटक में चुनाव प्रचार करने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी पर ग्रामीण विकास मंत्री प्रियांक खरगे ने जमकर निशाना साधा। प्रियांक खरगे ने कहा कि मोदी प्रधानमंत्री नहीं बल्कि प्रचार मंत्री है। खरगे के अपमान पर मोदी कैबिनेट के मंत्री प्रह्लाद जोशी भड़क गए हैं। जोशी इस बात से नाराज हैं कि प्रियांक खरगे पब्लिसिटी के लिए मोदी के खिलाफ बातें कर रहे हैं। साउथ में भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी जंग जारी है, जिसके चलते जहां 14 अप्रैल को महा रैली की गई, तो राहुल गांधी 17 अप्रैल को मेगा रोड शो करेंगे। इसी के चलते दोनों खेमों में वार पलटवार जारी है। पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से पूछा है कि मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री क्यों बनना चाहिए और मोदी के चेहरे पर वोट क्यों देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को ओल्ड मैसूर में महा रैली की। मोदी ने मैसूर के महाराजा कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित किया। जिसके बाद वो मैसूर से मैंगलोर के लिए रवाना हुए और तट पर एक मेगा रोड शो किया। प्रधानमंत्री मोदी के कर्नाटक पहुंचने के 3 दिन के अंदर ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी कर्नाटक के कोलार में 17 अप्रैल को मेगा शो करेंगे। 17 अप्रैल को राहुल गांधी कोलार और चीनी बीडू मांड्या में चुनाव प्रचार करेंगे। बता दें, दक्षिण भारत में 130 सीटें जीतने और दक्षिण का मुखिया बनने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व वाले भारत गठबंधन और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के बीच महासंग्राम शुरू हो गया है।

कांग्रेस की 25 गारंटियां

इधर कांग्रेस ने बेहद महत्वाकांक्षी घोषणापत्र जारी किया, जिसमें अपनी सरकार बनने पर पांच न्याय के तहत 25 गारंटियों के जरिए अनेक लोकलुभावन घोषणाएं की गई हैं। लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा हमला बोलते हुए इस पर आजादी के पहले वाली मुस्लिम लीग की छाप बताया है। इससे तिलमिलाई कांग्रेस ने भी जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी और मुस्लिम लीग के रिश्तों का इतिहास गिना दिया है। जिस तरह सत्ताधारी एनडीए गठबंधन का पूरा दारोमदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धुआंधार प्रचार पर केंद्रित होता जा रहा है, जबकि विपक्षी इंडिया गठबंधन व्यक्ति से ज्यादा मुद्दों पर जोर दे रहा है, उससे 2024 का लोकसभा चुनाव धीरे-धीरे मोदी बनाम मुद्दे बनता जा रहा है। सत्तापक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, विश्वसनीयता, उनकी वैश्विक छवि, भारत को विश्वगुरु बनाने और भारतीय अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर की करते हुए विश्व में तीसरे नंबर पर लाने का मोदी का सपना और मजबूत नेतृत्व पर विपक्ष को घेर रहा है तो वहीं विपक्ष बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की दशा, महिला सुरक्षा, जातीय जनगणना, अग्निवीर आदि मुद्दों को आगे करके सरकार पर हमलावर है। अब नतीजे बताएंगे कि जनता ने मोदी का चेहरा स्वीकार किया या फिर मोदी पर विपक्ष के मुद्दे भारी पड़े।

चुनाव में हावी ये मुद्दे

चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही अब लोकसभा का समर और गरमा गया है। एक तरफ भाजपा का दावा है कि मोदी सरकार ने

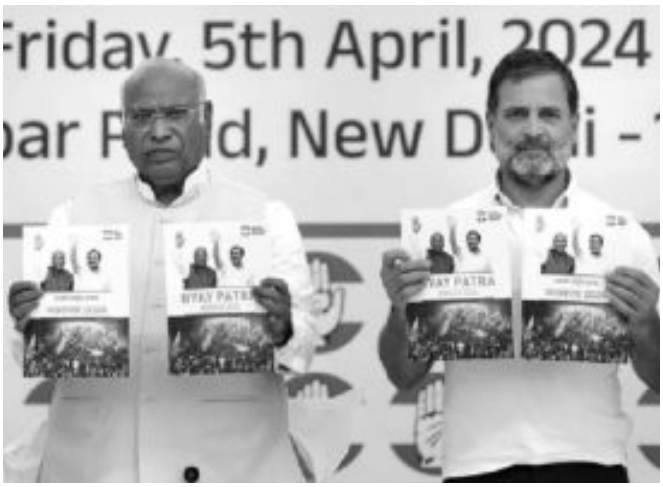

अमृतकाल में सुशासन, तेज गति से विकास और भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण का आश्वासन दिया है तो वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस ने मोदी सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल पर सवाल उठाए हैं। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव में कई ऐसे मुद्दे हैं जो हावी रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री अपनी हैट्रिक के लिए पूरी तरह से विश्वास से भरे हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने मोदी की गारंटी को अपने अभियान का मुख्य विषय बनाया है। नरेंद्र मोदी की वेबसाइट पर भी मोदी की गारंटी को विस्तृत तरीके से बताया गया है। इसमें कहा गया है कि ये युवाओं के विकास, महिलाओं के सशक्तिकरण, किसानों के कल्याण और उन सभी हाशिये पर पड़े व कमजोर लोगों के लिए एक गारंटी है जिन्हें दशकों से नजरअंदाज किया गया है। देश की सबसे पुरानी पार्टी को हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के राज्य चुनावों में उस समय फायदा मिला, जब उसने लोगों को गारंटी दी। लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी ने अपनी 5 न्याय गारंटी सामने रखी है, जिसका उद्देश्य युवाओं, किसानों, महिलाओं, मजदूरों के लिए न्याय सुनिश्चित करना और साथ ही सहभागी न्याय सुनिश्चित करना है। मणिपुर से मुंबई तक राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लोगों के सामने न्याय की गारंटी पेश की गई है।

कांग्रेस का घोषणापत्र इन गारंटियों के इर्द-गिर्द तैयार किए जाने की संभावना है और पार्टी अपना अभियान इन्हीं गारंटियों के इर्द-गिर्द तैयार करेगी। हालांकि इसका कितना फायदा पार्टी को मिलेगा, यह तो समय ही बताएगा। कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन में शामिल विपक्षी पार्टियां बेरोजगारी और आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों का मुद्दा उठाती रही हैं। उन्होंने बार-बार कहा है कि नौकरियों की कमी सबसे बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की गई। वहीं पेट्रोल-डीजल के दाम हो या फिर रोजमर्रा का सामान, इनकी कीमतों को लेकर भी मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर रही है। हालांकि भाजपा ने रोजगार वृद्धि और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का हवाला देते हुए पलटवार भी किया है। चुनावी मौसम में बेरोजगारी और महंगाई भी बड़े मुद्दे हैं। अनुच्छेद 370, सीएए और समान नागिरक संहिता भाजपा के लोगों के बीच किए गए वादों में से हैं। भाजपा ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के कार्यान्वयन और जम्मू-कश्मीर के लिए अनुच्छेद 370 को निरस्त करके अपने वादे पूरे कर दिए हैं। वहीं सीएए को भी लागू कर दिया गया है। इन्हें पार्टी ने समय-समय पर मुद्दा बनाया है और इस चुनाव में भाजपा इन मुद्दों को भुनाने में जुटी है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो चुका है। अन्य राज्यों पर बातचीत जारी है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह को भाजपा ने जबरदस्त उत्साह के साथ मनाया। समारोह का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ-साथ उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतीकवाद किसी से भी छिपा नहीं था। भाजपा नेताओं ने सदियों पुराने सपने को साकार करने का श्रेय प्रधानमंत्री को दिया है। इस अवसर पर हिंदी भाषी क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में भगवा झंडे फहराए गए, इसका प्रभाव हर किसी पर महसूस किया जा सकता है। यहां तक कि विपक्षी नेता भी मानते हैं कि राम मंदिर से भाजपा को उत्तर भारत में फायदा हुआ है। विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा को कम से कम 370 सीटें मिलने का ज्यादातर भरोसा इसी राम मंदिर लहर से उपजा है।

सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद एसबीआई द्वारा उपलब्ध कराए जाने पर चुनाव आयोग ने चुनावी बॉन्ड पर डेटा सार्वजनिक कर दिया है। कांग्रेस ने चुनावी बॉन्ड योजना में कथित भ्रष्टाचार के लिए सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से उच्च स्तरीय जांच और उसके बैंक खातों को फ्रीज करने की मांग की है। चुनाव से ठीक पहले यह मुद्दा सामने आया है और विपक्ष ने इसे लपक लिया है, लेकिन यह जमीनी स्तर पर काम करेगा या नहीं, यह अभी भी देखना बाकी है। हालांकि, यह निश्चित रूप से अभियान के दौरान चर्चा के बड़े विषयों में से एक होगा।

फीका दिख रहा है चुनावी प्रचार

सूरज की तपिश बढ़ने के साथ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश में सियासी माहौल गर्म हो रहा है। लेकिन पिछले 17 लोकसभा चुनावों की अपेक्षा इस बार चुनावी माहौल बिलकुल ठंडा पड़ा है। न सत्तारूढ़ भाजपा और न ही इंडिया गठबंधन चुनावी माहौल बना पाए हैं। जहां चुनावी सभाएं हो रही हैं वहां आरोपों की बौछार की जा रही है, लेकिन चुनावी रंगत गायब है। राजनीतिक पार्टियों द्वारा भाड़े की भीड़ जुटाकर चुनावी सभाएं की जा रही हैं। लेकिन मैदान में चुनावी माहौल पूरी तरह फीका पड़ा हुआ है। जबकि इस बार के चुनाव में 96.8 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। पहले फेज में 102 सीटों पर वोटिंग होगी। ये निर्वाचन क्षेत्र 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत आते हैं। इनमें से अधिकांश सीटें तमिलनाडु (39) में हैं। जबकि राजस्थान की 12 सीटें पर, उप्र की 8 सीटों पर, मप्र की 6, असम की 5, उत्तराखंड की 5 और महाराष्ट्र की 5 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग होगी। लेकिन विडंबना यह है कि बिहार, उप्र झारखंड, गुजरात, हरियाणा जैसे राज्यों में चुनाव प्रचार ने अभी जोर नहीं पकड़ा है। इसके विपरीत तमिलनाडु, मप्र, और पश्चिम बंगाल में प्रचार सबसे अधिक जोरों पर है।

चुनावों में बढ़ेगा काला धन

केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने वित्त वर्ष 2022-23 में चुनावी बॉन्ड के जरिए करीब 1,300 करोड़ रुपए का राजनीतिक चंदा जुटाया है। यह राशि इसी अवधि में चुनावी बॉन्ड के जरिए कांग्रेस को मिले चंदे की तुलना में सात गुना अधिक है। चुनावी बॉन्ड के विवरण को सार्वजनिक करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से केंद्र सरकार के साथ चंदा देने वाले उद्योगपतियों को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। चुनावी बॉन्ड की खरीद के तहत सर्वाधिक चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने वित्त वर्ष 2022-23 में चुनावी बॉन्ड के जरिए करीब 1,300 करोड़ रुपए का राजनीतिक चंदा जुटाया है। यह राशि इसी अवधि में चुनावी बॉन्ड के जरिए कांग्रेस को मिले चंदे की तुलना में सात गुना अधिक है। कांग्रेस को चुनावी बॉन्ड के जरिए 171 करोड़ रुपए की आय हुई, जो वित्त वर्ष 2021-22 में 236 करोड़ रुपए से कम है। राज्य स्तर पर समाजवादी पार्टी को 2021-22 में चुनावी बॉन्ड के जरिए 3.2 करोड़ रुपए की आय हुई थी लेकिन 2022-23 में उसे इन बॉन्ड के जरिए कोई धनराशि नहीं मिली। वहीं, राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त एक अन्य दल तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) को 2022-23 में चुनावी बॉन्ड के माध्यम से 34 करोड़ रुपए मिले, जो पिछले वित्त वर्ष से 10 गुना अधिक राशि है।

ऐसा नहीं है कि एसबीआई के लिए बॉन्ड की जानकारी का खुलासा करना कोई बहुत कठिन काम हो। एसबीआई चाहे तो 24 घंटे में जानकारी को मुहैया करा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने अर्जी दाखिल करके बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक करने के लिए 30 जून तक समय मांगा है। दरअसल इस बीच लोकसभा चुनाव संपन्न हो जाएंगे। इसके बाद केंद्र की भाजपा सरकार को मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इससे पहले चुनावी बॉन्ड का खुलासा होने पर सर्वाधिक समस्या बॉन्ड के रूप में चंदा देने वाले उद्योगपतियों और व्यवसायियों को करना पड़ेगा। भाजपा को चूंकि सर्वाधिक चंदा मिला है, ऐसे में बॉन्ड के खरीददार कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के निशाने पर रहेंगे। विशेषकर जिन राज्यों में कांग्रेस और गैर भाजपा दलों की सरकारें हैं, उनमें बॉन्ड खरीददारों को सत्तारुढ़ दलों के कोपभाजन का निशाना बनना पड़ सकता है। राजनीतिक दुर्भावना की नीयत से इनके खिलाफ कार्रवाई करने में विपक्षी दल कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। गौरतलब है कि राहुल गांधी और विपक्षी पार्टी के नेता पहले ही अडानी और अंबानी को घेरे हुए हैं। यही वजह है कि एसबीआई गले पड़ी इस मुसीबत को टालने के लिए 30 जून तक का समय मांग रही है। इस अवधि के बाद केंद्र की भाजपा सरकार को किसी बात का डर नहीं रहेगा। भाजपा को पूरी उम्मीद है कि फिर केंद्र में सरकार उसकी ही बनेगी। सरकार बनने के बाद भाजपा के बॉन्ड के खरीददारों को सुरक्षा देने में केंद्र सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। लेकिन इससे पहले यदि इनके नामों का खुलासा किया गया तो निश्चित तौर पर राज्यों के सत्तारूढ़ विपक्षी दल खरीददारों को बख्शेंगे नहीं। कारण स्पष्ट है कि भाजपा की तुलना कांग्रेस को बेहद कम और अन्य दलों को अल्पमात्र चंदा मिला है।

पिछले महीने, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच- न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था और एसबीआई को राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि जानकारी में नकदीकरण की तारीख और बॉन्ड के मूल्यवर्ग को शामिल किया जाना चाहिए और 6 मार्च तक चुनाव पैनल को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आदेश दिया था कि वह इन बॉन्डों को जारी करना बंद कर दे और इस माध्यम से किए गए दान का विवरण चुनाव आयोग को दे। इसके बाद चुनाव आयोग से कहा गया कि वह इस जानकारी को 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करे। पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने माना कि काले धन से लड़ने और दानदाताओं की गोपनीयता बनाए रखने का घोषित उद्देश्य इस योजना का बचाव नहीं कर सकता। अदालत ने कहा कि चुनावी बॉन्ड कालेधन पर अंकुश लगाने का एकमात्र तरीका नहीं है।

चुनावी बॉन्ड योजना 2018 में कालेधन को राजनीतिक प्रणाली में प्रवेश करने से रोकने के घोषित उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी। तत्कालीन वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि भारत में राजनीतिक फंडिंग की पारंपरिक प्रथा नकद दान है। उन्होंने कहा था, स्रोत गुमनाम या छद्म नाम हैं। धन की मात्रा का कभी खुलासा नहीं किया गया। वर्तमान प्रणाली अज्ञात स्रोतों से आने वाले अशुद्ध धन को सुनिश्चित करती है। यह पूरी तरह से गैर-पारदर्शी प्रणाली है। गोपनीयता खंड पर, उन्होंने कहा था कि दानदाताओं की पहचान का खुलासा उन्हें नकद विकल्प पर वापस ले जाएगा। दानकर्ता की जानकारी गोपनीय रखने के लिए एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीद और भुगतान के संबंध में देशभर में अपनी 29 अधिकृत शाखाओं (जहां से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड जारी होते थे) के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) तय किया था।

● **अक्स ब्यूरो**

आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी

चुनावी बॉन्ड मामले को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार और विपक्षी एक-दूसरे के खिलाफ आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि जो पैसा भाजपा को मिला, हम भी ये जानना चाहते हैं कि आपने इन पैसों से क्या किया? भाजपा को अकेले 5000 करोड़ से ज्यादा पैसा आया। एसबीआई इन तमाम बातों का खुलासा करे कि किस पार्टी ने कितना पैसा किसको दिया। इसके जवाब में मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हम अभी भी ये मानते हैं कि ये सबसे ज्यादा पारदर्शी व्यवस्था थी। अगर कोई कहता है कि भाजपा को ज्यादा पैसा मिला तो यह कुतर्क है, आज से 30-40 साल पहले हम अगर कहते कि कांग्रेस को ज्यादा पैसा मिला तो उसका क्या मतलब था। आज भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है। यह निश्चित है कि केंद्र सरकार के चुनावों में काले धन के जरिए होने वाले भ्रष्टाचार को रोकने के प्रयासों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से झटका लगा है। कोर्ट के बॉन्ड के मामले में दिए गए आदेश के बाद राजनीतिक दल फिर से चुनावी चंदे के नाम पर उद्योपतियों की बांह मरोड़ने से बाज नहीं आएंगे।

परिवारवाद से विस्तारवाद

नेहरू-गांधी राजवंश के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सत्तारूढ़ भाजपा परिवारवाद (भाई-भतीजावाद) के खिलाफ बात करती रहती है और लोकसभा चुनावों में वंशवाद की राजनीति के खिलाफ लड़ाई को अपना मुख्य मुद्दा बनाती रही है।

यदि किसी परिवार में एक से अधिक लोग जनसमर्थन से अपने बलबूते पर राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो उसे हम परिवारवाद नहीं कहते हैं। हम परिवारवाद उसे कहते हैं जो पार्टी परिवार चलाता है। पार्टी के सारे निर्णय परिवार के लोग करते हैं वो परिवारवाद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम चाहते हैं, एक ही परिवार के 10 लोग राजनीति में आएं। नौजवान राजनीति में आएं। लेकिन परिवारवाद के जरिए नहीं। यह चिंता का विषय है। लोकसभा में फरवरी के महीने में प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद आखिर क्या है? उस पर अपने विचार रखे थे। परिवारवाद या वंशवाद की राजनीति संभवत: लोकतंत्र की भावना से विपरीत है।

आलोचकों का कहना है कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्याप्त कई राजनीतिक बुराईयों में से एक है। राजनेता अक्सर पारिवारिक सदस्यों को अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर पेश करते नजर आते हैं। भारत या फिर कहें कि दक्षिण एशिया में आमतौर पर राजनेताओं के बच्चों का राजनीति में आना कोई नई बात नहीं है। राजनीति उनके लिए भी सबसे अच्छा करियर है। नेहरू-गांधी राजवंश के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सत्तारूढ़ भाजपा परिवारवाद (भाई-भतीजावाद) के खिलाफ बात करती रहती है और लोकसभा चुनावों में वंशवाद की राजनीति के खिलाफ लड़ाई को अपना मुख्य मुद्दा बनाती रही है। लेकिन पार्टी के पास अब कई पूर्व प्रधानमंत्रियों और उप प्रधानमंत्रियों के परिवार के सदस्य हैं। हरियाणा के मंत्री और पूर्व उपप्रधानमंत्री देवीलाल के बेटे और निर्दलीय विधायक रणजीत सिंह चौटाला इस सूची में नवीनतम नाम बन गए हैं। वह हिसार संसदीय सीट से तुरंत टिकट पाने के लिए भाजपा में शामिल हो गए। अन्य में कांग्रेस के दो गैर-गांधी प्रधानमंत्रियों लालबहादुर शास्त्री और पीवी नरसिम्हा राव के परिजन शामिल हैं। भाजपा की तरफ से कांग्रेस पर अक्सर उन दिग्गजों को दरकिनार करने का आरोप लगाया जाता है जो गांधी परिवार से नहीं हैं।

नरसिम्हा राव के बेटे प्रभाकर राव के जल्द ही तेलंगाना भाजपा में शामिल होने की संभावना है। राव के पोते एनवी सुभाष पहले से ही भाजपा में हैं। समाजवादी पूर्व प्रधानमंत्रियों के परिवारों के कुछ सदस्यों को भी भाजपा या उसके सहयोगियों या मित्र दलों में घर मिल गया है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर 2019 में समाजवादी पार्टी (सपा) से भाजपा में आ गए और वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं। जनता दल के पूर्व प्रधानमंत्री आईके गुजराल के बेटे नरेश गुजराल अकाली दल के एक प्रमुख नेता रहे हैं, जो अब निरस्त कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को लेकर सितंबर 2020 में एनडीए से बाहर निकलने से पहले भाजपा का सबसे पुराना सहयोगी था। अपने गठबंधन को पुनर्जीवित करने के लिए पर्दे के पीछे हुई बातचीत के कुछ दौर विफल होने के बाद दोनों पार्टियों ने अब पंजाब में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है।

जनता पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे और आरएलडी के संस्थापक अजीत सिंह ने एनडीए और कांग्रेस के नेतृत्व वाली दोनों सरकारों के मंत्रिमंडल में अपनी भूमिका निभाई थी। वह वीपी सिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का हिस्सा थे और बाद में नरसिम्हा राव सरकार में शामिल हो गए। जुलाई 2001 में वह अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में कृषि मंत्री के रूप में शामिल हुए। बाद में वह मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए कैबिनेट का भी हिस्सा बने। पिछले महीने, दिवंगत अजित सिंह के बेटे जयंत चौधरी लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी भारतीय गठबंधन को छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए थे।

देश में लोकसभा चुनावों का शंखनाद हो चुका है। आज परिस्थितियां सत्तारुढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पक्ष में

दक्षिण में भी कमोबेश यही स्थिति

पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली जनता दल (सेक्युलर) भी अब कर्नाटक में एनडीए के साथ गठबंधन में है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि उनकी जीत की स्थिति में उनके बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बन सकते हैं। जबकि लालबहादुर शास्त्री का परिवार एक घनिष्ठ परिवार के रूप में जाना जाता है, उनके रिश्तेदारों की राजनीतिक वफादारी विभिन्न दलों के बीच विभाजित रही है। उनके बड़े बेटे हरिकृष्ण शास्त्री हमेशा कांग्रेस के साथ खड़े रहे हैं। उनके अन्य पुत्रों में से सुनील शास्त्री कई बार कांग्रेस और भाजपा के बीच घूम चुके हैं, जबकि अनिल शास्त्री, जो 1980 के दशक में जनता दल में थे। कई वर्षों से कांग्रेस के साथ हैं। शास्त्री के पोते-पोतियों में, उप्र के पूर्व मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह, उनकी बेटी सुमन सिंह के बेटे, भाजपा की सबसे अधिक पहचानी जाने वाली आवाजों में से एक रहे हैं। पार्टी ने पिछले हफ्ते उन्हें आंध्र प्रदेश में चुनाव के लिए सह-प्रभारी नियुक्त किया, जहां विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हो रहे हैं।

भाजपा की परिवारवाद की परिभाषा

2009 में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हरिकृष्ण शास्त्री के बेटे विभाकर फरवरी में भाजपा में शामिल हो गए। सुनील शास्त्री के बेटे विनम्र रालोद में हैं, जबकि शास्त्री के सबसे छोटे बेटे अशोक शास्त्री की बेटी महिमा भाजपा में हैं। भाजपा के कद्दावर नेता और वाजपेयी सरकार में उप प्रधानमंत्री रहे लालकृष्ण आडवाणी के परिवार के सदस्य राजनीति में नहीं आए हैं लेकिन वे अनौपचारिक रूप से पार्टी से जुड़े हुए हैं। हालांकि देशभर के कई प्रमुख राजनीतिक परिवार कांग्रेस के सुनहरे दिनों में उससे जुड़े रहे, क्योंकि गांधी परिवार के पास इसके कामकाज पर जबरदस्त नियंत्रण था, लेकिन भाजपा अब इन परिवारों के हर महत्वपूर्ण चेहरे को अपने हिस्से में शामिल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय राजनीति में विस्तार और वर्चस्व के लिए इसकी अथक कोशिश है। एक भाजपा नेता का कहना है कि यह एक विशेष समुदाय या उस नेता के अनुयायियों तक पहुंच भी है। अपने वैचारिक अभिभावक आरएसएस से संकेत लेते हुए, भाजपा उन क्षेत्रों और समुदायों के साथ जैविक संबंध का दावा करने के लिए कई राष्ट्रीय प्रतीकों और नेताओं को गले लगा रही है, जिन पर उसका सीधा प्रभाव नहीं है। नेता ने कहा कि भाजपा के लिए, विभिन्न विचारधाराओं के शीर्ष नेताओं के रिश्तेदारों को शामिल करने से गांधी परिवार के प्रति कांग्रेस पार्टी के जुनून को उजागर करने में भी मदद मिलती है।

बताई जा रही हैं। वर्तमान में द्रुत गति से हो रहा विकास, कुलांचे भरती अर्थव्यवस्था, स्वदेशी और आत्मनिर्भरता को लक्ष्य बना अग्रसर हो रहे भारत व विदेशी कूटनीतिक मोर्चों पर देश को मिलती सफलता या बात करें सांस्कृतिक उत्थान और साम्प्रदायिक सौहार्द की, तो थोड़ी बहुत नुक्ताचीनी के बाद कमोबेश हर विरोधी भी मान रहा है कि वर्तमान सरकार का कार्यकाल अच्छा रहा है। इन परिस्थितियों से ही तो उत्साहित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबकी बार 400 पार का उत्साही नारा दिया है, सत्ताधारियों की दृष्टि से हर कहीं बम-बम है, बस यहीं से शुरू हो सकता है अनुकूल परिस्थिति के खतरे पैदा होने का क्रम। अतिउत्साही भाजपा को यह विस्मृत नहीं होना चाहिए कि साल 2004 में भी उसके पास नरेंद्र मोदी व अमित शाह की तरह अटल बिहारी वाजपेयी व लालकृष्ण आडवाणी जैसे करिश्माई नेतृत्व की छत्रछाया थी। उस लोकसभा चुनाव में भारत उदय का आकर्षक नारा दिया गया था, अर्थव्यवस्था व विकास तब भी मृगझुंडों के साथ चुंगियां भरने की स्पर्धा कर रहे थे परंतु पार्टी की दृष्टि से परिणाम निराशाजनक रहे। छोटे-छोटे दलों को साथ लेकर कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजग को ऐसी पटकनी दी कि अगले दस साल तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार सत्ता में रही।

माना कि इस तरह की चेतावनी पहली बार नहीं दी जा रही और भाजपा नेतृत्व इस प्रकरण से कुछ सीखा नहीं होगा परंतु इसके बावजूद भी पार्टी को संघर्ष के मार्ग को हर हालत में पकड़कर रखना होगा। वैसे भी मोदी-शाह की जुगलबंदी और अटल-आडवाणी की जोड़ी की कार्यप्रणाली में गांधीजी व सरदार पटेल जैसी भिन्नता सर्वज्ञात है और विपक्ष की डांवाडोल हालत में 2004 दोहराया जाना फिलहाल संभव नहीं लगता परंतु भाजपा को अपनी संघर्षमयी कार्यप्रणाली को बनाए रखना होगा।

देश में केवल भाजपा व वामदलों को ही कार्यकर्ता आधारित दल होने का श्रेय प्राप्त है। कार्यकर्ता के गुणों की पहचान, कार्यकर्ता निर्माण, उसे रूचि व क्षमता अनुसार काम और पूरा सम्मान व इसके साथ जनता से निरंतर संपर्क भारतीय जनता पार्टी की प्रमाणिक कार्यप्रणाली मानी जाती है। पालने से लेकर पार्लियामेंट तक पार्टी इसी पद्धति से आगे बढ़ी है। आज चाहे भाजपा को लक्ष्य सरल लग रहा है परंतु मार्ग इतना भी आसान नहीं है कि लोकसभा में 400 सदस्यों को बिना संघर्ष किए शपथ दिलवाई जा सके। चाहे कांग्रेस कमजोर दिख रही है परंतु तृणमूल कांग्रेस, सपा, डीएमके, एआईएडीएमके, बसपा, आम आदमी पार्टी, पीडीपी, नेशनल कान्फ्रेंस सहित अनेक क्षत्रप अपने-अपने क्षेत्रों में मजबूती के साथ पांव जमाए हुए हैं। कहीं-कहीं इंडिया गठजोड़ के प्लेटफार्म पर मिलकर ये सूबेदार भाजपा की कड़ी परीक्षा लेने वाले हैं। दूसरी ओर विकसित और आत्मनिर्भरता के मार्ग पर बढ़ रहा भारत बहुत-सी शक्तियों के आंखों की किरकिरी बना हुआ है। जो भारत दुनिया में हथियारों की दुनिया का सबसे बड़ा आयातक था वो आज सैन्य सामग्री निर्यात करने लगा है, भला देसी-विदेशी शस्त्रलॉबी इसे कैसे बर्दाश्त कर सकती है? प्रतिबंध के बाद से देश में जिन लाखों विदेशी एनजीओ की दुकानदारी बंद हो गई क्या वे सत्ता परिवर्तन नहीं चाह रही होंगी? इन सबके मद्देनजर भाजपा को कार्यपद्धति पर चलते हुए पूरी शक्ति के साथ चुनावों में उतरना होगा और अनुकूलता के खतरों से सावधान रहना होगा।

कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के घोषणा पत्रों को जुमलेबाजी कहा है। राहुल गांधी का यह जुमला बहुत चर्चित हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि वह एक झटके से गरीबी दूर कर देंगे। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के खाते में डायरेक्ट एक लाख रुपया डालकर एक झटके में गरीबी दूर कर देंगे। उनके खातों में हर महीने साढ़े आठ हजार रुपया खटाखट डालेंगे। भाजपा ने कांग्रेस के गरीब परिवारों को एक-एक लाख रुपए देने के चुनावी वायदे को जुमला कहा है, तो कांग्रेस ने भाजपा के संकल्प पत्र में देशभर में बिजली फ्री देने को जुमला और फ्रीबीस (मुफ्त में रेवड़ियां बांटना) कहा है। हालांकि दोनों में कुछ फर्क है, कांग्रेस ने कहा है कि वह सरकारी खजाने से गरीब परिवारों के खाते में हर साल एक लाख रुपया डालेगी। जबकि भाजपा ने कहा है कि वह हर घर सोलर पैनल योजना शुरू करेगी, सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार सब्सिडी देगी, उसके बाद जो बिजली का उत्पादन होगा, वह एक तरह से फ्री होगा। सरकार सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बिजली फ्री नहीं देने वाली। मोदी सरकार के मंत्रियों का कहना है कि एक करोड़ लोगों ने सोलर पैनल के लिए फार्म भर भी दिया है। सरकार का मानना है कि ग्रामीण व्यक्ति अगर खुद पर 26 रुपए खर्च करने की स्थिति में नहीं है, और शहरी व्यक्ति अगर खुद पर 32 रुपए खर्च करने की स्थिति में नहीं है तो वह गरीबी रेखा के नीचे है।

● **विपिन कंधारी**

कांग्रेस अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। उसके अपने सांसद और बड़े-बड़े नेता चुनाव लड़ने से कन्नी काट रहे हैं। भाजपा के बढ़ते प्रभाव और कांग्रेस की कमजोर पड़ती सत्ता से कांग्रेसियों में भगदड़ मची हुई है। दरअसल कांग्रेस के डूबते राजनीतिक जहाज में सवार नेताओं को अपना भविष्य डूबने का खतरा सता रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस की हालत आयाराम-गयाराम जैसी हो गई है।

दल बदल की राजनीति

भगदड़ से नया ट्रेंड स्थापित

एक बात पानी की तरह साफ है कि हाल के दशक में कांग्रेस के छोटे और कद्दावर नेताओं के भाजपा में भागे चले आने का एक नया ट्रेंड स्थापित हुआ है। बहुत हद तक कांग्रेस पार्टी अब एक खाली हो रहा घर बन चुकी है। ऐसा 10 साल तक सत्ता से दूर रहने के कारण हुआ है। हालिया दल-बदल से हिमाचल प्रदेश की सुक्खु सरकार की न सिर्फ मुश्किलें बढ़ गई हैं बल्कि जिस आक्रामक ढंग से भाजपा ऐसे मामलों को हैंडल करती रही है उसे देखकर तो यही लगता है कि प्रदेश सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश में नौ विधायकों के त्यागपत्र के बाद 68 सदस्यीय सदन में विधायकों की संख्या अब 59 रह गई है। यानी कि बहुमत का आंकड़ा 35 से घटकर 29 पर आ चुका है। कांग्रेस का संख्या बल 39 से गिरकर फिलहाल 33 रह गया है। भाजपा के पास 25 विधायक हैं। जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, अगर वहां भाजपा सभी सीटों पर बाजी मार लेती है तो उसकी संख्या बढ़कर 34 हो जाएगी। अगर कांग्रेस एक और सीट जीतती है तो गेंद स्पीकर के पाले में होगी। राजनीतिक मान्यता है कि प्रतिबद्ध और समर्पित विचारधारा के आधार पर दल-बदल लोकतंत्र को मजबूत और विकसित करते हैं।

देश की सबसे पुरानी एवं मजबूत कांग्रेस पार्टी बिखर चुकी है, पार्टी के कद्दावर, निष्ठाशील एवं मजबूत जमीनी नेता पार्टी छोड़कर अपनी सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, वह भी तब जब लोकसभा चुनाव निकट हैं। कांग्रेस नेताओं का यह दलबदल आश्चर्य की बात है। पार्टी छोड़ने का जैसा सिलसिला चल रहा है, वह देश के इस सबसे पुराने दल की दयनीय दशा और स्याह भविष्य को ही रेखांकित करता है। हालांकि भाजपा और कुछ अन्य दलों के चंद नेता कांग्रेस की शरण में भी गए हैं, लेकिन इसकी तुलना में उसके नेताओं के पार्टी छोड़ने की संख्या कहीं अधिक है। प्रश्न है एक लोकतांत्रिक संगठन की यह दुर्दशा एवं रसातल में जाने की स्थितियां क्यों बनीं? इसके कारणों की समीक्षा एवं आत्म-मंथन जरूरी है। कांग्रेस पार्टी लगातार न केवल हार रही है, बल्कि टूट एवं बिखर रही है, जनाधार कमजोर हो रहा हैं, इन बड़े कारणों के बावजूद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने न इसकी समीक्षा की, न विश्लेषण किया। कांग्रेस पर वंशवाद एवं पुत्रमोह का ठप्पा लगा हुआ है। पार्टी में आंतरिक प्रजातंत्र नहीं है। शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेने में अक्षम है। बहुसंख्यकों के कल्याण की कोई नीति नहीं है। तुष्टीकरण नीति भी उसके लिए घातक साबित हो रही है। इन बड़े कारणों के बावजूद पार्टी में सन्नाटा पसरे होने के कारण ही अनेक जिम्मेदार एवं कर्णधार नेता ही पार्टी छोड़कर जा रहे हैं या चले गए हैं। आज का कांग्रेसी शीर्ष नेतृत्व साम्प्रदायिक, असामाजिक, स्वार्थी, चाटुकारी एवं देश-विरोधी तत्वों के साथ इस तरह ताना-बाना हो गया है कि उससे निकलना मुश्किल हो गया है। सांप-छछूंदर की स्थिति है। न निगलते बनता है और न उगलते। कांग्रेस नेतृत्व सत्ता प्राप्ति की खुशफहमी और खोने के खतरे की फोबिया से ग्रस्त है।

लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की लंबी फेहरिस्त सामने आ चुकी है। यह सिलसिला लोकसभा चुनाव तक जारी रहने की उम्मीद है। कांग्रेस में बदहवासी का आलम यह है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरते-गिरते बची है। राज्यसभा के निर्वाचन में हुई क्रॉस वोटिंग का सर्वाधिक खामियाजा कांग्रेस ने भुगता है। क्रॉस वोटिंग करने वाले नेताओं को इस बात का अंदाजा लग गया कि इस राजनीतिक पार्टी में भविष्य सुरक्षित नहीं है। यही वजह रही कि बहती गंगा में हाथ धोने से कांग्रेस के नेता बाज नहीं आए।

आश्चर्य की बात यह है कि एक तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पहले देश में एकता यात्रा निकाली और उसके बाद न्याय यात्रा। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता कांग्रेस में व्याप्त हताशा को रोकने के लिए कोई मजबूत उपाय नहीं कर सके। पार्टी से एक के बाद एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस का दामन छोड़ने में लगे हुए हैं। कांग्रेस की बात करें तो पांच बड़े नेताओं ने पिछले एक महीने के अंदर पार्टी छोड़ी है। और तो और यह सिलसिला अभी भी चल रहा है। चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। ऐसे में कांग्रेस के लिए नई रणनीति बनाना और जीत हासिल करना बेहद मुश्किल होगा। बड़े नेताओं के दल बदलने से सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हुआ है, लेकिन भाजपा भी इससे नहीं बच पाई है। सत्ताधारी पार्टी के तीन बड़े नेता पाला बदल चुके हैं। खास बात यह है कि तीनों नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के अशोक तंवर भी भाजपा का हिस्सा बन चुके हैं। हालांकि, भाजपा का साथ छोड़कर कांग्रेस में

जाने वाले आखिरी बड़े नेताजी विवेक थे, जिन्होंने नवंबर 2023 में ऐसा किया था। इसके बाद से पार्टी अपने नेताओं को बांधकर रखने में सफल रही है।

कांग्रेस के कई पूर्व मुख्यमंत्री जैसे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह, गुलाम नबी आजाद, एन. बिरेन सिंह, नारायण राणे, एसएम कृष्णा, शंकर सिंह वाघेला, पेमा खांडू और अशोक चव्हाण जैसे नेताओं का भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भरोसा समाप्त होता नजर आया। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता एक तरफ तो पार्टी छोड़ चुके हैं। वहीं, दूसरी तरफ कई बड़े नेताओं के पार्टी छोड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। महाराष्ट्र में तो कांग्रेस को एक के बाद एक प्रदेश के तीन दिग्गज नेताओं ने झटका दिया है। सबसे पहले पार्टी से दो महीने पहले मिलिंद देवड़ा ने इस्तीफा दिया। इसके बाद 8 फरवरी को बाबा सिद्दीकी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया और उसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण भी कांग्रेस की नाव से उतर चुके हैं। कांग्रेस के अंदर की अंतर्कलह आज से जारी नहीं है।

राहुल गांधी के सबसे नजदीकी नेताओं में शामिल रहे दिग्गज भी अब भाजपा के साथ हैं, तो वहीं कांग्रेस में सोनिया गांधी के करीबी माने जाने वाले नेताओं में से रीता बहुगुणा जोशी, कैप्टन अमरिंदर सिंह और गुलाम नबी आजाद भी पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं। कांग्रेस से युवा नेताओं का भी मोहभंग होता जा रहा है। इसका उदाहरण मिलिंद देवड़ा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, अल्पेश ठाकोर, हार्दिक पटेल, सुष्मिता देव, प्रियंका चतुर्वेदी, आरपीएन सिंह, अशोक तंवर जैसे नेता हैं, जो कांग्रेस से अलग हो चुके हैं। बिहार में अशोक चौधरी, असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा, सुनील जाखड़ के साथ अश्विनी कुमार जैसे भी नेता हैं जो पार्टी के काम करने के तरीके से नाखुश होकर पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं। कांग्रेस ने पूरे देश में विपक्ष को एनडीए के खिलाफ इकट्ठा करने के लिए इंडिया गठबंधन तैयार किया, तब उसे लगा था कि देश की सत्ता तक पहुंचने के लिए यह रास्ता आसान होगा। लेकिन, एक-एक कर इंडिया गठबंधन से पार्टियां अलग होती चली गईं। सबसे पहले नीतीश कुमार जिन्होंने इस गठबंधन के लिए सबको इकट्ठा किया था भाजपा के साथ हो लिए। फिर ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को भी कांग्रेस का साथ रास नहीं आ रहा। ममता कांग्रेस पर निशाना साध रही हैं तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने का दावा किया था उससे साफ हो गया है कि वह एकला चलो रे की राह पर बढ़ रहे हैं। एनसीपी और शिवसेना टूटी और उनका नेतृत्व जिनके हाथ में है, वह कांग्रेस का विरोध करते रहे हैं। कांग्रेस के 10 साल के समय को देखें तो पता चल जाएगा कि एक तरफ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से पार्टी की जमीन देश में मजबूत करने की कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ पार्टी के दिग्गज और युवा नेताओं ने एक-एक कर पार्टी का साथ छोड़ दिया है। कांग्रेस को छोड़ते समय इनमें से ज्यादातर नेताओं ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और खासकर राहुल गांधी पर उनकी अनदेखी के आरोप लगाए। इनमें से जिन्होंने भी भाजपा का दामन थामा, उन्हें पार्टी ने जगह भी दी। कांग्रेस ने आचार्य प्रमोद कृष्णम को बाहर का रास्ता दिखाया तो अब उनके भी भाजपा में शामिल होने की बात कही जा रही है। पार्टी के नेताओं के असंतोष पर ध्यान दें तो पता चलेगा कि बड़े-छोटे देशभर के हर प्रदेश से कुल मिलाकर 400 से ज्यादा की संख्या में अलग-अलग स्तर के नेता कांग्रेस का दामन छोड़ चुके हैं। जर्जर होती कांग्रेस की इसी हालत का फायदा इंडिया गठबंधन के क्षेत्रीय दलों ने उठाया है। क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ लोकसभा की सीटों के मोलभाव अपनी सुविधा के हिसाब से कर रहे हैं। लाचार कांग्रेस के पास क्षेत्रीय दलों की शर्तें मानने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचा है। यही वजह है कि कांग्रेस ने पंजाब, दिल्ली और उप्र सहित कई राज्यों में मजबूरी में समझौते किए हैं। यह बात दीगर है कि कभी इन राज्यों में कांग्रेस की दुदंभी बजती थी।

दरअसल भाजपा के ताकतवर होने के बाद कांग्रेस ने कभी भी पार्टी के लगातार कमजोर पड़ते जाने को लेकर आत्म-मंथन नहीं किया। कांग्रेस अपनी किसी भी नीति और सिद्धांत पर कायम नहीं रह सकी। ऐसे में भाजपा ने कांग्रेस के ढहते किले में तोड़फोड़ करने में कसर बाकी नहीं रखी। भाजपा ने दोतरफ से कांग्रेस का घेराव किया। एक तरफ कांग्रेस शासन के भ्रष्टाचार और गलत नीतियों को न सिर्फ उजागर किया बल्कि कई दिग्गजों पर सीबीआई और ईडी की कार्रवाई भी करवाई। दूसरी तरफ भाजपा ने कांग्रेस में सेंधमारी करके उसे हाशिए पर लाने में कसर बाकी नहीं रखी। दोनों तरफ से पिटती कांग्रेस में नेताओं को लगने लगा कि इसके दिन लद गए लगते हैं। कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं को बेशक भाजपा में अपना भविष्य बेहतर लग रहा हो, किंतु भाजपा के अनुशासन केंद्रीकृत नीतियों के चलते कांग्रेस जैसी मौज नहीं मिल सकती।

● इन्द्र कुमार

दल-बदल नई परिघटना नहीं

देश में दल-बदल कोई नई परिघटना नहीं है, बल्कि राजनीतिक अस्थिरता और अनिश्चितता की स्थिति में हमेशा से रही है। किंतु आजकल स्वार्थ और पद के लालच में जो दल-बदल हो रहे हैं उससे सरकारों की स्थिरता के लिए खतरा पैदा हो गया है। यह न केवल उन राजनीतिक दलों के साथ विश्वासघात है जिसके टिकट पर कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ता है, जीतता है, बल्कि उन लोगों की इच्छा के साथ भी अन्याय है जिन्होंने उन्हें चुना है। कौन, कब, किस करवट मुड़ जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं रह गया है। चुनाव आते ही दल-बदल के मामलों की भरमार होने लगती है। मौसम विज्ञानियों की तरह राजनीतिक मौसम को आंकने वाले नेता लहर के साथ खुद को जोड़ लेते हैं। दल-बदल यूं तो देश के पहले आम चुनाव से ही हो रहा है, लेकिन चौथे आम चुनाव के बाद मार्च 1967 से फरवरी 1968 के बीच की छोटी अवधि में ही लगभग 438 सदस्यों ने दल बदल का रिकॉर्ड कायम किया। दिलचस्प तो यह है कि हरियाणा विधानसभा के एक निर्दलीय सदस्य ने एक ही दिन में पांच बार दल-बदल कर आया राम-गया राम की कहावत को चरितार्थ किया था। तब लोकसभा के सचिव पी बैंकट सुब्बैया द्वारा अगस्त 1967 में संसद में एक संकल्प प्रस्तुत किया गया था, जिसका संज्ञान लेते हुए सरकार ने तत्कालीन गृहमंत्री वाईबी चव्हाण की अध्यक्षता में दल-बदल संबंधी एक समिति का गठन किया था, जिसने 18 फरवरी 1969 को अपनी संस्तुति दी थी, लेकिन उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।

नक्सल नहीं, अब धर्मांतरण बड़ा मुद्दा

मुद्दा अब बस्तर की चुनावी रंगत में दिखा रहा असर

हिंदू पक्ष का कहना है कि यहां केरल तथा पूर्वोत्तर के ईसाई पादरी आकर वनवासी हिंदू ग्रामीणों को इलाज के नाम पर बरगलाते हैं और उन्हें ईसाईयत में धर्मांतरित करते हैं। नक्सल समर्थकों का भी उन्हें इसमें साथ मिलता है। फिर जो वनवासी हिंदू ईसाई बन जाते हैं वे अपना सरनेम नहीं बदलते, मंदिर से बैर रखते हैं और हिंदू परंपरा नहीं मानते किंतु वनवासी होने के लाभ भी लेते रहते हैं। इसलिए इस बार डीलिस्टिंग बड़ा मुद्दा है और इस मांग को लेकर हिंदू पक्ष एकजुट हुआ है। नारायणपुर से निकलकर यह मुद्दा अब बस्तर की चुनावी रंगत को और गहरा कर रहा है। इसके अलावा बस्तर में रोजगार, पलायन, विकास, कृषि जैसे मुद्दे भी हैं किंतु उनका जोर मात्र शहरी सीमा तक चल रहा है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में वहीं मुद्दे हैं जो दशकों से बस्तर में छाए हुए हैं जिनके समाधान का आज तक ईमानदार प्रयास नहीं हुआ है। बस्तर के मतदाता इस बार भी मतदान द्वारा अपनी किस्मत बदलने की मंशा पाले बैठे हैं किंतु राजनीतिक दलों की राजनीति को देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि उनकी मंशा कितनी और कैसे पूरी होगी? फिलहाल तो देश के लिए अबूझ पहेली सा बस्तर अपनी ही समस्याओं से जूझ रहा है।

8 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी नक्सलियों के गढ़ माने जाने वाले बस्तर में थे लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने नक्सल समस्या पर कुछ नहीं बोला। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जनसभा करने पहुंचे मोदी ने कांग्रेस और इंडिया एलायंस पर तो हमला बोला लेकिन बस्तर जिस समस्या से दो चार होता रहा है, उस पर मौन रहे। असल में नक्सली अभी भी बस्तर में प्रभावी तो हैं लेकिन अब यहां ईसाई मिशनरियों द्वारा आदिवासियों का धर्मांतरण ज्यादा बड़ा मुद्दा बन गया है। इसलिए 19 अप्रैल को प्रथम चरण में जब बस्तर में वोटिंग होगी तब धर्मांतरण का मुद्दा हावी रहेगा। इसका मतलब यह नहीं कि बस्तर में नक्सली कोई मुद्दा ही नहीं रहे। बस्तर में नक्सली हथियारों से कमजोर भले पड़ गए हों लेकिन वैचारिक रूप से वो आज भी चुनावों को प्रभावित करते हैं। इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी के कैंडिडेट का वोट प्रतिशत चुनाव दर चुनाव बढ़ता जा रहा है।

रेड कोरिडोर का हिस्सा बस्तर सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है और 1952 से 1996 तक यह सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। 1998 से 2014 तक यहां भाजपा के सांसद चुने गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के दीपक बैज ने भाजपा के बैदूराम कश्यप को 38,982 वोटों से हराकर भाजपा का तिलिस्म तोड़ दिया था। लेकिन इस बार कांग्रेस ने अपने सिटिंग एमपी दीपक बैज का टिकट काटकर सुकमा जिले की कोंटा सीट से विधायक कवासी लखमा को टिकट दिया है। वहीं भाजपा ने विश्व हिंदू परिषद से जुड़े महेश कश्यप को चुनावी मैदान में उतार दिया है। बस्तर लोकसभा सीट से सीपीआई ने फूलसिंह कचलाम को टिकट दिया है। बसपा से आयतुराम मंडावी चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं किंतु मुख्य मुकाबला भाजपा-कांग्रेस प्रत्याशियों के बीच ही है।

बस्तर लोकसभा सीट के अंतर्गत आठ विधानसभा सीटें आती हैं जिनमें से जगदलपुर एकमात्र अनारक्षित सीट है जबकि शेष सातों विधानसभाएं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव परिणामों के अनुसार बस्तर लोकसभा की 8 में से 5 विधानसभाओं कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, चित्रकोट तथा जगदलपुर में भाजपा जबकि शेष 3 विधानसभा सीटों बीजापुर, कोंटा और बस्तर में कांग्रेस प्रत्याशी को जीत मिली थी। इस हिसाब से देखा जाए तो बस्तर में भाजपा का पलड़ा भारी दिखता है किंतु क्या विधानसभा चुनाव की जीत लोकसभा में भी कायम रह पाएगी? दो दशक से भाजपा के कश्यप परिवार की सीट रही बस्तर लोकसभा में इस बार भाजपा प्रत्याशी कश्यप अवश्य है किंतु चार बार सांसद रहे बलिराम कश्यप और दो बार सांसद रहे दिनेश कश्यप परिवार से इनका कोई संबंध नहीं है। यहां कश्यप परिवार के साथ पर भी भाजपा संगठन की नजर है। यह सच है कि 1969 में अस्तित्व में आए **नक्सल मूवमेंट** की नाभि बस्तर रहा है जिसके गर्भ में आज भी नक्सली फल-फूल रहे हैं किंतु अब इनका प्रभाव और दायरा सिमट गया है, क्योंकि सरकार ने बड़े पैमाने पर बस्तर में विकास कार्य प्रारंभ किए हैं। एक समय बस्तर के हजारों सरकार विहीन गांवों तक जैसे-तैसे कच्ची-पक्की सड़कें बनती जा रही हैं। जिन गांवों में आपसी विवादों का निपटारा नक्सली करते थे, अब सरकारी नुमाइंदे करते हैं। फोर्स भी बस्तर के हर गांव तक पहुंच बनाने में सफल हो रही है।

दरअसल, छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहे जाने वाले बस्तर में भौगोलिक विषमता सरकार के कदम रोक देती है। स्वतंत्रता के 75 वर्षों बाद भी बस्तर में रेल सपना ही है। राष्ट्रीय-राजकीय राजमार्गों को छोड़ दें तो गांवों तक पहुंच पाना कमर तोड़ देता है। सन् 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद से अधिकांश समय राज्य में भाजपा का शासन रहा है जिसमें बड़े पैमाने पर नक्सल हिंसा से जुड़े नेता या तो पकड़े गए हैं अथवा सुरक्षाबलों द्वारा मारे गए हैं। यही कारण है कि भाजपा शासन को नक्सली अपने दुश्मन के रूप में देखते हैं। हाल ही में एक समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के अनुसार नक्सलियों ने बस्तर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जिताने की अपील करते हुए पोस्टर्स गांवों में लगवाए थे। नक्सलियों की यह अपील चुनाव में बड़ा मुद्दा बन गई है। इसके अलावा चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशी वनवासी समाज की मान्यताओं, परंपराओं एवं जल, जंगल, जमीन को लेकर उनकी भावनाओं को लेकर बड़े दावे कर रहे हैं। हालांकि अब तक बस्तर से चुने गए 12 में से 7 सांसदों ने नक्सल समस्या एवं वनवासी संस्कृति को लेकर ही चुनाव लड़ा और जीते। इस बार भी परिदृश्य बदला नहीं है गोयाकि नक्सलवाद और वनवासी संस्कृति इस क्षेत्र में सदाबहार मुद्दा है। दिसंबर, 2022 से लेकर जनवरी, 2023 के एक महीने में बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले में ईसाई धर्मांतरण को लेकर हिंसा की दर्जनों बड़ी घटनाएं हुईं।

● **रायपुर से टीपी सिंह**

सीट बंटवारे की फांस...

पिछले लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में दो गठबंधन थे, एनडीए और यूपीए। एनडीए में भाजपा ने 25 और शिवसेना ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था। दूसरी तरफ यूपीए में कांग्रेस ने 26 और एनसीपी ने 22 सीटों पर चुनाव लड़ा था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना एनडीए छोड़कर यूपीए में शामिल हो गई थी, और इस नए गठबंधन को महाविकास आघाडी नाम दिया गया। इसके बाद शिवसेना और एनसीपी के दो टुकड़े हो चुके हैं। शरद पवार तो कांग्रेस के ही साथ आघाडी में हैं, लेकिन उनके भतीजे अजीत पवार दो तिहाई सांसद लेकर एनडीए में चले गए हैं। उद्धव ठाकरे भी आघाडी में ही हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे शिवसेना के दो तिहाई से ज्यादा विधायक और सांसद अपने साथ लेकर एनडीए में चले गए।

महाराष्ट्र में भाजपा-एनसीपी-शिवसेना गठबंधन को महायुति कहा जाता है। महाविकास आघाडी में हुए सीट बंटवारे में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने सबसे ज्यादा 21 सीटें हासिल कर ली हैं, कांग्रेस को 17 सीटें मिली हैं, जबकि एनसीपी को मात्र 10 सीटें मिली हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो उद्धव ठाकरे ने महाविकास आघाडी में 21 सीटें हासिल करके अपनी स्थिति को लगभग बरकरार रखा है। मांगी गई 5 सीटें नहीं मिलने पर प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन आघाडी गठबंधन से बाहर हो गई है। उनके इंडी एलायंस से बाहर निकलने के बाद बाकी बचे तीनों दलों के लिए सीट शेयरिंग करना आसान हो गया।

महाविकास आघाडी या यह कहिए कि इंडी एलायंस में सीटों का बंटवारा तो हो गया है। कांग्रेस ने जिस तरह दिल्ली में त्याग किया है, उसी तरह महाराष्ट्र में भी सांगली और भिवंडी सीटों का त्याग कर दिया। कांग्रेस ने सांगली सीट उद्धव ठाकरे की शिवसेना और भिवंडी सीट एनसीपी के लिए छोड़ दी। शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों ने ही इन सीटों पर सीट शेयरिंग से पहले अपने उम्मीदवारों का ऐलान करके कांग्रेस को दबाव में ला दिया था। शरद पवार ने सीट शेयरिंग होने से पहले ही कांग्रेस के मजबूत दावे वाली भिवंडी सीट से सुरेश महात्रे को उम्मीदवार घोषित कर दिया था। कांग्रेस से टिकट मांग रहे दयानंद चौरघे बागी उम्मीदवार बनकर एनसीपी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। इसी तरह उद्धव ठाकरे ने सीट शेयरिंग होने से पहले ही सांगली से पहलवान चंद्रहार पाटिल को उम्मीदवार घोषित कर दिया था। जबकि कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री वसंत दादा पाटिल के पोते विशाल पाटिल को चुनाव लड़वाना चाहती थी। लेकिन बैकफुट पर आई कांग्रेस को दोनों दलों के सामने घुटने टेकने पड़े। इतना ही नहीं, बल्कि यह भी कहा जा रहा है कि पवार और उद्धव ने अपनी बेहतर रणनीति के चलते कांग्रेस को हारने वाली सीटें थमा दी हैं। जैसे उत्तर मुंबई, जहां से भाजपा ने पीयूष गोयल को टिकट दिया है, यह सीट भाजपा की मजबूत सीट है, लेकिन मुंबई पर अपना पहला दावा करने वाली उद्धव शिवसेना के पास कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं था, तो यह सीट कांग्रेस को थमा दी गई।

उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने कांग्रेस से 31 सीटें हासिल करके एनडीए में गए एकनाथ शिंदे और अजीत पवार पर भी भाजपा से अपनी पार्टियों के लिए ज्यादा सीटें हासिल करने का मानसिक दबाव बना दिया है। भाजपा ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 10 से 14 और अजीत पवार की एनसीपी को 4 सीटें देने की पेशकश की थी। अमित शाह ने एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ बातचीत में कहा था कि भाजपा 30-34 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन एकनाथ शिंदे ने अमित शाह से 16 सीटों की मांग रखी है। महाविकास आघाडी में हुए सीट बंटवारे के बाद एकनाथ शिंदे और अजीत पवार पर अपनी-अपनी पार्टियों के भीतर ज्यादा सीटें मांगने का दबाव बढ़ना स्वाभाविक है। महाराष्ट्र में भाजपा के पुराने सहयोगी रामदास अठावले ने आरपीआई के लिए दो सीटें मांगी हैं, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि भाजपा उनकी मांग नहीं मानती है, तो भी वह एनडीए नहीं छोड़ेंगे। इससे स्पष्ट है कि भाजपा ने उन्हें राज्यसभा में बनाए रखने का आश्वासन दे दिया है। अलबत्ता भाजपा उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण को दो सीटें देने पर विचार कर रही है। एनडीए ने भले ही सीट शेयरिंग का सार्वजनिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन 36 सीटों पर तीनों दलों में सहमति बन चुकी है। अभी तक भाजपा 24, एकनाथ शिंदे 8 और अजीत पवार तीन उम्मीदवारों की घोषणा कर चुके हैं। अजीत पवार ने परभणी सीट के लिए राष्ट्रीय समाज पक्ष (आरएसपी) के संस्थापक महादेव जानकर का समर्थन किया है। इसका मतलब साफ है कि इन 36 सीटों पर आपसी सहमति के बाद ही उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है। बाकी 12 सीटों पर सहमति बनना बाकी है।

भाजपा ने अपनी सूची में महाराष्ट्र के किसी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया था, लेकिन दूसरी सूची में महाराष्ट्र के जिन 20 नामों की घोषणा की, उनमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को उनके गृह क्षेत्र नागपुर से, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को मुंबई उत्तर से, पंकजा मुंडे को उनकी बहन प्रीतम की जगह बीड से, सुधीर मुनगंटीवार, मिहिर कोटेचा और रावसाहेब दानवे जैसे दिग्गजों को भी उनकी सीटों पर बरकरार रखा है।

● **बिन्दु माथुर**

कौन बनेगा जाणता राजा?

मोदी को कितनी सीटें मिलेंगी, इससे ज्यादा इस बात पर चर्चा हो रही है कि महाराष्ट्र की जनता एकनाथ शिंदे बनाम उद्धव ठाकरे में से किसे असली शिवसेना का सर्टिफिकेट देने वाली है? एकनाथ शिंदे के साथ बहुसंख्यक विधायक और सांसद भले ही चले गए हों, बाला साहेब ठाकरे की पार्टी का नाम और सिंबल भले ही एकनाथ शिंदे को मिल गया हो, एकनाथ शिंदे भले ही उद्धव को कुर्सी से उतारकर खुद महाराष्ट्र के राजा बन गए हों, लेकिन शिवसेना के समर्थकों के दिलों में कौन राज करता है इस पर महाराष्ट्र में संशय बना हुआ है। पार्टी का विभाजन, वफादारी में बदलाव और तमाम कानूनी झटकों के बाद भी उद्धव ठाकरे मराठी मानुष की सहानुभूति को अपने पक्ष में बनाए रखने में काफी हद तक सफल रहे हैं। उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को गद्दार और मोदी-शाह के रहमोकरम पर पलने वाला मुख्यमंत्री बता रहे हैं और कह रहे हैं कि बाघ की खाल ओढकर कोई शेर नहीं बन जाता। शिंदे के हाथों मूल शिवसेना गंवा चुके उद्धव ठाकरे पूरे महाराष्ट्र का दौरा करने का प्लान बना रहे हैं और उनकी कोशिश महाराष्ट्र की सभी 48 लोकसभा सीटों पर पहुंचने की है। ऐसा इसलिए क्योंकि उद्धव ठाकरे जानते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव उनके लिए जीने और मरने का चुनाव है।

कहीं मजबूरी, कहीं लालसा...

लोकतंत्र में चुनाव लड़ने के भी अलग-अलग कारण होते हैं। अधिकतर प्रत्याशी तो केवल अपना शौक पूरा करने के लिए चुनाव लड़ते हैं। उन्हें पता होता है कि उनकी जमानत जब्त होगी, इसके बावजूद भी वे चुनावी मैदान में आते हैं। कोई जनता की सेवा के लिए विधानसभा या लोकसभा पहुंचकर उनके हक की आवाज उठाने के लिए चुनाव लड़ते हैं तो कोई राजनीति में अपनी हैसियत दिखाने और आगे बढ़ने के लिए चुनावी मैदान में कूदते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राजस्थान में नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कुल प्रत्याशियों में कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जो वर्तमान में विधायक हैं। इसके बावजूद भी वे लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं।

राजस्थान में हो रहे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के चार विधायक चुनावी मैदान में हैं। पार्टी ने देवली-उनियारा विधायक हरीश मीणा को टोंक-सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है जबकि मुंडावर सीट से विधायक ललित यादव को अलवर लोकसभा सीट से टिकट दिया है। इसी तरह झुंझुनू विधायक बृजेंद्र ओला को झुंझुनू लोकसभा और दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा को दौसा लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। खींवसर से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक हनुमान बेनीवाल नागौर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं। आरएलपी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके बेनीवाल को प्रत्याशी बनाया है। उधर चौरासी विधानसभा सीट से भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) के विधायक राजकुमार रोत बांसवाड़ा-डूंगरपुर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर-जैसलमेर लोकसभा सीट से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी लोकसभा चुनाव में कूदे हैं। भाटी शिव विधानसभा सीट से पहली बार विधायक चुने गए और वे लोकसभा जाने का प्रयास कर रहे हैं।

वर्ष 2004 से लेकर 2019 तक के लोकसभा चुनाव में भी कई विधायकों ने लोकसभा जाने का सपना देखा। 10 विधायक लोकसभा पहुंचने में कामयाब भी रहे। वर्ष 2004 में बहरोड़ के तत्कालीन विधायक करण सिंह यादव अलवर से सांसद चुने गए थे जबकि मेड़ता से तत्कालीन विधायक भंवर सिंह डांगावास नागौर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। वर्ष 2009 में टोडाभीम से तत्कालीन निर्दलीय विधायक डॉ. किरोड़ी लाल मीणा और सलूंबर से कांग्रेस के तत्कालीन विधायक रघुवीर मीणा सांसद बनकर लोकसभा पहुंचने में कामयाब रहे। वर्ष 2014 में 4 विधायक लोकसभा पहुंचे। इनमें वैर से तत्कालीन विधायक रामस्वरूप कोली, नसीराबाद से सांवरमल जाट, कोटा दक्षिण से ओम बिरला और सुजानगढ़ से संतोष अहलावत भी सांसद बने थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में दो तत्कालीन विधायक लोकसभा पहुंचे थे जिनमें खींवसर से हनुमान बेनीवाल और मंडावा के तत्कालीन विधायक नरेंद्र कुमार शामिल हैं।

लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा दोनों चुनावी रणनीतियों की चौसर पर अपनी सियासी चालें चल रही हैं। भाजपा फिर से राजस्थान में कांग्रेस का क्लीन स्वीप ऑपरेशन में जुटी हुई है। इसके चलते राजस्थान में मिशन 25 को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जमकर गरज रहे हैं, लेकिन इस बीच सियासी चर्चा है कि राजस्थान में भाजपा के क्लीन स्वीप वाले रिकॉर्ड को खतरा है। राजस्थान की तीन लोकसभा सीटों पर कांग्रेस काफी मजबूती से डटी हुई है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि यह तीन सीटें भाजपा का क्लीन स्वीप का गेम बिगाड़ सकती हैं। हालांकि, भाजपा 25 में से 25 सीटों को जीतने का दावा कर रही है, लेकिन जो सियासी समीकरण दिखाई दे रहे हैं, उससे तो भाजपा का क्लीन स्वीप वाला खेल बिगड़ सकता है। सियासत में बाड़मेर-जैसलमेर, नागौर और चूरू लोकसभा सीट के समीकरणों को लेकर काफी चर्चा है। इस रिपोर्ट में तीनों सीटों के समीकरणों को समझने की कोशिश करते हैं।

राजस्थान की सबसे बड़ी सीट बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट है। यहीं नहीं, यह सीट इस लोकसभा चुनाव की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। इसकी वजह शिव के विधायक रविंद्र सिंह भाटी, जिन्होंने निर्दलीय ताल ठोककर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के समीकरणों को बिगाड़ रखा है। रविंद्र सिंह भाटी को लेकर लोगों और युवाओं में जो उत्साह देखने को मिल रहा है, उससे भाजपा की चिंता बढ़ गई है। इसके कारण खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तीन दिनों तक डैमेज कंट्रोल करने के लिए बाड़मेर प्रवास पर रहे। जहां उन्होंने विभिन्न समाजों के लोगों से बातचीत कर समीकरणों को सुलझाने का प्रयास किया। 12 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी बाड़मेर में चुनावी रैली भी कर चुके हैं। माना जा रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी भाजपा के प्रत्याशी कैलाश चौधरी और कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मेदाराम बेनीवाल की जीत में सबसे बड़ा रोड़ा बनकर खड़े हो गए हैं। इधर, फलोदी सट्टा बाजार में भी रविंद्र सिंह भाटी की जीत का दावा किया जा रहा है।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

वसुंधरा राजे और राजपूत वोटर नाराज

राजस्थान में भाजपा भले ही सभी 25 सीटें जीतने का दावा कर रही है, लेकिन राह इतनी आसान भी नहीं है। वजह यह है कि भाजपा का कोर वोटबैंक माना जाने वाला राजपूत समाज इस बार नाराज है। राजपूतों की नाराजगी भाजपा को भारी पड़ सकती है। राजपूत समाज सुखदेव सिंह गोगामेड़ी प्रकरण से पहले ही नाराज चल रहा था, लेकिन अब गुजरात के भाजपा नेता पुरुषोतम रुपाला के विवादास्पद बयान ने आग में घी का काम कर दिया है। गुजरात के बाद इसका असर राजस्थान में दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ वसुंधरा राजे ने खुद को सिर्फ झालावाड़ तक ही सीमित कर लिया है। ऐसे में सियासी जानकारों का कहना है कि भाजपा के लिए इस बार राह आसान नहीं है। हालांकि, शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि भाजपा हैट्रिक लगा लेगी, लेकिन अब स्थितियां पलटती जा रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भाजपा में हमेशा मुख्यमंत्री पद राजपूतों को ही मिलता रहा है। लेकिन इस बार भाजपा ने राजपूत को मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। कहीं न कहीं राजपूत वोटर इससे नाराज है। यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री शेखावत को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस ने राजपूत समाज को विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पर्याप्त टिकट दिए थे।

माफिया मुक्त हो जाएगा उप्र?

ऐसा लग रहा है कि उप्र से धीरे-धीरे माफियाओं का अंत होता जा रहा है। मुन्ना बजरंगी की जेल में हत्या से जो सिलसिला चला वो मुख्तार अंसारी तक पहुंच गया है, जिसकी जेल में ही हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। मुख्तार की मौत से एक सवाल यह जरूर उठता है कि क्या उप्र अब माफिया मुक्त हो जाएगा? अगर हम उप्र में माफियाओं के इतिहास पर नजर डालें तो इसकी शुरुआत 70 के दशक में हरिशंकर तिवारी से होती है जिनकी पिछले साल ही मौत हुई है। इसके बाद 90 के दशक में जिन माफिया सरगनाओं का नाम तेजी से सामने आया, उसमें श्रीप्रकाश शुक्ला वह पहला अपराधी था जिसने उप्र के प्रशासन को घुटने पर ला दिया था। उसे खत्म करने के लिए एक स्पेशल फोर्स का गठन करना पड़ा जिसे एसटीएफ कहा जाता है। इसके बाद मुख्तार अंसारी, बृजेश सिंह, रघुराज प्रताप सिंह (राजा भैया), कृष्णानंद राय, अतीक अहमद, अभय सिंह, प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी, विजय मिश्र, बबलू श्रीवास्तव, संजीव जीवा और धनंजय सिंह ऐसे नाम उभरे जो माफिया थे लेकिन बाहुबली बना दिए गए। राजनीति में उनकी दखल के कारण कुछ तो माननीय विधायक भी बन गए। इनमें से कई मारे जा चुके हैं। कुछ जेल में हैं और कुछ अपराध से विमुख होकर बिजनेस की ओर चले गए हैं।

अपराधियों, माफियाओं के बारे में कहा जाता है कि उनकी उम्र 40-50 साल से अधिक नहीं हुआ करती। इस उम्र तक आते-आते या तो वे आपसी रंजिश का शिकार हो जाते हैं या फिर उन्हें शासन-प्रशासन की ओर से निपटा दिया जाता है। जिनके साथ ऐसा नहीं होता वो खुद ही अपराध का रास्ता छोड़कर या तो राजनीति में चले जाते हैं या ठेके पट्टे वाला बिजनेस व्यापार करने लगते हैं। कुछ ऐसा ही इस समय उप्र में हो रहा है। 9 जुलाई 2018 को बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी की हत्या एक दूसरे माफिया सुनील राठी ने कर दी थी। राठी ने बजरंगी के सिर में 10 गोलियां दागी थीं। यह वह समय था जब योगी सरकार को सत्ता में सालभर हो गया था और प्रदेशभर में माफियाओं, गुंडों, अपराधियों के खिलाफ ठोक दो वाली एनकाउंटर नीति पर सख्ती से अमल किया जा रहा था।

पश्चिमी उप्र से लेकर पूर्वी उप्र तक बहुत सारे छुटभैया गुंडों, शार्प शूटरों को इस अभियान के तहत निपटा दिया गया था। विकास दुबे का एनकाउंटर तो देशभर में चर्चा का कारण बना था। इसी तरह संजीव जीवा भरी कचहरी में मार दिया गया। अतीक अहमद को भी इसी तरह दो छुटभैया अपराधियों ने पुलिस के बीच घुलकर गोली मार दी थी। जो माफिया बच गए उन्होंने या तो सरेंडर कर दिया था या फिर अपराध जगत से ही तौबा कर ली थी। इनके कमजोर पड़ते ही बड़े माफियाओं को भी संकट पैदा होने लगा, क्योंकि इनके अपराध का कारोबार इन्हीं छुटभैया गुंडों और शूटरों के भरोसे चलता था। लेकिन योगी सरकार के निशाने पर वो बड़ी मछलियां भी थीं जिन्होंने राजनीति और अपराध का सहारा लेकर अरबों रुपए की बेनामी संपत्तियां खड़ी कर ली थीं। इस कड़ी में सबसे पहले नंबर लगा इलाहाबाद के अतीक अहमद और गाजीपुर के मुख्तार अंसारी का। ये दोनों पहले से ही किसी न किसी अपराध में जेल में बंद थे और जेल से ही अपना आर्थिक और आपराधिक कारोबार चला रहे थे।

योगी सरकार ने सबसे पहले इनकी बेनामी संपत्तियों पर हमला बोला। जिन-जिन शहरों में इनकी बेनामी संपत्तियां थीं उन्हें कुर्क किया जाने लगा। माफिया अपराध के जरिए जो पैसा कमाता है उसे रियलिटी या फिर ऐसे ही किसी अन्य व्यापार में लगाता है। इसलिए योगी सरकार के इस प्रहार से माफियाओं के आर्थिक साम्राज्य को धक्का लगा। इस लिस्ट में ताजा नाम भदोही में ज्ञानपुर से विधायक विजय मिश्र का शामिल हुआ है जिनकी 113 करोड़ की संपत्ति मुख्तार की मौत से एक दिन पहले ही नीलाम कर दी गई। 2020 में उन्हें एक स्टेज शो करने वाली महिला से रेप का दोषी पाए जाने पर 15 साल की सजा सुनाई गई है और वो जेल में ही हैं। उनकी नामी-बेनामी संपत्तियों को या तो खंडहर बना दिया गया है या फिर उसे नीलाम किया जा रहा है। अतीक, मुख्तार और विजय मिश्र की संपत्तियों पर तो कार्रवाई हुई लेकिन बृजेश सिंह, धनंजय सिंह और अभय सिंह जैसे माफिया कारोबारी ऐसी किसी कार्रवाई से अछूते रह गए। कभी मुख्तार को मारने की कोशिश से चर्चा में आने वाले बृजेश सिंह पर दर्जनों हत्या के मुकदमे चले लेकिन अब वो सभी मुकदमों में बेदाग होकर घर पर रह रहे हैं और उड़ीसा से लेकर झारखंड तक अपना कारोबार कर रहे हैं। धनंजय सिंह जरूर चुनावी रंजिश में सजायाफ्ता मुजरिम बन गए हैं लेकिन जिस तरह से बंद हो चुके केस में उन्हें सजा सुनाई गई है, उससे वो ज्यादा दिन अंदर रहेंगे ऐसा लगता नहीं है।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

माफिया के सफाए में भी जातिवाद

उप्र में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई में ठाकुर माफियाओं का बच जाना या फिर उनकी नामी-बेनामी संपत्तियों के खिलाफ वैसी कार्रवाई का न होना जैसा अतीक, मुख्तार या विजय मिश्र के खिलाफ हुई है, प्रदेश में कई सवालों को जन्म दे रहा है। आरोप है कि ठाकुर माफियाओं को योगी आदित्यनाथ सरकार में संरक्षण मिल रहा है। अगर धनंजय सिंह जेल गए भी हैं तो उसे लेकर पूर्वांचल के ठाकुर मतदाता अपनी नाराजगी दिखाने से नहीं चूक रहे। सवाल यह उठता है कि क्या गुंडों-माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई में कहीं न कहीं जाति और धर्म देखा जा रहा है? अगर स्थानीय लोगों द्वारा उठाए जाने वाले ऐसे सवालों में जरा भी सच्चाई है तो उप्र कभी भी माफिया मुक्त नहीं हो पाएगा। जो अपराधी होते हैं उनकी न कोई जाति होती है और न धर्म। उनका अपना स्वार्थ ही उनकी जाति होती है और उस स्वार्थ को पूरा करने के लिए किया जाने वाला अपराध उनका धर्म। अगर ऐसा न होता तो मुख्तार अंसारी के साथ कभी मुन्ना बजरंगी और अभय सिंह काम न करते। माफियाओं और अपराधियों का जो लोग जातीय और धार्मिक आधार खोज रहे हैं उनकी मानसिकता ही वह समस्या है जिसे देखकर लगता है कि आज कुछ पेड़ जरूर गिरे हैं लेकिन यही मानसिकता रही तो फिर माफियाओं की नई कोंपले निकलेंगी।

भ्रष्टाचार, जंगलराज, नौकरी बड़ा मुद्दा

लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों के ऐलान से पहले बिहार में परिवारवाद का मुद्दा खूब हावी रहा। एनडीए सबसे आक्रामक रही। हालांकि, अब उसके ही नेता चुप्पी साध लिए हैं। मौका तेजस्वी यादव के हाथ लगा और चुनाव प्रचार के दौरान वे एनडीए में परिवारवाद को गिना रहे हैं। हालांकि, बिहार में यही परिवारवाद जीत की गारंटी दे रहा है। इसलिए एनडीए से थोक में ऐसे कैंडिडेट्स उतरे हैं, जिनके माता-पिता या रिश्तेदार सांसद-विधायक, मंत्री और केंद्रीय मंत्री तक रहे हैं। कोई जीजा है, तो कोई बेटा और बेटी है। एनडीए के 40 में से 14 प्रत्याशी ऐसे ही हैं। इनमें अकेले लोजपा (आर) के 4 प्रत्याशी हैं।

बिहार में 24 जनवरी को नीतीश कुमार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी पर परिवारवाद को लेकर हमला किया था। इस पर लालू परिवार की ओर से रिएक्शन आया और सरकार से आरजेडी बेदखल हो गई। नीतीश और लालू-तेजस्वी के बीच कुछ दिनों से नाराजगी चल रही थी, लेकिन तत्कालिक कारण परिवारवाद का सवाल ही था। लालू और मोदी के बीच शुरू हुई परिवारवाद की बयानबाजी और सीट शेयरिंग के बाद बिहार में एनडीए के एजेंडे से परिवारवाद का मुद्दा क्यों दूर हो गया और बात जंगलराज, भ्रष्टाचार, राममंदिर और नौकरी पर होने लगी है। गौरतलब है कि बिहार की राजनीति लालू यादव के एक बयान से गरमाई। लालू यादव ने कहा था कि क्या है मोदी...मोदी कोई चीज है। आज कल परिवारवाद पर हमला कर रहा है। तुम बताओ ना, तुमको संतान क्यों नहीं हुआ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता है कि **परिवारवाद है,** परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम हिंदू भी नहीं है। तुम्हारी माता जी का जब देहावसान हो गया तो हर हिंदू अपनी मां के शोक में बाल-दाढ़ी बनवाता है। क्यों नहीं बनवाया, बताओ? क्यों नहीं बनवाया? देशभर में नफरत फैला रहे हो।

इस पर मोदी ने तेलंगाना में कहा, जब इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। कोटि-कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, 140 करोड़ देशवासी ही मेरा परिवार हैं। बेतिया में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आजादी के बाद से बिहार में पलायन बड़ी समस्या रही है। जंगलराज आया तो यह समस्या और बढ़ गई। यहां के नौजवान दूसरे राज्यों और शहरों में रोजी-रोटी के लिए जाते रहे और यहां एक ही परिवार फलता-फूलता रहा। नौकरी के बदले जमीनों पर कब्जा किया गया। यह परिवार बिहार के लोगों का सबसे बड़ा गुनहगार है। आचार संहिता लागू होने के बाद बिहार में मोदी की दो सभाएं हो चुकी हैं। एक माह पहले तक बिहार में मोदी का पूरा अटैक परिवारवाद पर होता था, लेकिन अब वह इस पर कोई बयान नहीं दे रहे हैं। जमुई में 4 अप्रैल को आयोजित बिहार की पहली चुनावी सभा में मोदी ने अपराध और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। मोदी की गारंटी के साथ जंगलराज की भी बात की, लेकिन जैसे वह जंगलराज के पीछे लालू परिवार को लेकर हमलावर होते थे, वैसा बयान नहीं दिया। हालांकि, दिल्ली में चुनावी सभा के दौरान उन्होंने परिवारवाद का मुद्दा उठाया, लेकिन बिहार में इससे परहेज करते दिखे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट सीनियर जर्नलिस्ट लव कुमार मिश्रा बिहार में एनडीए के टिकट बंटवारे में परिवारवाद को मोदी की खामोशी की बड़ी वजह बता रहे हैं। कई लोकसभा सीट पर फैमिली पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। जमुई में प्रधानमंत्री की पहली चुनावी सभा के बाद तेजस्वी यादव ने एनडीए को परिवारवाद के मुद्दे पर घेर लिया। तेजस्वी यादव ने 10 सवाल किए। फेसबुक पर लाइव आकर तेजस्वी ने कहा, चुनाव मोदी पर नहीं, बल्कि मुद्दों पर होना चाहिए। उन्होंने कहा, प्रथम चरण की 4 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार विशुद्ध रूप से 100 प्रतिशत परिवारवाद वाले हैं।

तेजस्वी यादव ने मोदी को एनडीए के कैंडिडेट्स से ही परिवारवाद के मुद्दे पर काउंटर किया है। उन्होंने एनडीए के 14 उम्मीदवारों से मोदी को परिवारवाद में घेरने की कोशिश की है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट बताते हैं, दांव उल्टा न पड़े, इसलिए एनडीए का कोई नेता अब परिवारवाद का मुद्दा नहीं उठा रहा है। बेतिया में 6 मार्च को मोदी के कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मोदी के मंच पर परिवारवाद का मुद्दा उठाया था। लेकिन, चुनाव आते ही वह भी परिवारवाद के मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। मोदी की दो-दो चुनावी सभाएं हुईं। इस बड़ी चुनावी सभा में मोदी से पहले भी कई नेताओं ने संबोधन किया, लेकिन किसी ने भी परिवारवाद का नाम तक नहीं लिया। सीनियर जर्नलिस्ट लव कुमार मिश्रा कहते हैं कि एनडीए में ही कई ऐसे कैंडिडेटस हैं, जो पॉलिटिकल फैमिली से हैं।

● **विनोद बक्सरी**

बिहार में वोटर्स के टॉप इश्यूज

रोजगार और विकासः प्राइवेट नौकरी करने वाली सिमिरन कहती हैं- परिवारवाद को लालू ही नहीं मोदी भी बढ़ावा दे रहे हैं। राजनीतिक परिस्थिति के हिसाब से ही पार्टियां इसे बढ़ावा देती हैं। यह ऐसे ही चला आ रहा है, राजनीति में जैसी परिस्थिति होती है, इसे लोग अपना लेते हैं। चुनाव में ऐसे मुद्दों को दरकिनार कर रोजगार और विकास के मुद्दे की बात करनी चाहिए। पार्टियों की आपसी लड़ाई में मुद्दे डायवर्ट हो जाते हैं, विकास साइड हो जाता है। चुनाव के मुद्दों पर महिलाओं की भी बात होनी चाहिए। टीचर कन्हैया कहते हैं कि लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सेहत का मुद्दा जरूरी है। जब सेहत ही नहीं रहेगी तो रोजगार और कानून व्यवस्था का क्या मतलब है। आज भी बिहार में प्राथमिक उपचार सही नहीं है। हमारा अधिकार है, लेकिन आज भी प्राथमिक उपचार के लिए व्यवस्था सही नहीं है। बड़े सरकारी अस्पतालों में बेड नहीं मिलता है। प्राइवेट के लिए पैसा नहीं होता, लेकिन कभी भी यह मुद्दा नहीं बनता है। टीचर शमसुद्दीन कहते हैं कि राजनीतिक मुद्दे भटकाव वाले हैं। जब चुनाव आता है, मुद्दे तैयार हो जाते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की व्यवस्था के साथ बिहार की कानून व्यवस्था किसी से छिपी नहीं है। इसके बाद भी लोग ऐसे-ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं, जिससे आम लोगों का कोई सरोकार नहीं है। हम यही चाहते हैं, ऐसे लोगों को वोट किया जाए, जो परिवारवाद और विवादों वाले मुद्दों से दूर लोगों को बांटने के बजाय जोड़कर तरक्की की राह दिखाने वाले हों। वोटर ब्रजेंद्र नाथ सिंह कहते हैं कि राम मंदिर का मुद्दा भी जायज नहीं है। इसे भुनाया जा रहा है। राम सबके हैं, राम के नाम पर बांटना गलत है।

अरब देशों की बढ़ती नजदीकियां

अमेरिका और भारत के अरब देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने के मद्देनजर कई देशों को मिलाकर कई बिलियन अमेरिकी डॉलर से इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बनाया जा रहा है। यह कॉरिडोर बनने से भारत और अरब देशों के लिए ग्लोबल मार्केट के नए दरवाजे खुलेंगे। इसका एक सुखद पहलू यह भी है कि इससे भारत सहित कई देशों के करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर एक वैश्विक समूह है और इसके समझौते भारत से जुड़े हैं या भारत के हितों को प्रभावित कर रहे हैं। इसका पूर्वी कॉरिडोर भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ेगा। वहीं उत्तरी कॉरिडोर खाड़ी को यूरोप से जोड़ेगा।

आईएमईसी कॉरिडोर में एक बिजली केबल, एक हाइड्रोजन पाइपलाइन और एक हाई-स्पीड डेटा केबल भी शामिल होगी। जबकि रेलवे लाइन फुजैरा बंदरगाह (यूएई) को सऊदी अरब (घुवाईफात और हराद) और जॉर्डन के माध्यम से हाइफा बंदरगाह (इजराइल) से जोड़ेगा और यूरोप में ग्रीस में पीरियस बंदरगाह, दक्षिण इटली में मेसिना और फ्रांस में मार्सिले से जुड़ेगा।

प्रारंभिक अनुमानों से पता चलता है कि इनमें से प्रत्येक आईएमईसी मार्ग को विकसित करने में 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच लागत आ सकती है। इस प्रस्तावित आईएमईसी में रेलमार्ग, शिप-टू-रेल नेटवर्क और सड़क परिवहन मार्ग शामिल हैं, जो दो कॉरिडोर तक फैले होंगे, अर्थात् पूर्वी कॉरिडोर-भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ता है और उत्तरी कॉरिडोर-खाड़ी को यूरोप से जोड़ता है। आईएमईसी कॉरिडोर में एक बिजली केबल, एक हाइड्रोजन पाइपलाइन और एक हाई-स्पीड डेटा केबल भी शामिल होगी। यह परियोजना महाद्वीपों और सभ्यताओं के बीच संबंधों और एकीकरण को मजबूत कर सकती है। यह क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच अमेरिका को प्रभाव बनाए रखने और पारंपरिक भागीदारों को आश्वस्त करने का एक रणनीतिक अवसर देता है। इस एग्रीमेंट पर भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूरोपीय संघ, इटली, फ्रांस और जर्मनी ने हस्ताक्षर किए हैं। भारत में मुंद्रा (गुजरात), कांडला (गुजरात), और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (नवी मुंबई) इसके बंदरगाह हैं। वहीं मध्य पूर्व में संयुक्त अरब अमीरात में फुजैरा, जेबेल अली और अबू धाबी के साथ-साथ सऊदी अरब में दम्मम और रास अल खैर बंदरगाह हैं।

रेलवे लाइन फुजैरा बंदरगाह (यूएई) को सऊदी अरब (घुवाईफात-हराद) और जॉर्डन के माध्यम से हाइफा बंदरगाह (इजराइल) से जोड़ेगी। इसी तरह इजराइल में हाइफा बंदरगाह, यूरोप में ग्रीस में पीरियस बंदरगाह, दक्षिण इटली में मेसिना और फ्रांस में मार्सिले शामिल हैं। इसका उद्देश्य भारत, मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ने वाला एक व्यापक परिवहन नेटवर्क बनाना है, जिसमें रेल, सड़क और समुद्री मार्ग शामिल हैं। इसका मकसद परिवहन दक्षता बढ़ाना, लागत कम करना, आर्थिक एकता बढ़ाना, रोजगार पैदा करना और ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन कम करना है। इससे व्यापार और कनेक्टिविटी को सुविधाजनक बनाकर एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व के एकीकरण में बदलाव आने की उम्मीद है। यह मौजूदा समुद्री और सड़क परिवहन के पूरक के लिए एक विश्वसनीय और लागत प्रभावी सीमा-पार जहाज-से-रेल पारगमन नेटवर्क देगा।

आईएमईसी में अंतर-क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की क्षमता है और यह अरब प्रायद्वीप में राजनीतिक तनाव कम करने में मदद कर सकता है। यह क्षेत्र में शांति के लिए बुनियादी ढांचा बनने की संभावना रखता है। ट्रांस-अफ्रीकी कॉरिडोर विकसित करने की अमेरिका और यूरोपीय संघ की योजना के अनुरूप इस कॉरिडोर गलियारे के मॉडल को अफ्रीका तक बढ़ाया जा सकता है। यह अफ्रीका के साथ अपना जुड़ाव मजबूत करने और इसके बुनियादी ढांचे के विकास में योगदान करने के भारत के इरादे दर्शाता है। आईएमईसी प्रमुख क्षेत्रों के साथ अपनी व्यापार कनेक्टिविटी बढ़ाकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत के लिए एक परिवर्तनकारी अवसर देता है। यह मार्ग पारगमन का समय काफी कम कर सकता है, जिससे स्वेज नहर समुद्री मार्ग की तुलना में यूरोप के साथ व्यापार 40 प्रतिशत तेज हो जाएगी। यह कॉरिडोर माल की निर्बाध आवाजाही के लिए एक कुशल परिवहन नेटवर्क तैयार करेगा।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

पारदर्शी बुनियादी ढांचा साझेदारी

भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर, जी20 शिखर सम्मेलन, ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी), बैल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई), यूरेशियन क्षेत्र, एसईजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र है। यह भारत के महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में आयोजित जी20 शिखर सम्मेलन में भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (आईएमईसी) परियोजना पर हस्ताक्षर किए गए, जो भारत के लिए महत्वपूर्ण भूराजनीतिक और आर्थिक निहितार्थ रखता है। यह परियोजना वैश्विक अवसंरचना और निवेश साझेदारी (पीजीआईआई) का हिस्सा है। पीजीआईआई कई और मध्यम आय वाले देशों के विशाल बुनियादी ढांचे की जरूरतें पूरी करने के लिए एक मूल्य-संचालित, उच्च-प्रभाव और पारदर्शी बुनियादी ढांचा साझेदारी है। इसका भूराजनीतिक और आर्थिक निहितार्थ चीन के बीआरआई को विफल करना है। आईएमईसी को यूरेशियाई क्षेत्र में चीन के बैल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) के संभावित प्रतिकार के रूप में देखा जाता है। यह खासकर अमेरिका के साथ ऐतिहासिक रूप से मजबूत संबंधों वाले क्षेत्रों में चीन के बढ़ते आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव को संतुलित करने का काम कर सकता है। आईएमईसी का एक मकसद पश्चिम के साथ भारत की जमीनी कनेक्टिविटी पर अपने वीटो को तोड़ते हुए पाकिस्तान को दरकिनार करना है, जो अतीत में लगातार एक बाधा बना हुआ था। इसका एक मकसद अरब प्रायद्वीप के साथ रणनीतिक जुड़ाव रखना भी है। यह कॉरिडोर स्थायी कनेक्टिविटी स्थापित कर और क्षेत्र के देशों के साथ राजनीतिक और रणनीतिक संबंधों को बढ़ाकर अरब प्रायद्वीप के साथ भारत की रणनीतिक भागीदारी को गहरा करता है।

कब रुकेगा गाजा पट्टी में युद्ध...

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गाजा पट्टी में युद्ध और मानवीय पीड़ा पर विराम लगाने के लिए, तत्काल युद्धविराम लागू किए जाने और तमाम बंधकों की तत्काल व बिना शर्त रिहाई की मांग करने वाला एक नया प्रस्ताव पारित कर दिया है। यह प्रस्ताव, 11 मार्च को शुरू हुए रमजान के महीने की करुण एवं मानवीय पुकार है। साथ ही, इजराइल पर हमलों के दौरान बंधक बनाए लोगों में से शेष 130 लोगों को रिहा किए जाने की मांग है।

हमास एवं इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को विराम देकर, शांति का उजाला करने, अभय का वातावरण, शुभ की कामना और मंगल का फैलाव करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को दृढ़ता से शांति प्रयास एवं युद्ध विराम को लागू करना ही चाहिए। मनुष्य के भयभीत मन को युद्ध की विभीषिका से मुक्ति देनी चाहिए। इन दोनों देशों को अभय बनकर विश्व को निर्भय बनाना चाहिए। निश्चय ही यह किसी एक देश या दूसरे देश की जीत नहीं बल्कि समूची मानव-जाति की जीत होगी। यह समय की नजाकत को देखते हुए जरूरी है और इस जरूरत को महसूस करते हुए दोनों देशों को अपनी-अपनी सेनाएं हटाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। गाजा में विशाल स्तर पर उपजी आवश्यकताओं और जरूरतमंद **आबादी तक मानवीय** सहायता पहुंचाएं जाने की भी जरूरत है, क्योंकि वहां के लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं।

छह महीने से जारी इस भयंकर जंग के दौरान यह पहला मौका है, जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने युद्धविराम का प्रस्ताव पारित किया है। यह इसलिए संभव हुआ कि अमेरिका ने इसे वीटो करने से परहेज किया। निश्चित रूप से सुरक्षा परिषद का यह प्रस्ताव विश्व जनमत से उपजे दबाव की अभिव्यक्ति है। बड़े शक्तिसंपन्न राष्ट्रों को इस युद्ध विराम देने के प्रस्ताव को बल देना चाहिए और इसे लागू करने के प्रयास करने चाहिए। पिछले 7 अक्टूबर को हमास की ओर से किए गए आतंकी हमले के खिलाफ जब इजराइल ने कार्रवाई की बात कही तो अमेरिका और भारत समेत तमाम देशों की सहानुभूति उसके साथ थी। लेकिन इजराइल ने जिस तरह से गाजा में हवाई हमले शुरू किए और वहां से आम लोगों के हताहत होने की खबरें आने लगीं, उसके बाद यह आवाज तेज होती गई कि इजराइल को अपने अभियान का स्वरूप बदलना चाहिए। अब तक गाजा में करीब 32 हजार लोगों के मारे जाने की खबरें हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। भारत हमेशा युद्ध-विरोधी रहा है, युद्ध-विराम की उसकी कोशिशें निरंतर चलती रही हैं। किसी भी देश में यह भ्रम पैदा नहीं होना चाहिए कि भारत हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा है। भारत ने उचित ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को यह भी बता दिया है कि वह सभी संबंधित पक्षों के संपर्क में है और उनसे बातचीत की मेज पर लौटने का आग्रह कर रहा है। निस्संदेह, भारत को मानवता के पक्ष में शांति, युद्ध-विराम और राहत के प्रयासों में जुटे रहना चाहिए। भारत के ऐसे प्रयासों का ही परिणाम है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने युद्धविराम का ऐसा प्रस्ताव पारित किया है।

गाजा पट्टी में हिंसक टकराव पर विराम लगाने के लिए सुरक्षा परिषद की कई बैठकें हो चुकी हैं, मगर फिलहाल यह संभव नहीं हो पाया है। नवंबर 2023 में एक सप्ताह के लिए लड़ाई रोकी गई थी और गाजा से बंधकों और इजराइल से फलस्तीनी बंदियों की अदला-बदली हुई थी। मगर, इसके बाद लड़ाई फिर भड़क उठी और इसमें तेजी आई है। गाजा में मृतक संख्या और भूख व कुपोषण से प्रभावित फलस्तीनियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। इसके मद्देनजर लड़ाई को जल्द से जल्द रोके जाने और मानवीय पीड़ा पर मरहम लगाने की मांग भी प्रबल हो रही है। दुनिया के किसी भी हिस्से में मानवता का इस तरह पीड़ित एवं मर्माहत होना शर्म की बात है। इस शर्म को लगातार ढ़ोते रहना शक्तिसंपन्न एवं निर्णायक राष्ट्रों के लिए शर्मनाक ही है। अब एक सार्थक पहल हुई है तो उसका स्वागत होना ही चाहिए।

समूची दुनिया और उसके देश हमास एवं इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को विराम देने की अपेक्षा महसूस करते हुए लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात थी कि अलग-अलग देशों में हो रहे प्रदर्शनों में व्यक्त होती जनभावना एवं मानवता की पुकार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के रूप में बाहर नहीं आ पा रही थी। खुद अमेरिका इससे पहले गाजा युद्ध विराम से जुड़े तीन प्रस्ताव को वीटो कर चुका था। गत दिनों मतदान से अलग रहते हुए भी उसने इस प्रस्ताव को पारित होने दिया, जो उसके अब तक के रुख में अहम बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिकी रुख में आए इस कथित बदलाव पर इजराइल ने भले ही तीखी प्रतिक्रिया जताई। इजराइली पीएम नेतन्याहू ने इसी सप्ताह बातचीत के लिए अमेरिका जाने वाले एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के कार्यक्रम को रद्द करने की घोषणा कर दी। हालांकि अमेरिका ने अपने रुख में बदलाव से इनकार किया है, लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि अमेरिका का ताजा कदम इस बात का स्पष्ट संकेत है कि इजराइल उसके समर्थन को तय मानकर न चले।

● **कुमार विनोद**

युद्ध के परिणाम होंगे घातक

बात भले ही अभी गाजा में युद्ध-विराम की हो, लेकिन युद्ध कहीं भी हो, विनाश का ही कारण है, विकास को अवरुद्ध करने एवं शांति एवं अमन को बाधित करने का जरिया है। युद्ध तो लंबे समय से रूस एवं यूक्रेन के बीच भी चल रहा है। हमास और इजराइल भी लंबे समय से युद्धरत है। इस तरह युद्धरत बने रहना खुद में एक असाधारण और अति-संवेदनशील मामला है, जो समूची दुनिया को विनाश एवं विध्वंस की ओर धकेलने जैसा है। ऐसे युद्ध का होना विजेता एवं विजित दोनों ही राष्ट्रों को सदियों तक पीछे धकेल देगा, इससे भौतिक हानि के अतिरिक्त मानवता के अपाहिज और विकलांग होने का भी बड़ा कारण बनेगा। विश्वशांति एवं मानवता की रक्षा का ध्यान रखते हुए युद्धरत देशों को युद्ध विराम के लिए अग्रसर होना चाहिए। जब तक युद्धरत देशों के अहंकार का विसर्जन नहीं होता तब तक युद्ध की संभावनाएं मैदानों में, समुद्रों में, आकाश में तैरती रहेगी, इसलिए आवश्यकता इस बात की भी है कि जंग अब विश्व में नहीं, हथियारों में लगे। मंगल कामना है कि अब मनुष्य यंत्र के बल पर नहीं, भावना, विकास और प्रेम के बल पर जीए और जीते।

महिलाओं में रील बनाने की सनक

रोहतक के भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) द्वारा किए गए हालिया सर्वे के अनुसार युवा हर रोज औसतन 7 घंटे सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। सोशल मीडिया पर पुरुषों की तुलना में महिलाएं करीब 20 मिनट ज्यादा सक्रिय रहती हैं। वर्चुअल स्क्रीन पर पल-पल सामने आती रील्स और अजब-गजब वीडियोज पर नजर डालें तो यह बात सही प्रतीत होती है। आभासी संसार में महिलाएं काफी समय बिता रही हैं। साथ ही देशभर के हर हिस्से में सोशल मीडिया के प्रति महिलाओं की इस बढ़ती सनक के गंभीर परिणाम सामने आने लगे हैं। इस जुनून के चलते ना केवल महिलाओं और बेटियों के लिए असुरक्षा के हालात पैदा हुए हैं बल्कि आपराधिक घटनाएं भी हो रही हैं। ठहराव और मन की दृढ़ता के मान पाने वाली भारतीय स्त्रियों द्वारा रील्स और वीडियोज में साझा की जा रही सामग्री वाकई हैरान करने वाली है। मजाक के नाम पर हद दर्जे की असभ्य बातें और नृत्य के नाम पर अश्लील हावभाव स्वयं स्त्रियां ही परोस रही हैं। कहीं ग्रामीण महिलाएं कुएं में झूलती चारपाई पर बैठी रील्स बनाकर जीवन को खतरे में डाल रही हैं, तो कहीं भैंस पर चढ़कर नृत्य कर रही हैं।

परिस्थितियां ऐसी हैं कि छोटे-छोटे गांवों-कस्बों में बसी घर-परिवार संभाल रही महिलाएं भी इस पागलपन का शिकार हो चली हैं। बहुत से घरों में उनके अपने भी इस जुनून से परेशान हैं। रोक-टोक करने पर आपराधिक घटनाएं तक हो रही हैं। हाल ही में कर्नाटक के चामराज नगर में एक युवक ने पत्नी के रील्स बनाने के जुनून से व्यथित होकर आत्महत्या कर ली। युवक को हर समय पत्नी का सोशल मीडिया में व्यस्त रहना परेशान करने लगा था। वहीं पत्नी इंस्टाग्राम और टिकटोक पर रील्स को लेकर बेहद जुनूनी हो गई थी। बिहार के बेगूसराय में हुई एक अन्य घटना में पति ने पत्नी को रील्स बनाने से रोका तो पत्नी और ससुराल के कुछ लोगों ने उसकी हत्या कर दी। इस मामले की जांच में खुलासा हुआ है कि रील्स बनाने की वजह से पत्नी की दोस्ती अन्य लड़कों से हो गई थी। अनजान लोगों से हुई मित्रता को लेकर पति महिला को बार-बार समझाता था। इसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद समझाने के लिए पति अपने ससुराल गया था, जहां महिला ने अपने अन्य साथियों की मदद से उसे मौत के घाट उतार दिया। विचारणीय है कि रील्स बनाने की दीवानगी के कारण उजड़ी इस गृहस्थी के बिखराव का दंश झेलने वालों में दोनों का एक 5 साल का बेटा भी है।

सोशल मीडिया पर चल रहे रील्स के इस दौर में नाबालिग बच्चियां, युवतियां और घर-परिवार बसाकर मातृत्व की जिम्मेदारी निभा रहीं महिलाएं तक अपनी सुधबुध खो रही हैं। ना केवल अनजान चेहरों से मित्रता कर असुरक्षा को न्योता दे रही हैं बल्कि रील्स बनाने के फेर में गलत कदम भी उठाने से भी नहीं चूक रहीं हैं। दुखद यह है कि अंततः खुद महिलाएं भी इस बिखराव का दंश झेलती हैं, पर समय रहते दी गई अपनों की समझाइश का कोई असर नहीं दिखता। बिहार के ही बेगूसराय में बीते साल हुई एक घटना में तीन नाबालिग छात्राओं ने परिजनों की डांट से नाराज होकर घर छोड़ दिया था। अभिभावकों द्वारा अपहरण की शिकायत दर्ज करवाने के बाद सकुशल बरामद होने पर छात्राओं ने बताया कि परिजन उन्हें रील्स बनाने से मना करते थे। इस रोक-टोक से नाराज होकर तीनों एक साथ घर से भाग गईं।

साल 2022 में उप्र के फर्रूखाबाद में एक युवती ने रील्स बनाने से रोकने पर अपने भाइयों पर हमला कर दिया था। युवती इस रोक-टोक से इतनी नाराज थी कि उसने अपने छोटे भाइयों को गला घोंटकर मारने की कोशिश की। शिकायत के बाद युवती को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। वहीं हाल ही में राजस्थान के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की रील बनाने की आदत से नाराज होकर उसकी हत्या कर दी। वर्चुअल संसार में छा जाने के नाम पर महिलाओं की बदलती सोच का यह पक्ष वाकई समझ से परे है। आभासी प्रशंसा पाने की ललक में पारिवारिक संबंध तक दरक रहे हैं। रील बनाने का दबाव डालने के कारण मप्र में तो एक पति ने स्वयं को न केवल पत्नी से बचाने की गुहार लगाई, बल्कि इस आधार पर कुटुंब न्यायालय में तलाक की अर्जी तक डाली थी। पति का कहना था कि पत्नी के रील्स वीडियो बनाने की सनक ने उसका जीवन नर्क बना दिया है।

राज्य में एक साल के भीतर पत्नियों द्वारा इंटरनेट मीडिया पर हद से ज्यादा सक्रिय होने की वजह से बिगड़ते संबंधों से जुड़े करीब 70 प्रतिशत मामले कुटुंब न्यायालय तक पहुंचे थे। देश के सभी हिस्सों में ऐसे वाकये हो रहे हैं जहां रील्स के चक्कर में उलझी महिलाओं को लेकर परिजनों के शिकायती स्वर सुनने को मिल रहे हैं। रील्स बनाने के लिए गैर जरूरी चीजों की खरीदारी से खर्चे बढ़ रहे हैं। घर-परिवार की संभाल में कोताही हो रही है। खुद का जीवन जोखिम में डाला जा रहा है। तकनीकी के जाल में उलझती मानसिकता के कारण हो रहे ऐसे मामले यकीनन भयभीत करने वाले हैं।

● **ज्योत्सना**

रीयल जिंदगी से दूर करती रील्स

इतना ही नहीं बढ़ती आभासी सक्रियता और वास्तविक जीवन से बढ़ती दूरी अनगिनत स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ा रही हैं। रीयल जिंदगी से दूर करती रील्स हों या इंस्टाग्राम, वॉट्सएप और फेसबुक के अपडेट्स और लाइक-कमेंट देखने की व्यग्रता, मानसिक सेहत पर सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। बावजूद इसके वर्चुअल छवि में गुम महिलाएं अपनी सूझ-बूझ खो रही हैं। पैसा कमाने की जुगत में रील्स को हिट बनाने और लाखों व्यूज पाने के लिए हर हद पार कर रही हैं। बिहार में ही मिट्टू मानसी का जोड़ा इन दिनों काफी चर्चित है जिसने प्रेम विवाह किया था। जब लव मैरिज किया था तब उनका इरादा था कि रील बनाकर पैसे कमाएंगे और जिंदगी चलाएंगे। वो ऐसा करने भी लगे लेकिन जब कमाई इतनी नहीं हुई कि घर चल सके तो अब दोनों के बीच तकरार शुरू हो गई है। तकनीक के जाल में आधी आबादी का जमीनी सोच और व्यावहारिक समझ से दूर होना समग्र समाज के लिए पीड़ादायी है। जिन आधुनिक सुविधाओं को जागरूकता और सजगता के लिए इस्तेमाल कर महिलाएं सशक्त बन सकती हैं वे सुविधाएं ही उन्हें असुरक्षा और अपराध की राह पर ले जा रही हैं।

भगवद गीता को हिंदू धर्म ग्रंथों में एक मुख्य स्थान दिया गया है। गीता का उपदेश भगवान श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुन को युद्ध की भूमि में दिया गया सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। इस ज्ञान के द्वारा ही अर्जुन को सही और गलत के बीच का अंतर पता चल सका और इसी के आधार पर अर्जुन ने युद्ध में विजय हासिल की।

आखिर पाप क्यों करता है मनुष्य

महाभारत के युद्ध में भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन के सारथी बने और अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। यह उपदेश जितना उस दौरान प्रासंगिक था उतना आज भी है। क्योंकि आज के समय में मनुष्य का जीवन ही एक युद्ध बनता जा रहा है। ऐसे में आप यहां जान सकते हैं कि किन परिस्थियों के कारण मनुष्य पाप में भागीदार बनता है और इससे किस प्रकार बचा जा सकता है।

केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः।
अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः॥

इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्रीकृष्ण से यह प्रश्न पूछता है, कि मनुष्य न चाहते हुए भी बुरे कर्म क्यों करता है। जिसके उत्तर में भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं, कि मनुष्य की वासना और निहित स्वार्थ के चलते ही वह पाप करने के लिए विवश हो जाता है। पाप करने की सबसे बड़ी वजह मनुष्य की काम भावना (किसी चीज को पाने की इच्छा) है क्योंकि काम वासना से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से भ्रम पैदा होता है, जिससे सबसे पहले बुद्धि नष्ट हो जाती है और यही मनुष्य के विनाश का कारण बनती है।

मनुष्य के सबसे बड़े दुश्मन- भगवान श्रीकृष्ण आगे कहते हैं कि जिस प्रकार धुआं अग्नि को ढक देता है, ठीक उसी तरह काम, मोह और वासना भी मनुष्य के ज्ञान को ढक देती है। इन्हीं कारणों के चलते मनुष्य पाप करने के लिए विवश हो जाता है। भगवान श्रीकृष्ण पाप से बचने के कुछ उपाय भी गीता में बताते हैं। जिसके अनुसार मनुष्य को आसक्ति या विरक्ति के प्रभाव के अधीन नहीं होना चाहिए। जब किसी व्यक्ति में आसक्ति और विरक्ति का अभाव होता है तो उस जीवन को ही उत्तम माना जाता है।

परमात्मा शिव कहते हैं पाप और पुण्य का सारा खेल भारतवासियों के ऊपर बना हुआ है, भारत वाले पाप करते हैं तो सब करने लग जाते हैं। भारतवासी ही धनी थे फिर एकदम निधन के बन जाते हैं। जो हमें लगता है पाप व्यक्ति की चॉइस है वो जानबूझकर पाप करता है, हमने जो ओब्सर्व किया हमारे पास सदा चॉइस रहती है अच्छा करने की लेकिन हम गलत मार्ग चुनते हैं और फंस जाते हैं। पापी व्यक्ति सफलता के लिए जल्दी प्राप्ति खुशी नाम, मान, शान जो कि अल्पकाल की प्राप्ति होती है, उनको पाने के लिए ही करता है। जैसे धन कमाना सबको पता है पेट दो रोटी ही मांगता है फिर भी व्यक्ति पाप कर लेता है, क्योंकि कहीं न कहीं हमें ये पता रहता है कि पाप करने से हमे ज्यादा धन थोड़े समय के लिए प्राप्त हो जाएगा, और जल्दी धनी बन जाएंगे लेकिन वो धन दुख अशांति घर में कलह-क्लेश ले आता है।

व्यक्ति कभी ये नहीं कह सकता कि पाप हमसे किसी ने करवाया, अगर ऐसा होता तो सबके कर्म समान होते। कोई राजा कोई प्रजा नहीं होता, बल्कि हम गलत काम करना चुनते हैं और कोई अच्छा मार्ग चुनता है, और हमें केवल सही कर्मों से ही बड़ी सफलता मिलती है। पापों से थोड़ी देर हमें सुख सफलता प्राप्त हो सकती है, लेकिन इसका रिटर्न दुख, पीड़ा, तकलीफें दर्द ही हाथ आते हैं और हम उन्हें भोगते रहते है, ये सब हमारी कहानी है।

पाप करने के पीछे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी न उठाने की हेबिट हो सकती है, जो हम रिस्पॉन्सिबल ग्रहों को, परिस्थिति को, लोगों को दुनिया में जो हो रहा है उन्हें ठहरा देते हैं, जिस कारण हम अच्छा मार्ग त्याग कर गलत मार्ग अपना लेते हैं या हो सकता हमारे साथ गलत व्यवहार हुआ है, गलत किया लोगों ने तो हम गलत मार्ग पर चल पड़ते हैं, इससे हम जैसा करेंगे वैसा ही पाएंगे। ये हमारी चॉइस होगी, अगर हम गलत मार्ग पर जाते, इसके लिए वो व्यक्ति कोई भी चीज रिस्पॉन्सिबल नहीं, किसी ने गलत किया वो हमारे पूर्व जन्म में उनके साथ किए गलत का रिटर्न मिलता है। कोई बिना वजह किसी से गलत करता नहीं अगर हम पाप चुनते हैं फिर हम इसके लिए किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। पाप करना सदा हमारी चॉइस रहती है।

इसके अलावा हमारे पास ये भी चॉइस है कि गलत करने के बाद भी हम सही रिस्पॉन्स दें, हमारे पास ये भी पावर है, अगर निगेटिव पावर हो सकती है तो सकारात्मक शक्ति भी हम में ही है। इस पावर को जगाने के लिए हम राजयोग मेडीटीशन की जो प्रेक्टिस करते हैं इसकी प्रेक्टिस कर आप अपने जीवन में शांति-प्रेम को स्थान दें। मन की कड़वाहट को धीरे-धीरे निकाल सकते हैं। ये प्रेक्टिस काफी लाभदायक है, जब दिल बहुत चोटिल है, जख्मी है, ये न केवल हमें हील करती है बल्कि अन्य के लिए भी काफी लाभदायक सिद्ध होती है। क्योंकि चोट हमारे गलत कर्मों के कारण लगी और वो लगाई हमने और उसे हील भी हमें ही करना होता है।

सुख दुख में साथ नहीं देते ऐसे लोग- भगवद गीता में भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं कि जो लोग खुद में रहना पसंद करते हैं और अपने मित्रों या परिवारजनों से दूरी बनाकर रखते हैं, उन्हें जीवन में कई असफलताओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि यह लोग सुख-दुख में किसी का साथ नहीं देते।

छोड़ दें ऐसा व्यवहार- अगर आप संकोची हैं, तो इस स्थिति में भी सफलता मिलना मुश्किल है। वहीं, अगर कोई व्यक्ति अहंकार से भरा है तो उसे भी हार का सामना करना पड़ता है। क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज है, जो बांटने से बढ़ती है और अहंकार व्यक्ति के कर्मों का नाश कर देता है।

सफल नहीं होने देती ये आदतें- यदि कोई व्यक्ति किसी चीज को पाने के लिए जल्दबाजी दिखाता है, तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं होता। इसलिए विवेक रखना बहुत जरूरी है। वहीं, अगर किसी व्यक्ति में तुलना करने की आदत पाई जाती है या फिर ईर्ष्या का भाव होता है, तो इस स्थिति में भी सफलता हाथ लगना मुश्किल है।

आत्म मूल्यांकन जरूरी- जो व्यक्ति स्वयं का मूल्यांकन करना नहीं जानता वह व्यक्ति भी कभी सफलता हासिल नहीं कर पाता। क्योंकि अपनी ताकत और कमजोरियों को जाने बिना कोई भी युद्ध नहीं जीता जा सकता, चाहे वह जीवन रूपी युद्ध क्यों न हो।

● **ओम**

सेल्फी जोन

रेणु और उसकी सहेलियां उस विवाह समारोह में सजी-धजी हुईं सेल्फी जोन ढूंढ रही थीं। विवाह की रिसेप्शन पार्टी शानदार थी। हर तरफ बिजलियों की जगमगाहट थी पर सेल्फी जोन कहीं नजर नहीं आ रहा था।

आजकल तो हर छोटे-मोटे समारोह में सेल्फी जोन बनाया जाता है पर यहां क्यों नहीं है? रेणु अपनी सहेलियों से कह रही थी। तभी मेहमानों का स्वागत करते हुए रेणु को दूल्हे के पिता दिखे। रेणू ने उनसे कहा-अंकलजी नमस्ते! विवाह का रिसेप्शन तो शानदार है पर आपने यहां पर सेल्फी जोन नहीं बनवाया है? आजकल तो सबसे अधिक इसका चलन है। सेल्फी जोन के बिना यहां की सजावट अधूरी लग रही है।

दूल्हे के पिता ने कहा- हां बेटे, सेल्फी जोन का चलन तो आजकल हर जगह है। देखो न, आज आदमी कितना बेचारा और अकेला है कि वो खुद ही अपनी फोटो खींचता है। यह मुझे अच्छा नहीं लगता और एक बहुत दुख भरी बात यह है कि इसी सेल्फी के चक्कर में मेरा बड़ा बेटा नदी में गिरकर बह गया और हम सबसे हमेशा के लिए बिछुड़ गया। यह कहते हुए उनकी आंखें छलछला आईं। रेणु और उसकी सहेलियां यह सुनकर सकते में आ गईं।

- डॉ. शैल चन्द्रा

सूखे पत्ते

मिस्टर शर्मा और कमल कांत बचपन के साथी तो थे ही आज भी सुख-दुख के साथी हैं। दोनों नियम से सूरज का उगना और अस्त होना देखना नहीं भूलते। दिन ढ़लते ही दोनों टहलने निकल पड़ते और पेड़ के नीचे पड़ी बेंच पर बैठ सूर्य के बदलते रंगों को निहारते और अपनी आप बीती सुनाते। चिड़ियों की चहकन के साथ पुनः सूर्य की नवल रश्मियों से मिलने निकल पड़ते। नदी के तीरे सूर्य दर्शन कर थोड़ी देर आकर पार्क में अपनी पुरानी जगह बैठते। कुछ देर योगा फिर बनावटी हंसी का अभ्यास।

आज कितनी सुंदर हवा चल रही है कमलकांत!

हां शर्मा! आज टहलने में आनंद आ गया।

दोनों बैठ के बतियाते हैं। हवा के झोंकों के साथ सूखे खनकते पत्ते टूटकर इधर-उधर बिखर रहे थे।

यार शर्मा! इन सूखे बिखरे पत्तों को देख रहे हो इनमें मुझे अपनी तुम्हारी परछाई दिख रही है।

हां कमलकांत! बच्चे बड़े हो गए और हम सूखे पत्तों जैसे सांसे कब रुक जाएं पता नहीं। कभी-कभी मेरा पोता बहुत याद आता है। बहुत खेलता था पर...

छोड़ो चलो चलते है ये सूखे पत्ते कभी पुनः शाख पर नहीं लग सकते। पतझाड़ आकर इन्हें गिरा ही देता है।

उदास मन से दोनों आश्रम के बगीचे में ही बैठ जाते हैं। दिन कब चढ़ आता है पता ही नहीं चलता।

नीम के सूखे पत्तों को इकट्ठा कर दोनों ने उन्हें ढेर में परिवर्तित कर दिया था। तभी आश्रम का चपरासी आकर कहता है शर्मा जी कोई आपसे मिलने आया है। शर्मा जी मुड़ते हुए मुझ से मिलने। अपूर्व मुस्करा रहा था। शर्मा जी चश्मा ठीक करते हैं, तभी कमलकांत बोल पड़ते हैं देख शर्मा नीम की शाखों पर पुनः कोपलें उग रही हैं पर कुछ अभी भी पल्लव रहित हैं।

- मंजूषा श्रीवास्तव

तुम चाहो तो आ जाना

नई सुबह का नया द्वार
मैं खोल रहा हूं;
तुम चाहों तो आ जाना
मैं बोल रहा हूं!
मैंने तो हर बार दर्द को
सुख-सा ही आभार दिया है।
मौसम ने बदली हो करवट,
हर क्षण को ही प्यार किया है।
घोर निराशा को पूरे मन से छोल रहा हूं;
तुम चाहों तो आ जाना
मैं बोल रहा हूं!
छूकर ही पहचान हुई है
प्राणवान होती है वायु।
प्रश्न अलग है, ज्ञान लिया क्या
ज्ञानवान होती है आयु।
जीवित मृत्युबोध के पल को,
मैं तोल रहा हूं;
तुम चाहों तो आ जाना,
मैं बोल रहा हूं।
अवरोधों से डरने वाले,
डरकर ही हरदम मिटते हैं।
आशा के प्रतिबिंब आंख में,
रखकर जो चलते, टिकते हैं।
जीना चाहो जी लेना,
मैं प्यार-प्यार में घोल रहा हूं;
तुम चाहों तो आ जाना,
मैं बोल रहा हूं!

- रामस्वरूप मूंदड़ा

कप्तानी के लिए परिपक्व नहीं पांड्या!

हमारे देश में क्रिकेट एक ऐसा खेल बन गया है जिसे खेल प्रेमी सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। इनका यह प्रेम तब और बढ़ गया जब वर्ष 2007 में इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की शुरुआत हुई। यह लीग खेलों में सबसे महंगी लीग के साथ ही अब दुनिया की सबसे लोकप्रिय लीग भी बन गई है। इस लीग से कई ऐसे खिलाड़ी उभरकर आए हैं जो अब देश का नाम रोशन कर रहे हैं। यहां तक कि मुंबई इंडियंस के बतौर कप्तान रहते रोहित शर्मा ने पांच बार आईपीएल खिताब जिताया। उनके इस प्रदर्शन के चलते उन्हें राष्ट्रीय टीम की कमान मिली है। लेकिन इस सीजन 2024 में मुंबई इंडियंस ने जबसे उन्हें कप्तानी से हटाकर हार्दिक पांड्या को कमान सौंपी है तब से मुंबई टीम में मनमुटाव देखने को मिल रहा है जो अब अपने चरम पर पहुंचता नजर आ रहा है।

आलम यह है कि गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच बीते दिनों अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए हाई वोल्टेज मैच में गुजरात से मुंबई को मिली हार और कुछ अजीबोगरीब निर्णयों को लेकर मुंबई इंडियंस के लिए पहली बार कप्तानी कर रहे हार्दिक पांड्या की जमकर आलोचना हो रही है। मैच के दौरान पूरे स्टेडियम में दर्शक उनकी मजाक बनाते नजर आए। वहीं मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी के दौरान हार्दिक ने रोहित शर्मा के साथ एक ऐसी हरकत भी की, जिससे फैंस का गुस्सा और बढ़ गया। हार्दिक पांड्या पूर्व कप्तान रोहित शर्मा की फील्डिंग पोजीशन चेंज करते हुए नजर आए। उन्होंने 30 यार्ड सर्कल के दायरे में खड़े रोहित शर्मा को बाउंड्री पर भेज दिया। इस पूरी घटना की वीडियो काफी वायरल हो रही है।

दरअसल गुजरात टाइटंस की पारी का आखिरी ओवर मुंबई इंडियंस की तरफ से जेराल्ड कोएट्जी डाल रहे थे। ओवर के दौरान हार्दिक गेंदबाज के साथ मिलकर फील्ड सजा रहे थे। ऐसे में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें हार्दिक 30 यार्ड सर्कल में खड़े रोहित शर्मा को बाउंड्री पर जाकर फील्डिंग करने के लिए कहते हैं। अक्सर सर्कल में फील्डिंग करने वाले रोहित लॉन्ग ऑन की तरफ चले जाते हैं। बाउंड्री पर जाने के बाद भी पांड्या रोहित को उनकी जगह से इधर से उधर करते हैं। रोहित के साथ इस तरह का बर्ताव फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आया जिसकी वजह से पांड्या सोशल मीडिया पर भी जमकर ट्रोल हो रहे हैं। यही नहीं मैच के दौरान हार्दिक ने कुछ अजीबोगरीब फैसले भी लिए। मैच खत्म होने के बाद हार्दिक पांड्या पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को गले लगाने जाते हैं, जो कि उन्हें काफी भारी पड़ा। हिटमैन ने ग्राउंड में ही पांड्या की क्लास लगा डाली।

इस वीडियो में हार्दिक पीछे से आकर रोहित शर्मा को गले लगा लेते हैं। जैसे ही वह देखते हैं कि पांड्या हैं, वह वैसे ही उन्हें डांटना शुरू कर देते हैं। हालांकि जिस तरीके से रोहित शर्मा उन्हें डांटते हैं, ऐसा लग रहा है वह मैच में की गई हार्दिक द्वारा गलतियों बतौर कप्तान पर उन्हें समझा रहे हैं। जब रोहित उन्हें गुस्सा करना शुरू करते हैं तो ठीक पीछे खड़े राशिद खान और आकाश अंबानी भी देखने लगते हैं। इस घटनाक्रम को लेकर खेल विशेषज्ञों और पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों का कहना है कि कप्तान नया हो और जीतते-जीतते हार जाए तो टीम के लिए मुश्किल वक्त होता है। लेकिन मैदान पर पूर्व कप्तान और गेंदबाज के साथ किसी चर्चा को छोड़कर भाग जाना, पूर्व कप्तान और अनुभवी खिलाड़ियों से बातचीत न करना दिखलाता है वे अभी कप्तानी के लिए परिपक्व नहीं हैं।

किसी का भी व्यक्तित्व तभी पता चलता है जब उसके पास पावर आती है। अब हार्दिक पांड्या को ही ले लीजिए। टीम में जसप्रीत बुमराह, ल्यूक वुड, शम्स मुलानी और गेराल्ड कोएट्जी जैसे तेज गेंदबाज होने के बावजूद हार्दिक पांड्या ने कप्तान के तौर पर पहले मैच में गेंदबाजी की शुरुआत की। यह बात न केवल दर्शकों, बल्कि क्रिकेट के दिग्गजों को भी कुछ खास पसंद नहीं आई। हालांकि, टीम के बैटिंग कोच पोलार्ड यह कहते नजर आए कि यह टीम का प्लान था। हो भी सकता है कि ऐसा हो, लेकिन कप्तान के तौर पर खुद हार्दिक पंड्या अपनी जगह किसी पेस स्पेशलिस्ट से गेंदबाजी करवाते तो शायद टीम को जरूर फायदा होता। उम्मीद है गुजरात और मुंबई के बीच खेले गए मुकाबले में जो कुछ हुआ उसे भूलकर हार्दिक अगले मुकाबलों में अपनी पावर का इस्तेमाल सही से करेंगे।

हार्दिक ने शुरुआती स्पेल में दो ओवर किए और 20 रन खर्च किए। इन दो ओवरों ने विपक्षी टीम के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका दिया। बाद में हार्दिक फिर एक ओवर करने आए तो 10 रन खर्च किए। इस तरह से उनकी बॉलिंग का एनालिसिस 3 ओवर 30 रन देकर कोई विकेट रहा। रोचक बात यह है कि टीम यह मैच जीतते-जीतते सिर्फ 6 रनों के अंतर से हार गई। यहां वह समझ सकते थे कि यह कोई गांव या गली क्रिकेट नहीं है, जहां कप्तान ही पहला ओवर करेगा और खिलाड़ियों को धकियाते फिरेगा। इस मैच में हार्दिक पंड्या की कप्तानी की धार तो कुछ खास नजर नहीं आई, लेकिन मैदान पर एक फ्रस्टेटेड कप्तान जरूर नजर आया। स्टेडियम में हजारों फैंस की हूटिंग के बीच हार्दिक हंसता हुआ चेहरा लेकर जरूर घूम रहे थे, लेकिन उनके फैसलों और उसे लागू करने के तरीकों से पता चल रहा था कि वह बेहद परेशान हैं। उन्होंने रोहित शर्मा को 20वें ओवर में फील्डिंग के लिए बाउंड्री रेखा पर भेजा और 2 से 3 मिनट तक यह तय करते दिखे कि रोहित को फील्डिंग कहां से खड़ा होकर करना है। या यूं कह लें कि वह यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि वह कप्तान हैं और वह जहां चाहे अपनी मर्जी से रोहित शर्मा को फील्डिंग के लिए भेज सकते हैं।

● आशीष नेमा

हार्दिक पहले भी कर चुके हैं दुर्व्यवहार

ऐसा नहीं है कि हार्दिक पांड्या मैदान पर इस तरह का व्यवहार पहली बार करते नजर आए। इससे पहले पिछले सीजन में ही मोहम्मद शमी को बुरा भला कहते दिखे थे, जिस पर शमी ने खुलेआम अपना गुस्सा जाहिर किया था। इंटरनेशनल मैच में कप्तानी के दौरान 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज में, मैं कप्तान, मेरा फैसला, मैं ही सब कुछ जैसा बयान देते नजर आए थे। मैदान पर साथी खिलाड़ियों को गाली देना हार्दिक के लिए आम है। 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ टी-20 मैच में भी एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह गाली देते नजर आए। 2023 में विराट कोहली को किसी बात पर इग्नोर करते दिखे तो आयरलैंड के खिलाफ डीआरएस गंवाने के बाद हर्षल पटेल और ईशान किशन पर गुस्से में कुछ कहते नजर आए थे। हार्दिक के भाई क्रुणाल पांड्या स्पिन स्पेशलिस्ट हैं और इसके बावजूद वह दो बार आईपीएल में टीम की कप्तानी करने के दौरान पहला ओवर कर चुके हैं। 2023 में वह केएल राहुल की गैरमौजूदगी में लखनऊ सुपरजायंट्स की कप्तानी कर रहे थे और दोनों ही मौके पर मुंबई इंडियंस के खिलाफ गेंदबाजी की शुरुआत की थी।

अक्षय कुमार ने दिया था शक्ति कपूर को धक्का

सालों पुरानी दिवाली पार्टी में हुआ था झगड़ा, कई सालों तक बंद रही बातचीत

साल 2002 में अक्षय कुमार और शक्ति कपूर का एक दिवाली पार्टी में जोरदार झगड़ा हुआ था। पार्टी के बाद दोनों ने झगड़े की अलग-अलग वजह बताई थीं। शक्ति ने आरोप लगाया था कि अक्षय ने कार्ड गेम में चीटिंग की और रोकने पर धक्का दे दिया। वहीं अक्षय ने कहा कि शक्ति दिवाली पार्टी में अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे।

अक्षय *ने झगड़े के बाद साल 2003 में एक इंटरव्यू में इस झगड़े पर बात करते हुए कहा था, शक्ति उस पार्टी में बिन बुलाए आ गए थे। वो पार्टी में लगातार अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। उनकी भाषा काफी शर्मनाक थी क्योंकि उस पार्टी में कई औरतें भी थीं। वो इतने नशे में थे कि उनसे ठीक तरह खड़े होते तक नहीं बन रहा था। मैंने बस उन्हें हल्का सा धक्का दिया था, जिससे वो जमीन पर गिर गए थे। अगर वो ऐसा कहते हैं कि उसने मुझे कार्ड गेम में चीटिंग करते देखा था, तो वो झूठ बोल रहे हैं। वो इतने नशे में थे कि उन्हें खुद नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं। मुझे उन्हें टच करने पर भी अफसोस है। मैं खुद से पूछता हूं कि मैंने एक शराबी पर अपनी एनर्जी बर्बाद क्यों की। वहीं दूसरी तरफ शक्ति कपूर ने अक्षय से हटकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था, अक्की (अक्षय) गेम में चीटिंग कर रहा था। मैंने उससे कहा कि वो चीटिंग न करे, तो उसने मुझे धक्का दे दिया और मैं गिर गया। उसने मुझे थप्पड़ नहीं मारा था। मैंने तुरंत पार्टी छोड़ दी थी। मैं नहीं चाहता था कि झगड़ा बढ़े। अक्की आज भी मेरा दोस्त है, हालांकि हमने कभी उस झगड़े के बाद बात नहीं की। साल 2002 में हुए झगड़े के बाद अक्षय कुमार और शक्ति कपूर फिल्म भागम भाम और दे दना दन में साथ नजर आए हैं।*

तलाक के बाद नए पार्टनर की तलाश में थी सुचित्रा कृष्णमूर्ति, पार्टी में दोस्त को लुभाने के लिए कर दी ऐसी हरकत...

फिल्म *कभी हां कभी ना की रिलीज के बाद सुर्खियों में छाईं एक्ट्रेस सुचित्रा कृष्णमूर्ति के लिए तलाक के बाद जीवन थोड़ा टफ हो गया था। एक इंटरव्यू में अभिनेत्री ने अपने एक्स हस्बैंड और फिल्म निर्माता शेखर कपूर के साथ मधुर संबंध बनाए रखते हुए अपनी बेटी को प्राथमिकता देने के बारे में बात की। इसके साथ एक्ट्रेस बताया कि नए पार्टनर की तलाश में उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी थी, जिसका एहसास उनके दोस्त ने उन्हें कराया। एक इंटरव्यू में सुचित्रा ने उनके जीवन के इस चरण के बारे में बात की। एक्ट्रेस ने बताया कि जब मैंने तलाक लिया था तब मैं बहुत भ्रम से गुजरी थी। हर कोई मुझसे कह रहा था कि मुझे एक साथी ढूंढना होगा और मैं अकेले सब मैनेज नहीं कर पाऊंगी। मुझे विश्वास होने लगा कि शायद मुझे किसी को ढूंढना होगा। तो जो भी मिले, पार्टी में, यहां वहां... फिर यह मजाक बन गया। वहां नागेश कुकुनूर और केन घोष थे। सुचित्रा ने आगे कहा, केन घोष से मैं एक पार्टी में मिली थी और मैं बोल्ड और उत्तेजक बनने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने कहा, सुचि, तुम क्या कर रही हो? आपके जैसे चेहरा छुपाए नहीं छुप सकता। सुचित्रा ने कहा, जब कोई मां बन जाता है, तो उसके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं।*

बिग बी सेट पर रोज गीता का पाठ करते थे, एक्टर रंजीत बोले- वो हर दिन की दिनचर्या में अपने मां-बाबू जी को चिट्ठी में लिखते थे

अमिताभ *बच्चन ने फिल्म सात हिंदुस्तानी के बाद रेशमा और शेरा में काम किया। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान एक्टर रंजीत ने इस फिल्म से जुड़ा एक किस्सा शेयर करते हुए कहा- फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन रोज सुबह गीता का पाठ करते थे और शाम को मां-बाबू जी को चिट्ठी लिखा करते थे।*

फिल्म रेशमा और शेरा की शूटिंग राजस्थान में हुई थी। फिल्म के सभी कलाकारों के रहने की व्यवस्था टेंट में थी। रंजीत कहते हैं, मेरे बगल वाले टेंट में अमिताभ बच्चन ठहरे हुए थे। मैं रोज सुबह उनको कुछ पढ़ते और रात में कुछ लिखते देखता था। एक दिन मैंने उनसे पूछ लिया कि रोज सुबह-सुबह क्या पढ़ते रहते हो और रात को लिखते क्या रहते हो? रंजीत ने कहा- अमिताभ बच्चन ने बताया कि सुबह गीता का पाठ करता हूं। और, रात को हर दिन की दिनचर्या मां-बाबू जी को चिट्ठी लिखकर भेजता हूं। मुझे अमिताभ की यह बात बहुत अच्छी लगी। अमिताभ रेशमा और शेरा से पहले सात हिंदुस्तानी में काम कर चुके थे। तो वो एक फिल्म मुझसे सीनियर थे। इस फिल्म के बाद हमने कई फिल्में साथ कीं, अब भी अमिताभ बच्चन से मुलाकात होती रहती है और हम खूब मजाक मस्ती करते रहते हैं।

जूते को कभी आम मत समझिए। जवानी के दिनों में अनेक दिल फेंक आशिक मिजाज जब-जब अपनी प्रेमिकाओं की गली में गए। तब तक अपनी जुल्फों के साथ-साथ अपने जूते भी चमका कर जाते थे। लेकिन उल्टा तब पड़ जाता था जब अपनी प्रेमिका के भाइयों के हाथ जूतारस का रसास्वादन किया। तब-तब उन्हें प्रेम रोग से मोक्ष प्राप्त हुआ। और कितनों ने कई-कई बार खाने के बाद मोक्ष प्राप्त किया। जूता एक उसके रंग अनेक होते हैं।

इसका जूता उसके सिर

जूते पैरों की आन, बान, शान होते हैं। जूते पहले हमारे देश में आम आदमी को बनाने का अधिकार था। तो ज्यादातर उसे ही खाने का भी अधिकार था। कोई भी उसे जूता खिला देता था। स्कूल में गुरुजी, घर में बाबूजी, तो कभी बड़े भाई बहन और कभी-कभी तो अड़ोसी-पड़ोसी तक खिला देते थे। पहले लोग बुरा भी नहीं मानते थे। क्या होता था कि बनाने वाले भी अपने, खिलाने वाले भी अपने, खाने वाले भी अपने होते थे। तो बुरा क्या मानना था। और आजकल लोग बुरा इसलिए मानते हैं कि आजकल लोग अपनों को अपना नहीं मानते हैं। जूते आम-खास सब पहनते थे। जूते बनाने का ज्यादातर काम अब कुछ ब्रांडेड कंपनियों के पास है। तो जूते खाने का काम भी ज्यादातर ब्रांडेड लोगों के पास ही है। आम आदमी के पास खाने के लिए खाना नहीं है तो वह जूते क्या खाएगा। गरीब न ब्रांड वाले जूता पहनता है ना खाता है। और ना जूते वाली क्लास से उसको कोई सरोकार है। गरीब का कोई ब्रांड नहीं होता है।

जूता बहुत काम की चीज होती है। साथ ही यह दो मुही तलवार भी होता है। पैर में पड़ा हो तो इज्जत बढ़ा देता है। सर पर पड़ा तो बेहद निर्दयता से इज्जत उतार भी लेता है। हां इसके लिए ब्रांड से कोई लेना-देना नहीं है। बिना ब्रांड के भी जूते वही काम करते हैं जो ब्रांडेड जूते करते हैं। जूते का सीधा संबंध हमारे सम्मान से कुछ यूं जुड़ा होता है। यदि घर में पड़ता है तो हमें सुधार देता है और यदि बीच बाजार पड़ता है तो मतलब हमारे सारे ग्रह नक्षत्र को बिगाड़ देता है। जूते को कभी आम मत समझिए। जवानी के दिनों में अनेक दिल फेक आशिक मिजाज जब-जब अपनी प्रेमिकाओं की गली में गए। तब तक अपनी जुल्फों के साथ-साथ अपने जूते भी चमका कर जाते थे। लेकिन उल्टा तब पड़ जाता था जब अपनी प्रेमिका के भाइयों के हाथ जूतारस का रसास्वादन किया। तब-तब उन्हें प्रेम रोग से मोक्ष प्राप्त हुआ। और कितनों ने कई-कई बार खाने के बाद मोक्ष प्राप्त किया। जूता एक उसके रंग अनेक होते हैं।

कई बार हमें बचपन में पढ़ते हुए पाठ याद नहीं हो पाता था। लाख रट्टा मारे लाख सिर पीटे किंतु याद होने का नाम ही नहीं लेता था। सारे तंत्र-मंत्र करके देख लेते थे। किताब में मोर पंख रखते। पुस्तक देवी को सौ-सौ प्रणाम करते। लेकिन पाठ याद नहीं हो पाता था। लेकिन ज्यों ही बाबूजी का जूता सिर पर तबला बजाता। आश्चर्यजनक रूप से कुछ ही मिनटों में सबकुछ याद हो जाता था। अत: यह सब भूला बिसरा याद कराने में सक्षम था। तो इस प्रकार जूता अव्यवस्थित याद्दाश्त को एक व्यवस्थात्मक प्रणाली में लाने का भी सहायक होता है। इतिहास गवाह है जब-जब बच्चों ने अपने बाप के हाथ में जूता देखा उनका सारा भूत-प्रेत भाग जाता था। और उनकी सारी बुरी बीमारी दूर हो जाती थी। अत: जूते को बाल सुधार यंत्र भी कहा जा सकता है। जिसका न कल कोई तोड़ था ना आज कोई तोड़ है।

कुछ लोग अपनी गरीबी के चलते जूते पहनने के बिल्कुल काबिल नहीं होते हैं। हां कभी कुछ लोग जूते खाने लायक जरूर होते हैं। अत: जब आप उन्हें जूते खिलाएं तो आप अपने पैरों के जूते को तैयार रखिए। दौड़ कर भागने के लिए। जितना तेज आपके जूते चलेंगे उतना आपके बचने की संभावना ज्यादा रहेगी। वरना थप्पड़ खाने से ज्यादा लोग जूता खाना बुरा मान जाते हैं। जबकि दोनों खाना अच्छा नहीं माना जाता है। इसमें भी लोग भेदभाव कर जाते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप किसी से पूछकर देख लीजिए कि महोदय आप जूते खाएंगे या थप्पड़ खाएंगे। सामने से आपको सामान्य जवाब तो मिलेगा ही नहीं, दोनों के उत्तर में महोदय को लाल-पीला होना है।

जूते में इतनी बुराई होने के बावजूद शादी ब्याह में दूल्हे की सालिया ना दूल्हे का बटुआ चुराती है ना घड़ी चुराती है ना चश्मा चुराती हैं। वह चुराती है तो दूल्हे के जूते चुराती हैं। और जूते के ओरिजिनल दाम से चौगुना दाम लेने के बाद ही देती हैं। इसी प्रकार हमारे देश के मंदिरों के बाहर बाकायदा जूता चोर बैठे रहते हैं। इधर आप दर्शन पूजन में लीन हुए उधर आपके जूते किसी औरों के पैरों में पड़कर चल दिए। उसके बाद आपके पास झक मारने के सिवा कुछ नहीं बचता। जूते में लाख बुराई सही लेकिन फिर भी जूते की पूछ कम नहीं है। अत: आप कोशिश कीजिए कि आपके जूते सही सलामत आपके पैरों में पड़े रहे ना कि सिर पर पड़े। अगर आपके जूते को सर की लत लग ही गई है तो कम से कम वह सर दूसरे का हो।

● **रेखा शाह आरबी**

PRISM®
CEMENT

प्रिज़्म® चैम्पियन प्लस

ज़िम्मेदारी मज़बूत और टिकाऊ निर्माण की.

- ज्यादा मज़बूती
- ज्यादा महीन कण
- ज्यादा वर्कबिलिटी
- बेहतरीन निर्माण कार्य
- इको–फ्रेन्डली
- कन्सिसटेंट क्वालिटी
- ज्यादा प्रारम्भिक ताक़त
- ज्यादा बचत

PRISM®
चैम्पियन
प्लस
सीमेंट

दूर की सोच®

Toll free: 1800-572-1444 Email: cement.customerservice@prismjohnson.in

ANU SALES CORPORATION

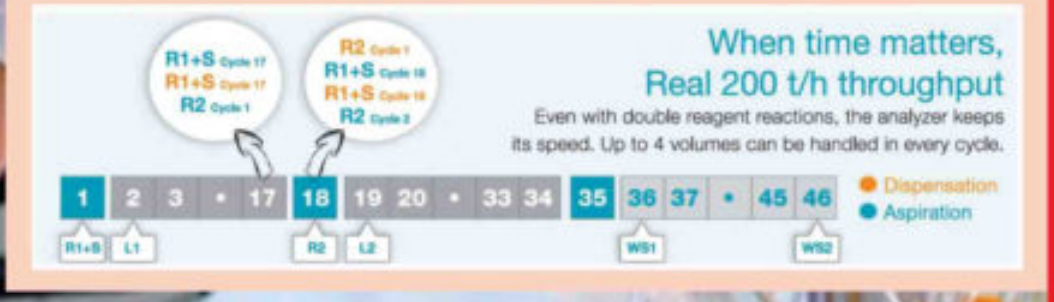

We Deal in Pathology & Medical Equipment

BA200

BioSystems

The Highest Flexibility

Address : M-179, Gautam Nagar,
Near Chetak Bridge, Bhopal-462023

9329556524, 9329556530 Email : ascbhopal@gmail.com